R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 22 । अंक : 02
16 से 31 अक्टूबर 2023
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

5 State ELECTION 2023

5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का शंखनाद

तय होंगे कई नेताओं के राजनीतिक भविष्य!

मोदी बनाम मुद्दों का पहला ट्रायल रन हैं ये चुनाव

मप्र, छग और राजस्थान के दिग्गजों की साख दांव पर

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

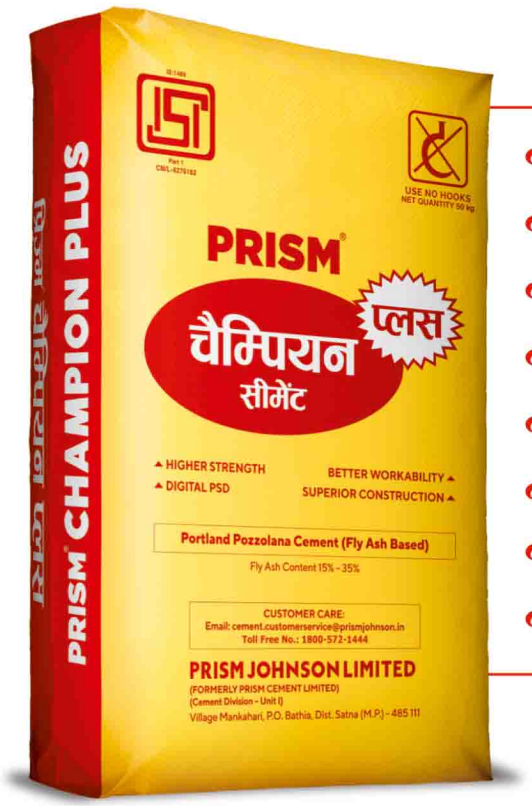

- ज्यादा मज़बूती
- ज्यादा महीन कण
- ज्यादा वर्कबिलिटी
- बेहतरीन निर्माण कार्य
- इको–फ्रेन्डली
- कन्सिसटेंट क्वालिटी
- ज्यादा प्रारम्भिक ताक़त
- ज्यादा बचत

PRISM®
चैम्पियन प्लस
सीमेंट

दूर की सोच®

Toll free: 1800-572-1444 Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

इस अंक में

प्रशासनिक

9 | बिरादरी का विद्रोह

मप्र के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस 30 नवंबर को रिटायर होंगे। यह दिन मप्र के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए खुशी का ऐतिहासिक दिन होगा। क्योंकि उनका कहना है कि इस दिन उन्हें लालफीताशाही से निजात...

राजपथ

10-11 | कांटेदार मुकाबला

विधानसभा की 230 सीटों वाले मप्र में 2023 के चुनाव की तैयारियां आखिरी दौर में हैं। पिछले एक साल से भाजपा के बड़े-बड़े रणनीतिकार प्रदेश में सक्रिय रहे, लेकिन अंतिम क्षणों में पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री...

राजकाज

13 | ओबीसी जिसके साथ उसकी...

इतिहास स्वयं को दोहराता है किंतु इस बार उल्टा हो रहा है। जातियों की जकड़न से हिंदू समाज को निकालने की मंशा से हिंदुत्ववादी राजनीति की शुरुआत हुई और अब हिंदुत्ववादी राजनीति के उभार को समाप्त कर हिंदू समाज को पुनः जातियों के फेर में...

योजना

15 | जंगल की गोद भरेगा बांध...

भूजल स्तर के मामले में रेड जोन में शामिल धार जिले को सूखे से बचाने के लिए हर स्तर पर जल संरचनाओं के विस्तार का काम चल रहा है। शासन से लेकर प्रशासन तक अलग-अलग माध्यम से जल संरचनाओं की मंजूरी और निर्माण पर फोकस किया जा रहा है। इसका नतीजा है कि पहाड़ों...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की बिसात बिछ गई है, जिसके नतीजे निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करेंगे, लेकिन इन चुनावों को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल नहीं कहा जा सकता है। निश्चित रूप से, इन चुनावों के नतीजे कई नेताओं के राजनीतिक भविष्य की पटकथा लिखेंगे। इन चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, छग के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री...

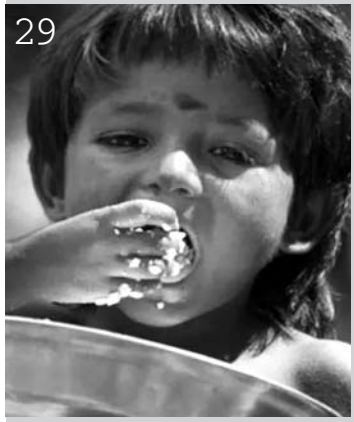

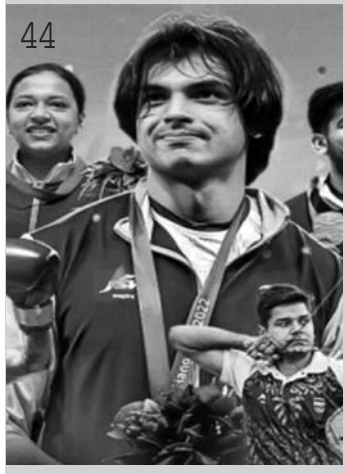

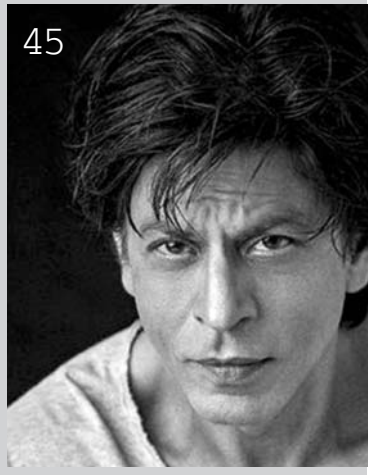

राजनीति

30-31 | आरक्षण बनाम...

कर्नाटक के उलट भाजपा ने मप्र में अब तक 4 सूचियां जारी कर 136 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कई नाम सामने आ चुके हैं। उधर, कांग्रेस ने अभी पहली सूची जारी कर 144 लोगों को टिकट दिया है। दोनों पार्टियों में बगावत के सुर उठ रहे हैं, इससे अन्य...

महाराष्ट्र

35 | क्या फिर बनेंगे नए समीकरण ?

ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में फिर हलचल देखने को मिल सकती है क्योंकि इन दिनों अजित पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच दूरियां साफ दिख रही हैं। बता दें कि बीते दिन अजित पवार कैबिनेट मीटिंग में भी शामिल नहीं हुए थे। अजित पवार की...

बिहार

38 | मझधार में नीतीश कुमार

एक तरफ तो नीतीश कुमार के करीबी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी का कहना है कि इंडी एलायंस में नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला हो गया है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर बिहार में फिर से...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

बर्बरता का जवाब क्रूरता से...यह कैसा न्याय?

आचार्य चाणक्य ने लिखा है-

क्रूर वो नहीं जिसने नहीं देखा,
क्रूर वो है जिसने स्पष्ट देखा फिर भी
आंखें मलते हुए आगे बढ़ गया!!

ऐसा ही कुछ इन दिनों इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग में हो रहा है। हमास ने इजराइल पर अचानक हमला बोलकर महिलाओं और बच्चों के साथ जिस तरह की बर्बरता की है, उससे बूतों की भी रूह कांप गई है। लेकिन अब हमास की बर्बरता के जवाब में इजरायल जो क्रूरता कर रहा है, वह भी इंसानियत को तार-तार कर रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि इनके बीच चल रही जंग को रोकने का प्रयास करने की बजाय पूरा विश्व दो खेमों में बंट गया है। आश्चर्य तो इस बात पर है कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ मूक दर्शक बना हुआ है। रूस और यूक्रेन की जंग के बाद अब हमास और इजरायल की जंग को रोकने में भी संयुक्त राष्ट्र महासंघ विफल हो रहा है। इस बीच दोनों तरफ से मानवता को बम-बारूद और हथियारों के दम पर रौंदा जा रहा है। एक तरफ इजरायल ने गाजा पर हमले तेज कर दिए हैं। हमास की क्रूरता की तस्वीरें भी मानवता को झकझोरने वाली हैं। हमास की ऐसी ही एक बर्बर हरकत ने अमानवीयता की हदें पार कर दी हैं। हमास के आतंकियों ने एक गर्भवती इजरायली महिला को भी नहीं बख्शा। पहले उसे चाकू मारा, जिससे उसकी मौत हो गई और फिर पेट से निकले अजन्मे बच्चे तक को गोद डाला। इस तरह के मंजर कई जगह देखने को मिले। हमास और इजरायल की जंग के दौरान वहां के आम लोगों को जो दर्द नसीब हुआ है, उसकी तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया हिल रही है। इस जंग की वजह से गम, गुस्सा और बेबसी हर तरफ दिख रही है। इजरायल के सैकड़ों लोग बंधक बने हुए हैं तो उधर, गाजा में मां-बाप अपने मासूम बच्चों को दफन करके रो रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक आतंकी संगठन और एक मुल्क लड़ रहा है, लेकिन इसका खामियाजा दोनों तरफ से ही आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। हमास और इजरायल की जंग ने कई परिवारों को ऐसा दर्द दिया है, जो जिंदगी भर दूर नहीं होगा। 7 अक्टूबर को अचानक इजरायल की सरहदों में घुसे सैकड़ों हमास लड़ाकों ने ऐसी दरिंदगी दिखाई कि सारी दुनिया कांप गई। उस दिन सिबुत्ज में सैकड़ों लोग जश्न में डूबे थे और तभी हमास के लड़ाकों ने हमला कर दिया था। इसके बाद जो हुआ वो सबकी आंखों के सामने है। इजरायल से दर्जनों लोगों को अगवा कर लिया गया। एक लड़की को हमास के आतंकी अगवा करके गाजा ले गए। उसके साथी को भी आतंकियों ने अगवा कर लिया। इसी तरह एक परिवार को हमास के आतंकियों ने बंधक बना रखा है। मासूम बच्चे फर्श पर डरे सहमे बैठे हैं। उनके मां-बाप लाचार हैं। अपने बच्चों के लिए कुछ ना कर पाने की बेबसी उनके चेहरे पर दिख रही है। परिवार की एक बेटी को हमास के आतंकी अगवा करके ले गए है। इजरायल में छोटे-छोटे बच्चे हमास के आतंकियों से रहम की भीख मांग रहे हैं। बच्चे गुजारिश कर रहे हैं कि जिन बच्चों को अगवा किया गया है उनको छोड़ दिया जाए। इन बच्चों के चेहरों पर डर है। आंखों में बेबसी है। मासूमों की अपील का हमास पर कितना असर पड़ेगा, कोई नहीं जानता। इसके बाद जब इजरायल ने गाजा पर हमला किया तो ऐसे ही मंजर वहां भी देखने को मिले। इजराइली हमले में पूरा गाजा शहर खंडहर हो गया है।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 22, अंक 2, पृष्ठ-48, 16 से 31 अक्टूबर, 2023

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी
फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर,
फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर,
भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर,
मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास
मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

किसान हो रहे परेशान

किसान हमें अन्न देते हैं। लेकिन उन्हें अपनी फसलों का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। सरकार को किसानों की परेशानी को समझना चाहिए और उनके लिए अन्य योजनाएं चलानी चाहिए। जिससे उन्हें अधिक परेशान नहीं होना पड़े। और उन्हें उचित मूल्य मिल सके।

● **राहुल पाल,** इंदौर (म.प्र.)

युवाओं के लिए क्या?

मप्र में विधानसभा के चुनाव जल्द ही होने वाले हैं, ऐसे में राजनीतिक दलों के पास युवाओं के लिए क्या खास है। प्रदेश में युवा वोटर्स की तादाद अधिक है, इसलिए उन्हें युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या खास है, इस पर विचार करना चाहिए। युवाओं को भी क्या सही है, इस पर ध्यान देना होगा।

● **सुमित शर्मा,** भोपाल (म.प्र.)

धर्म के नाम पर न हो चुनाव

सभी राजनीतिक दलों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि धर्म के नाम पर चुनाव न लड़ें। इससे कट्टरता पैदा होती है। चुनाव लड़ने के कई मुद्दे हैं, जैसे-शिक्षा, रोजगार, गरीबी आदि। इन सभी मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। न कि धर्म के नाम पर राजनीति हो।

● **अनुपमा सिंह,** राजगढ़ (म.प्र.)

महिलाओं को मिला सम्मान

नारी शक्ति वंदन विधेयक सर्वसम्मति से दोनों सदनों में पारित किया गया है। आधी आबादी को न्याय मिला है। बिल पास होने के बाद महिलाओं के मन में जो उम्मीद बंधी है, खुश होने का मौका तो है ही। निश्चित तौर पर महिला नेताओं को आरक्षण के तहत प्रतिनिधित्व मिलने के लिए अभी काफी इंतजार करना होगा, लेकिन ये भी तो है कि अभी का इंतजार अनंतकाल के लिए नहीं है।

● **रेखा चतुर्वेदी,** बीहोर (म.प्र.)

कौन होगा विपक्ष का चेहरा?

2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों ने नया गठबंधन तो बना लिया है, लेकिन इतने दलों में पीएम पद के लिए चेहरा कौन होगा? आम चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक राय बनाकर अपना पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए, जिसके चेहरे पर वे चुनाव लड़ेंगे। इससे सत्तापक्ष को भी जवाब मिलेगा। यदि चुनाव के बाद चेहरे पर फैसला करेंगे, तो मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। सभी दलों के कार्यकर्ता अपने मुखिया को पीएम पद का दावेदार बनाना चाहते हैं, इससे बाद में बगावत की स्थिति पैदा हो सकती है।

● **जुबैद खान,** नई दिल्ली

मिल रहा नल से जल

प्रदेश सहित देशभर में पथरीली जमीनों पर पीने के पानी के लिए पाइप लाइन बिछाने, गांव-गांव पानी की टंकियों को बनाने, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने, जल स्त्रोतों को बढ़ाने और घर-घर तक नल से जल पहुंचाने का काम तेजी से किया गया। भारत सरकार की हर घर जल योजना को सरकार ने राज्य के उन जिलों में प्राथमिकता से लागू किया जहां पानी की समस्या कई सालों से चिंता का कारण थी।

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

चुनाव लड़ सकते हैं अभिषेक सिंह

भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देने के बाद अब उप्र कॉडर के आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह क्या करेंगे इस पर सभी की नजर है। चर्चा है कि अभिषेक सिंह लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर जौनपुर से किस्मत आजमा सकते हैं। उनकी पत्नी दुर्गा शक्ति नागपाल वर्तमान में बांदा की जिलाधिकारी हैं। लंबे समय से बिना पद के रह रहे अभिषेक ने गत सप्ताह आईएएस से इस्तीफा दे दिया है। अभिषेक ने पिछले दिनों जौनपुर में गणेशोत्सव का आयोजन भी किया था, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी शामिल हुए थे। अब अभिषेक के इस्तीफे के बाद चर्चा का बाजार गर्म हो गया है कि अभिषेक राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव में भाजपा को जौनपुर से मजबूत प्रत्याशी की तलाश भी है। अभिषेक सिंह के पिता कृपाशंकर सिंह भी सेवानिवृत्त आईपीएस हैं। उनका जौनपुर में खासा वर्चस्व बताया जाता है। जौनपुर संसदीय क्षेत्र ठाकुर और यादव बिरादरी के लिए मुफीद है।

पशोपेश में भाजपा आलाकमान

राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति गरमा गई है। प्रदेश के प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अभी ज्यादा सक्रियता नजर नहीं आ रही है। राजे अभी भाजपा की परिवर्तन यात्रा से भी नदारद रहीं। वसुंधरा राजे की भूमिका पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। वहीं पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे कहां हैं इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री राजे को चुनाव से दूर कर रखा है या वह खुद ही चुनाव से दूर हैं। इस संबंध में कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वसुंधरा राजे पार्टी से नाराज हैं? राजस्थान में चुनाव प्रबंधन समिति के मुखिया नारायण पंचारिया ने राजे की सक्रियता को लेकर कहा कि वसुंधरा भी राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं और बड़े चुनाव प्रचार में आएंगी। माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे टिकटों की सूची देखकर किसी प्रकार का फैसला ले सकती हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हथियार डालने के लिए तैयार नहीं हैं। राजे को लेकर भाजपा आलाकमान पशोपेश में है। बगावत के डर से ही भाजपा ने किसी स्थानीय नेता को आगे नहीं किया है। माना जा रहा है कि भाजपा सत्ता में आती है तो वसुंधरा राजे की नाराजगी भाजपा को वैसी ही भारी पड़ सकती है, जैसे कांग्रेस को सचिन पायलट की पड़ी थी। वसुंधरा राजे ने धार्मिक यात्राओं के जरिए इशारों में इसके संकेत भी दे दिए हैं। आगामी दिनों में वसुंधरा राजे का नया रूप देखने को मिल सकता है।

लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं अपर्णा

उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। गत दिनों दिल्ली में भाजपा नेताओं से उनकी मुलाकात के बाद ऐसी चर्चाओं को और बल मिल गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा इसी सिलसिले में दिल्ली पहुंचीं। यहां उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और महासचिव सुनील बंसल से मुलाकात की। इसके बाद से उप्र की सियासत में भी अपर्णा यादव के चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कहा ये भी जा रहा है कि अपर्णा खुद भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। इससे पहले उप्र विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा द्वारा उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को प्रत्याशी बनाने के बाद अंदरखाने फूलपुर संसदीय सीट से अपर्णा को उम्मीदवार बनाने के कयास लगाए जा रहे थे। उप्र की सियासत में तब उनके नाम को लेकर हो रही चर्चा को चौंकाने वाला बताया गया था।

कांग्रेस का हाथ थामेंगे मसूद!

बसपा के पूर्व विधायक इमरान मसूद को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि इमरान मसूद कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। चर्चा है कि मसूद को फिर से कांग्रेस में शामिल करने को लेकर ब्लू प्रिंट तैयार हो गया है। असल में बसपा से निष्कासन के बाद पूर्व विधायक इमरान मसूद की सियासी गाड़ी मझधार में फंसी हुई है। बीते 10 सितंबर को उन्होंने अपने समर्थकों का एक सम्मेलन बुलाया था, जिसमें ज्यादातर कार्यकर्ताओं ने उन्हें वापस कांग्रेस ही ज्वाइन करने की सलाह दी थी। इसके बाद से ही उनके कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं शुरू हो गई थीं। हालांकि, इमरान मसूद ने उस समय अपने पत्ते नहीं खोल थे। लेकिन अब इमरान मसूद दिल्ली में कांग्रेस के कई राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के संपर्क में हैं जिस कारण इमरान मसूद के दोबारा से कांग्रेसी होने के कयास लगाए जाने लगे हैं।

एकला चलो की राह पर मायावती

इस साल होने वाले कई राज्यों के विधानसभा और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मायावती ने ट्वीट कर साफ किया कि उनकी पार्टी किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी। यानी मायावती न इंडिया और न ही एनडीए के साथ जाएंगी। बसपा सुप्रीमो ने एक के बाद एक ट्वीट कर कहा कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने इंडिया और एनडीए गठबंधन को सांप्रदायिक, पूंजीवादी और गरीब विरोधी पार्टियां बताकर कहा कि उनके साथ चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वहीं, बसपा चीफ ने कांग्रेस के वादे को हवा-हवाई बताते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सही तरह काम करती तो उसे सत्ता से बाहर ही नहीं होना पड़ता। हमारी पार्टी 2007 की तरह अकेले लोकसभा और राज्यों में होने वाले विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ गठबंधन के लिए सब तैयार हैं लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं। इससे पहले भी बसपा सुप्रीमो ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी। मगर अब उन्होंने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि वह एकला चलो की राह पर हैं।

मंत्री की सीडी चर्चा में

पिछले कुछ चुनावों से देश के हृदय प्रदेश में चुनावी सीडियां तहलका मचाती रही हैं। मिशन 2023 में भी कई नेताओं की सीडियां और वीडियो क्लिप्स आने वाली हैं। अभी तक कुछ ऐसे क्लिप्स आ भी गए हैं, जिससे कुछ नेताओं की साख पर सवाल उठे हैं। लेकिन एक मंत्रीजी की तथाकथित सीडी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस सीडी में क्या है, यह तो कोई नहीं जानता है, लेकिन अघोषित तौर पर कहा जा रहा है कि अगर यह सीडी सार्वजनिक हो गई तो मंत्रीजी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। सूत्रों का कहना है कि सीडी में मंत्रीजी की करतूतों की कहानी है, जिसे एक पूर्व विधायक लेकर घूम रहे हैं। यहां बता दें कि मंत्री और पूर्व विधायक एक ही जिले के रहने वाले हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि वर्तमान समय में दोनों एक ही पार्टी में हैं। सूत्रों का कहना है कि जब मंत्रीजी और पूर्व विधायक अलग-अलग पार्टी में थे तभी से दोनों के बीच टशन है, लेकिन जब से मंत्रीजी पूर्व विधायक की पार्टी में आए हैं, तबसे दोनों के बीच यह टशन बढ़ गई है। शायद यही वजह है कि पूर्व विधायक उनसे बदला लेने की फिराक में हैं और उनकी सीडी लेकर घूम रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अभी तक संगठन के दबाव के कारण पूर्व विधायक ने सीडी को सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन वे इस फिराक में हैं कि मौका मिलते ही सीडी को सार्वजनिक कर खलबली मचा देंगे, अगर मंत्री को टिकट दे दिया तो भी सीडी बाहर आनी है और पूर्व विधायक को नहीं मिला तब भी।

प्रशासनिक मुखिया के लिए अभी से जुगाड़

प्रदेश में चुनावी बिगुल के बीच प्रशासनिक वीथिका में कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इस जुगाड़ में लगे हैं कि उनको प्रशासनिक मुखिया की कुर्सी मिल जाए। गौरतलब है कि प्रदेश के वर्तमान प्रशासनिक मुखिया 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। प्रशासनिक वीथिका में चर्चा है कि उनके रिटायरमेंट के बाद किसी महिला को अगला प्रशासनिक मुखिया नियुक्त किया जाएगा, लेकिन उनकी पदस्थापना मात्र 10 दिन की रहेगी। इसलिए कई वरिष्ठ अधिकारी अभी से जुगाड़ में जुट गए हैं कि उन्हें प्रदेश का अगला मुख्य सचिव बना दिया जाए। इसके लिए उन्होंने भावी सरकार के लिए गुणा-भाग भी लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि कोई भी किसी एक तरफ जाकर रिस्क नहीं उठाना चाहता है, इसलिए मुख्य सचिव के दावेदार अफसर दोनों पार्टियों के नेताओं से संपर्क बनाए हुए हैं। ऊंट किस ओर करवट लेगा, यह तो अभी पता नहीं, लेकिन अफसर अभी से कयास लगाने में जुट गए हैं कि अमूक पार्टी जीतेगी तो अमूक आईएएस अधिकारी का सीएस बनने का सपना पूरा हो सकता है। फिलहाल प्रदेश के प्रशासनिक अफसरों में एक अनार सौ बीमार वाली स्थिति बनी हुई है।

तीन जिलों के एसपी आयोग के निशाने पर

अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने पुरानी शिकायतों के आधार पर दो जिलों के कलेक्टर और दो जिलों के एसपी को हटाकर उनकी जगह नए अफसरों की पदस्थापना कर दी है। हालांकि जब इन अफसरों को हटाया गया था, तो कई आईएएस और आईपीएस अफसर आयोग के पैमाने पर फिट नहीं बैठ पाए। अब जब चुनाव आयोग ने खाली सीटों पर कलेक्टर और एसपी की पदस्थापना कर दी है तो अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार अगर बदलती है तो कुर्सी पर बने रहेंगे अन्यथा रवानगी हो जाएगी। क्योंकि इसकी वजह यह है कि ये चारों चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किए गए हैं। अभी तो तीन जिलों के एसपी आयोग के निशाने पर बने हुए हैं। मुरैना के एसपी ने तो आचार संहिता लगने के एक दिन पहले ही 100-150 स्थानांतरण कर दिए। वहीं मंदसौर के एसपी जातीय समीकरण में तो ग्वालियर के एसपी ससुरालपक्ष भाजपा में होने के कारण आयोग के निशाने पर बने हुए हैं। इनकी भी रवानगी तय है। अब इसको लेकर नए एसपी जुगाड़ लगा रहे हैं कि यह तीनों जिले कब खाली होंगे और हम इन दमदार जिलों में पदस्थ हो जाएं। अभी आयोग ने कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन कुर्सी की चाह रखने वाले अफसर रात-दिन एसपी बनने का सपना देख रहे हैं। अब देखना यह है कि किसका सपना साकार होता है।

अफसरों में आई जान

कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेट्स जितना आपसी समन्वय बनाकर काम करते हैं, शायद ही कोई दूसरा वर्ग करता है। लेकिन वर्तमान समय में मप्र में स्थिति बिलकुल ही विपरीत है। यहां के आईएएस और आईपीएस अफसर प्रशासनिक लाटशाही के शिकार हैं। दूसरों को आवाज उठाने और दूसरों के अधिकार की बात करने वाले अफसरों की बोलती बंद है। अगर किसी ने तनिक भी चूं-चां की तो उसकी सीआर खराब कर दी जाती है। ऐसे में अफसर डरे-सहमे हुए हैं। लेकिन चुनावी साल में ऐसे अफसरों को एक पूर्व मुख्यमंत्री का साथ मिला है। उन्होंने हाल ही में अफसरों की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा है कि प्रदेश में किस तरह अफसरों को दबाया और डराया जा रहा है। उन पर दबाव बनाकर गैरकानूनी काम करवाया जा रहा है। अगर कोई अफसर ऐसा करने में आनाकानी करता है तो न केवल उसे हाशिए पर डाल दिया जाता है, बल्कि उसकी सीआर भी खराब कर दी जाती है। यही नहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने अफसरों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा है कि वे घबराएं नहीं, हम उनके साथ हैं। इससे अफसरों का मनोबल बढ़ा है।

गुनाह किसी का, सजा किसी को

इन दिनों एक प्रमोटी आईएएस अपनी नई जिम्मेदारी से इस कदर परेशान हैं। दरअसल, इन साहब को एक विवादित छवि वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के मामले में हाईकोर्ट में ओआईसी बना दिया गया है। गौरतलब है कि 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी की पारिवारिक विवादों के कारण नौकरी जाने वाली थी, लेकिन वे येनकेन वह कैट से जीत गए और उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए। इसको लेकर सरकार से उन्होंने नौकरी छोड़ने का आवेदन दिया, जिसे सरकार ने अमान्य कर दिया। भला जब कोई आरोपी नहीं है, तो उनके आवेदन को क्यों अस्वीकार कर दिया। यह साहब को नागवार गुजरा। इसको लेकर वह हाईकोर्ट में आए दिन रिट पिटीशन लगाते रहते हैं और सरकार को पार्टी बना दिया है। अब तो मजबूरी है कि किसी सीनियर व्यक्ति को रिट पिटीशन का जवाब तलब करने के लिए ओआईसी बनाना ही होगा। इसके चलते हुए अभी हाल ही में प्रमोटी आईएएस को ओआईसी बना दिया। फिर क्या था, साहब ठहरे एक नंबर के कंजूस अब बार-बार हाईकोर्ट और एजी ऑफिस के चक्कर लगाने होंगे। उधर, साहब की जेब सिली हुई है।

हमास ने जो दुस्साहस किया है, उसका परिणाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। उसने इजराइल को युद्ध के लिए चुनौती दी है। यह चुनौती उसके लिए घातक बनेगी, क्योंकि इस बार हम गाजा पट्टी को पूरी तरह नेस्तनाबूद करके ही रुकेंगे।

● **बेंजामिन नेतन्याहू**

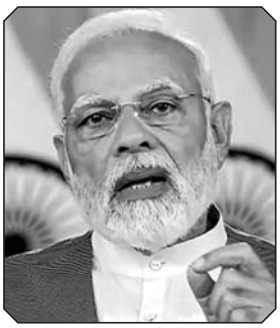

विश्व में आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है। भारत हमेशा शांति के साथ रहा है। इसलिए जहां भी आतंकी गतिविधियां होंगी, हम उसके खिलाफ रहेंगे। इजराइल में जिस तरह हमास ने आतंकी हमला कर सैकड़ों लोगों को मारा है, वह अक्षम्य है। इजराइल आतंकी संगठन हमास से जिस तरह लड़ रहा है, भारत उसके साथ पूरी तरह खड़ा है।

● **नरेंद्र मोदी**

अब भारत में खेलों के प्रति सरकारों के साथ ही युवाओं का भी फोकस बढ़ा है। इसका परिणाम 19वें एशियाई खेलों में देखने को मिला है। इतिहास में पहली बार भारत ने 100 से अधिक पदक जीतकर यह संकेत दे दिया है कि आने वाला समय भारत का है और खेलों की दुनिया में भारत गौरवमयी प्रगति करेगा और अपना दम दिखाएगा।

● **पीटी ऊषा**

इजराइल में हमने अपने सभी एम्प्लाइज से संपर्क किया है और उनका सपोर्ट करते रहेंगे। वहां हमारे 2,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। उन पर क्या गुजर रही होगी, यह हम भलीभांति जानते हैं। इस संकट की घड़ी में हम उनके साथ हैं।

● **सुंदर पिचाई**

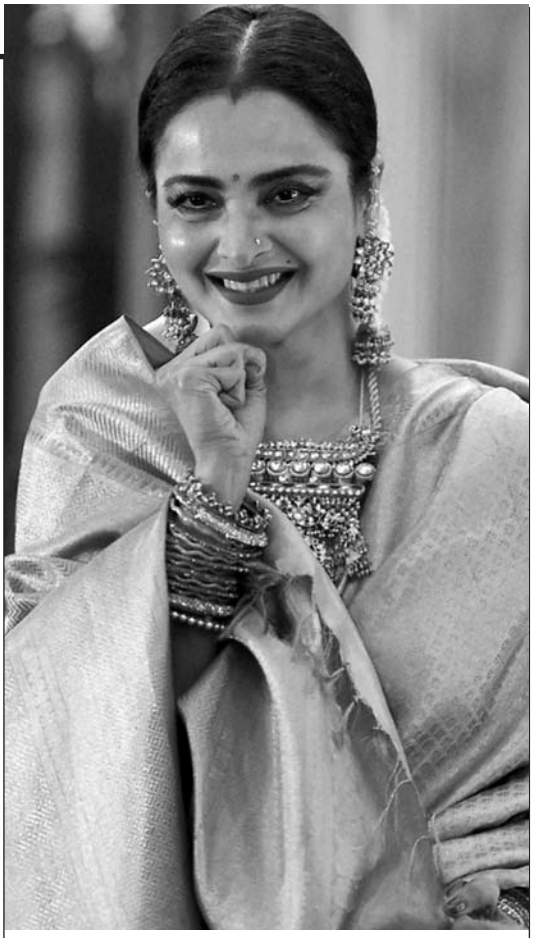

फिल्मी दुनिया में मैंने अपनी मेहनत से सफलता पाई। वैसे मैं बता दूं कि मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किस्मत की मार से फिल्मों में आई हूं। जब मैं 14 साल की थी, तो परिवार की स्थिति को देखते हुए मां के कहने पर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। मैं इस फील्ड में नहीं आना चाहती थी, लेकिन परिवार की मजबूरी मुझे खींच लाई। मेरा रूझान डांस और स्पोर्ट्स की तरफ था। जबकि मैं अपना भविष्य एयर होस्टेस के रूप में देख रही थी, लेकिन किस्मत के आगे किसकी चली है। मैंने फिल्मों में काम किया तो पूरी शिद्दत के साथ किया, जिसका परिणाम अब सबके सामने है।

● **रेखा**

वाक्युद्ध

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। हमारे विधायकों और नेताओं के खिलाफ झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं। अब तक हमारे खिलाफ 177 केस दर्ज किए गए, 140 फैसले हमारे पक्ष में आए। एक पैसे का घोटाला नहीं मिला। दरअसल, भाजपा हमसे डरी हुई है।

● **अरविंद केजरीवाल**

आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। स्कूलों से लेकर शराब तक के मामले में आम आदमी पार्टी की सरकार घिरी हुई है। अब दिल्ली ही नहीं, देशभर की जनता के सामने इनकी हकीकत उजागर हो गई है। इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

● **संबित पात्रा**

बिरादरी का विद्रोह

मप्र के इतिहास में अभी तक जितने भी मुख्य सचिव रहे हैं, उनकी विदाई पर पूरा प्रशासनिक महकमा भावविभोर हो जाता था। लेकिन वर्तमान मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस जब 30 नवंबर को रिटायरमेंट लेंगे तो प्रशासनिक महकमा दीपावली के बाद एक बार फिर दीपावली मनाएगा। शायद इससे पहले किसी भी अफसर की विदाई पर अधिकारी-कर्मचारी इतने खुश नहीं हुए होंगे।

मप्र के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस 30 नवंबर को रिटायर होंगे। यह दिन मप्र के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए खुशी का ऐतिहासिक दिन होगा। क्योंकि उनका कहना है कि इस दिन उन्हें लालफीताशाही से निजात मिलेगी। मप्र की प्रशासनिक वीथिका की हर गतिविधि पर नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा मुख्य सचिव देखा गया है, जिसने न तो मंत्रियों को भाव दिया और न ही अपने संगी-साथियों को। कनिष्ठ अधिकारियों को तो वे ठेंगे पर रखते हैं। यही कारण है कि प्रशासनिक वीथिका में हर कोई 30 नवंबर का इंतजार कर रहा है, जिस दिन इकबाल सिंह बैंस की विदाई पर एक महीने में दूसरी बार अधिकारी-कर्मचारी दिवाली मनाएंगे।

दरअसल, इकबाल सिंह बैंस का व्यक्तित्व ही ऐसा है। उन्होंने कभी भी न तो पद के साथ न्याय किया है और न ही अपने मातहतों के साथ। इन सबके बावजूद वे सरकार के चहेते अफसर बने रहे। सरकार किसी भी पार्टी की हो या मुख्यमंत्री कोई भी हो, इकबाल सिंह बैंस ने सबको साधकर काम किया है। इसलिए वे कभी लूपलाइन में नहीं रहे। इनको इस बात में महारथ हासिल है कि वे अच्छे-अच्छों को साध लेते हैं। अपनी इसी खासियत के कारण इन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिल में जगह बना ली है। इसका फायदा भी इन्हें भरपूर मिला है। ये हमेशा मुख्यमंत्री के करीबी अफसरों में शामिल रहे। इसी का परिणाम है कि इन्हें मुख्य सचिव बनाया गया। सूत्रों का कहना है कि मुख्य सचिव बनने के बाद इनके हाव-भाव पूरी तरह निरंकुश हो गए। इन्होंने न तो सरकार के मंत्रियों की कभी सुनी और न ही अफसरों की। फिर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैंस को दो बार सेवावृद्धि दिलवाई है। वरना तो वे नवंबर 2022 में ही रिटायर्ड हो जाते।

मुख्यमंत्री ने उन्हें दो सेवावृद्धि दिलाकर भले ही यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि बैंस एक योग्य प्रशासक हैं, लेकिन प्रशासनिक वीथिका में उन्हें निरंकुश, पक्षपाती माना जाता है। सभी जानते हैं कि मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की कार्यप्रणाली विवादों में रही है और वे अपने अधीनस्थों के साथ सख्ती से पेश आते हैं। उनके इस व्यवहार से तंग आईएएस खुल कर कुछ नहीं कहते लेकिन अनौपचारिक चर्चाओं में दर्द उभर आता है। इस पीड़ा को विगत दिनों एक रिटायर्ड आईएएस आरबी प्रजापति ने उठाया था। उन्होंने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस पर पक्षपाती होने के आरोप लगाए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर पूर्व आईएएस आरबी प्रजापति ने आरोप लगाया है कि इकबाल सिंह बैंस चुनावी प्रक्रिया से जुड़े हुए रिटर्निंग अधिकारियों को डिक्टेट करते हैं, इसलिए उनके रहते निष्पक्षता बनाए रखना संभव नहीं है। उन्हें हटाया जाना चाहिए। रिटायर्ड आईएएस आरबी प्रजापति ने 2014 के अशोकनगर कलेक्टर के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि इकबाल सिंह बैंस 2014 में शिवराज सिंह चौहान के प्रमुख सचिव थे। उस समय निर्वाचन पदाधिकारियों को प्रमुख सचिव इकबाल सिंह बैंस द्वारा नियंत्रित किया जाता था।

मप्र में इन दिनों पिता-पुत्र आईएएस की मनमर्जियां चर्चा में हैं। जहां एक ओर पूर्व आईएएस आरबी प्रजापति ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस पर डिक्टेटर होने का आरोप लगाया है तो मुख्य सचिव बैंस और उनके बेटे बैतूल कलेक्टर अमन सिंह बैंस पर मनमर्जियां चलाने का आरोप लगाते हुए डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे सड़क पर उतर आई हैं। अपने पद से इस्तीफा देकर निशा बांगरे साफ कर चुकी हैं कि वे बैतूल के आमला से चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन बैस पिता-पुत्र उनकी राह में बाधा बन रहे हैं। निशा बांगरे का आरोप है कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा है और उन्हें नोटिस देकर परेशान किया जा रहा है। इन आरोपों के साथ डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने लोकायुक्त में शिकायत की है। निशा बांगरे का कहना है कि प्रावधान है कि 30 दिन के भीतर इस्तीफा स्वीकार किया जाना चाहिए, लेकिन आईएएस पिता-पुत्र पद का दुरुपयोग कर प्रताड़ित कर रहे हैं।

● **सुनील सिंह**

नए अफसरों की सीआर खराब की

इकबाल सिंह बैंस प्रशासनिक वीथिका में नए अफसरों की सीआर खराब करने के लिए कुख्यात हो गए हैं। बताया जाता है कि इनकी मनमानी को न मानने वाले अफसरों को वे बिना सोचे-समझे न केवल हाशिए पर डाल देते हैं, बल्कि उनकी सीआर भी खराब कर देते हैं। प्रदेश के कई जिलों में पदस्थ आईएएस और आईपीएस अफसर की सीआर खराब किए जाने का मामला पिछले सप्ताह चर्चा में आ चुका है। हालांकि, कोई अधिकारी इस मामले में खुलकर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है पर मंत्रालय के प्रशासनिक हल्के में इसकी चर्चा जोरों पर है। इसके बाद अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश के युवा आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की सीआर खराब करने का मामला उठाया था। उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार आई तो युवा अफसरों का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से बगैर किसी डर के काम करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा था कि कई युवा आईएएस और आईपीएस अधिकारी जिन्होंने अपने वरिष्ठों के गैरकानूनी निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया, उन्हें अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में नकारात्मक मूल्यांकन का सामना करना पड़ा है। इससे उनके रिकॉर्ड खराब हो गए और उनका भविष्य खतरे में पड़ गया। आगामी विधानसभा चुनावों के बाद जब कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी तो हम इन मामलों का उनके गुणों के आधार पर गहन मूल्यांकन करेंगे।

मप्र में इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। भाजपा और संघ ही नहीं बल्कि कांग्रेस के सर्वे में भी भाजपा के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। शायद यही वजह है कि मप्र के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि पूरी भाजपा ने मप्र को अपना केंद्र बना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही भाजपा के दिग्गज चुनावी मोर्चे पर सक्रिय हैं। यह कांटेदार मुकाबले का संकेत है।

कांटेदार मुकाबला

विधानसभा की 230 सीटों वाले मप्र में 2023 के चुनाव की तैयारियां आखिरी दौर में हैं। पिछले एक साल से भाजपा के बड़े-बड़े रणनीतिकार प्रदेश में सक्रिय रहे, लेकिन अंतिम क्षणों में पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संभाल ली। भाजपा के विधायकों के प्रति मतदाताओं का असंतोष जाहिर है, लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुले रोष से बचे हुए हैं। दरअसल, 2005 में जब से आलाकमान ने शिवराज को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी तब से वे अभिभावक बनकर जनता की सेवा कर रहे हैं। अलग-अलग दिलो-दिमाग वाले सियासी इलाकों में सिमटी प्रदेश की 230 सीटों की राजनीति को शिवराज ने कमाल तरीके से समझा और भाजपा पर कभी भी अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने दी। उधर, कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ मोर्चे पर तैनात हैं। लेकिन भाजपा के खिलाफ जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है उससे इस बार मुकाबला कांटेदार होगा।

प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में 2018 का चुनाव संभवत: पहला मौका था जब परिणाम फोटो फिनिश जैसा रहा। इस बार के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री कर ली है। मुकाबला अब परंपरागत रूप से भाजपा-कांग्रेस के बीच होने के बजाय बहुकोणीय होता दिख रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी और सरकार भी कांग्रेस ने ही बनाई थी। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। उनकी सरकार डेढ़ साल भी नहीं चल पाई, क्योंकि कांग्रेस के 22 विधायकों ने विधानसभा से अपना इस्तीफा दे दिया था। इससे सूबे में सियासी संकट पैदा हो गया। इस संकट के केंद्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक पालाबदल था, जिसके चलते कमलनाथ सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फ्लोर टेस्ट से गुजरना पड़ा। फ्लोर टेस्ट की दोपहर ही कमलनाथ ने अपना इस्तीफा दे दिया और तीन दिन बाद 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। जो 22 विधायक कांग्रेस छोड़ गए थे, वे सब भाजपा में चले गए और सिंधिया को शिवराज ने राज्यसभा का टिकट दे दिया। इस समूचे प्रकरण में सियासी खरीद-फरोख्त के आरोपों के बीच सच्चाई कुल मिलाकर यही है कि शिवराज सिंह चौहान और भाजपा बीच के डेढ़ साल को छोड़ दें, तो तकरीबन बीस साल से सूबे में भाजपा सत्तासीन है। इसलिए इस बार के चुनाव में सबकी नजर कांग्रेस समेत अन्य दलों पर टिकी है।

इस कांटे की टक्कर में सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने है क्योंकि सत्ता-विरोधी माहौल के अलावा लंबे समय से मतदाता एक ही चेहरा देख-देख कर थक चुके हैं। इसी से मतदाताओं को उबारने के लिए शिवराज पूरे प्रदेश का तूफानी दौरा कर रहे हैं। वे हर जिले में कोई न कोई बड़ी परियोजना की शुरुआत कर रहे हैं और खास तौर पर अपने भाषणों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाली मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का भरपूर जिक्र करने से नहीं चूक रहे हैं। इस योजना में प्रदेश की सवा करोड़ से अधिक महिलाओं को सरकार हर महीने 1000 रुपए (अब 1250) दे रही है। और हो भी क्यों न? जब प्रदेश में कुल 5.39 करोड़ मतदाताओं में से 48.20 प्रतिशत मतदाता महिलाएं हैं और चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार पिछले दो चुनावों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत भी बढ़ा है, तो जाहिर है चुनाव प्रचार के केंद्र में महिलाएं ही रहेंगी। यही नहीं, मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण की

भाजपा की चुनावी बिसात

मप्र में पांचवी बार सरकार बनाने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने भी पूरी जमावट कर ली है। पार्टी जिला स्तर पर तीन-तीन प्रवक्ताओं की नियुक्ति कर रही है। इन तीन प्रवक्ताओं में एक महिला प्रवक्ता होगी। पार्टी ने प्रभारी और सह-प्रभारी बना दिया है। हर विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी उसके भौगोलिक, राजनीतिक और जातीय परिदृश्य को ध्यान में रखकर अन्य राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कद्दावर नेताओं को दी जा चुकी है। पार्टी ने इस बार उन चेहरों को जिम्मेदारी दी है जिनके पास चुनाव जिताने की काबिलियत रही है और उन खुशकिस्मत नेताओं पर दांव आजमाने का फैसला किया है जो विपक्षी पार्टियों के किसी भी कद्दावर उम्मीदवार को टक्कर देने में समर्थ और हार को जीत में बदलने में सक्षम हों। भाजपा ने मप्र का चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव को बनाया है। गृहमंत्री अमित शाह के मिस्टर भरोसेमंद कहे जाने वाले भूपेंद्र बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र के चुनाव प्रभारी रह चुके हैं और तीनों ही राज्यों में भाजपा सरकार बनाने में कामयाब रही है। मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए चुनाव प्रचार की कमान खुद शिवराज सिंह चौहान संभाल रहे हैं।

कार्रवाई में प्रदेश के 55 में से 41 जिले ऐसे पाए गए जहां महिला वोटरों के नाम ज्यादा जुड़े हैं। कम से कम 50 विधानसभा सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। इनमें अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए आरक्षित 18 सीटें भी शामिल हैं। भाजपा में एक तबके का मानना है कि राज्य सरकार की महिलाओं तक पहुंच बढ़ाने की कोशिश और उनके जीवन को बेहतर बनाना इस चुनाव में गेमचेंजर साबित होगा और पार्टी को 2018 में हारी हुई सीटों को जीतने में भी मदद मिलेगी। 2018 में भाजपा को कुल 56 सीटों का नुकसान हुआ था, हालांकि उसका वोट प्रतिशत कांग्रेस से एक प्रतिशत ज्यादा ही था।

प्रदेश में कई न्यूज चैनलों, एजेंसियों द्वारा चुनाव को लेकर तरह-तरह के सर्वे कराए गए हैं। उन सभी सर्वे में जनता की पहली पसंद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही हैं। दरअसल, बीमारू राज्य मप्र को शिवराज सिंह चौहान ने न केवल कलंक से मुक्ति दिलाई है, बल्कि इसे देश का सबसे विकासशील और सुंदर राज्य बनाया है। गौरतलब है कि मप्र ने पिछले सात दशक की राजनीति में कई उतार-चढ़ाव देखे। प्रदेश ने कई मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को देखा। विशेषकर, वर्ष 1993 से लेकर 2003 की तत्कालीन सरकार के कार्यकाल को लेकर नकारात्मक चर्चा होती रही है। वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव में नई सरकार ने जिन लक्ष्यों को लेकर सत्ता हासिल की थी, आज 20 वर्ष बाद हमें अंतर साफ नजर आता है। वर्ष 2003 के पहले प्रदेश बदहाल था। सड़कें गड्ढ़ों में परिवर्तित थीं, बिजली आती-जाती रहती थी। आमजन के लिए शासकीय सुविधाएं पाना कठिन था। शहरों के हालात बदतर थे, ग्रामीण जन-जीवन अपने पर ही निर्भर था। शासकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं स्वयं बीमार थी। शिवराज ने प्रदेश को इस संकट से उबारा है, इसका अहसास मप्र की जनता को है। इसलिए उसकी प्राथमिकता में शिवराज सिंह चौहान हैं।

मतदाताओं के मोर्चे को छोड़ दें, तो फिलहाल शिवराज के सामने तात्कालिक संकट कुछ और है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती नेताओं और

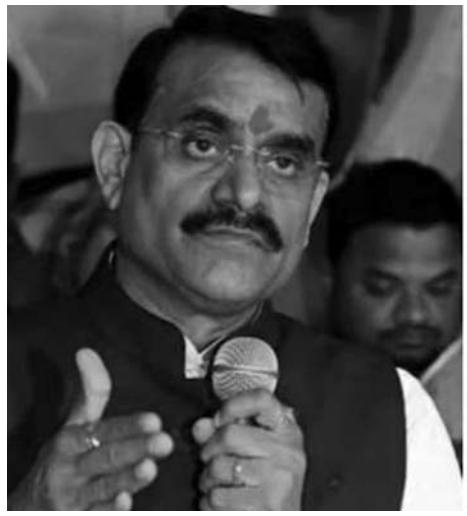

कार्यकर्ताओं के बीच से निकलकर आ रहे बगावत के सुरों और आलोचनाओं से निपटना है। फिलहाल स्थिति यह है कि प्रदेश भाजपा के कई बड़े नेता खुलकर पार्टी और कुछ नेताओं की आलोचना करने में जुट गए हैं। राज्यसभा के पूर्व सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा भी सार्वजनिक तौर पर संगठन के कार्यकलापों की आलोचना कर चुके हैं। उनका आरोप है कि पांच नेताओं को प्रदेश के संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है लेकिन वे संगठन नहीं चला पा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश संगठन की तुलना द्रौपदी से कर डाली है। भाजपा में अंदरूनी कलह के कई अजीबोगरीब मामले भी सामने आए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक साथ कई मंत्रियों के खिलाफ उन्हीं के इलाके के नेता खुलकर शिकायतें कर रहे हैं। ताजा उदाहरण पिछले महीने का है, जब मुख्यमंत्री के सामने उनके निवास में हो रही उज्जैन कोर कमेटी की बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के खिलाफ पूर्व मंत्री पारस जैन और पूर्व सांसद डॉ. चिंतामणि मालवीय समेत अन्य नेताओं ने एक सुर में मोर्चा खोल दिया। खास बात यह है कि ऐसे शिकवे-शिकायतें अब कोर ग्रुप की बैठकों तक पहुंच चुके हैं। शिवराज के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक दर्जन से ज्यादा उन विधानसभा सीटों की है जो भाजपा लंबे समय से जीतती आ रही है। उधर, कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की तर्ज पर मप्र में भी पे-सीएम कैंपेन चलाकर शिवराज और भाजपा को घेरने की तैयारी में है। आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी की रणनीति 2018 के मुकाबले एकदम भिन्न है। 2018 के चुनाव में पार्टी ने राहुल गांधी को ज्यादा तवज्जो दी थी। इस बार कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा के चेहरे पर दांव लगा रही है। इसकी झलक भी मिल चुकी है।

मप्र के चुनावी समर में भाजपा अगर सबसे अधिक किसी वर्ग को महत्व दे रही है तो वह है आधी आबादी यानी महिलाओं का वर्ग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो हमेशा से ही महिलाओं के लिए ऐसी योजनाएं क्रियान्वित करते रहते हैं जिसके कारण उन्हें मामा और भाई की उपाधि मिली हुई है। इस बार लाड़ली बहना योजना सबसे बड़ा उदाहरण है। वहीं केंद्र सरकार ने लोकसभा व विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर महिलाओं को साध लिया है। अब भाजपा को उम्मीद है कि चुनाव में उसे आधी आबादी का भरपूर समर्थन मिलेगा और पार्टी को बड़ी जीत मिलेगी। इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का फोकस महिलाओं पर रहेगा। पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार पार्टी महिला प्रत्याशियों की संख्या बढ़ा सकती है।

● **कुमार विनोद**

सामूहिक नेतृत्व का फॉर्मूला

भाजपा ने इस बार के चुनाव में सामूहिक नेतृत्व का फॉर्मूला बनाया है। इसकी झलक जन आशीर्वाद यात्रा में देखने को मिली। वहीं केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को टिकट के पीछे भाजपा की सामूहिक नेतृत्व के फॉर्मूले को धार देने की रणनीति भी एक वजह बताई जा रही है। मप्र में मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा किसी एक नेता को उम्मीदवार बताने से बच रही है और सामूहिक नेतृत्व के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। भाजपा 2018 के चुनाव नतीजों से सबक लेकर 2023 के लिए व्यूह रचना में जुटी है। ग्वालियर रीजन में कांग्रेस भारी पड़ी थी और इंदौर में भी भाजपा का गणित गड़बड़ हो गया था। ग्वालियर में कांग्रेस के खेवनहार रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भाजपा में आ चुके हैं लेकिन पार्टी किसी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर की गिनती ग्वालियर संभाग के प्रभावशाली नेताओं में होती है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ग्वालियर के साथ ही गुना और मुरैना में भी अच्छा प्रभाव है। वहीं, कैलाश विजयवर्गीय इंदौर, गणेश सिंह सतना, राकेश सिंह जबलपुर, उदयप्रताप सिंह होशंगाबाद, रीति पाठक सीधी क्षेत्र में प्रभावशाली नेता हैं। ये नेता जिन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ ही आसपास की कई सीटों पर भी परिणाम प्रभावित कर पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ा सकते हैं। भाजपा ने जिन 8 विधानसभा सीटों पर दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा है, उनमें से 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी।

सोशल मीडिया पर चुनावी वार तेज

मिशन 2023 के लिए भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने रणनीति बनाकर जहां मैदानी मोर्चा संभाल लिया है, वहीं दोनों पार्टियों के मीडिया सेंटरों ने चुनावी वार तेज कर दिया है। इसका नजारा सोशल मीडिया पर दिखने भी लगा है। मुद्दा बड़ा हो या फिर छोटा मीडिया सेंटर में तैनात नेता एक-दूसरे पर हमला करने से तनिक भी नहीं चूक रहे हैं। इसी क्रम में राजनीतिक दल खासकर भाजपा और कांग्रेस ने मप्र में अपनी मीडिया टीमों को चुनावी हमले के लिए सक्रिय कर दिया है। भाजपा ने राजधानी में राज्य स्तरीय अत्याधुनिक मीडिया सेंटर तैयार किया है। पार्टी की चुनाव संबंधी हर पत्रकारवार्ता या चर्चा यहीं हो रही हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से पुराने ढर्रे पर ही काम चला रही है। चुनाव को लेकर कांग्रेस ने किसी तरह का नया बदलाव नहीं किया है। इससे प्रदेश का राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है।

गौरतलब है कि प्रदेश के अधिकांश मतदाताओं तक पहुंचने का सबसे बड़ा माध्यम सोशल मीडिया है। इसलिए भाजपा-कांग्रेस ने इसके लिए बकायदा रणनीति बनाई है। कांग्रेस एवं भाजपा की मीडिया टीम के सभी पदाधिकारी सोशल मीडिया पर खासे सक्रिय हैं। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, कू, टिंबर एप से लेकर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लगातार विरोधी दलों पर हमलावर बने हैं। भाजपा के प्रदेश संवाद प्रमुख आशीष अग्रवाल कांग्रेस पर सबसे ज्यादा आक्रामक भूमिका में हैं। पार्टी के प्रवक्ता, पेनालिस्ट भी मीडिया, सोशल मीडिया पर खासे सक्रिय बने हुए हैं। जिन प्रवक्ताओं को जिला और संभाग स्तर पर दायित्व सौंपे हैं, वे भी मुस्तैदी से मोर्चा संभाले हैं। वहीं कांग्रेस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले और मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा भाजपा पर हमला कर रहे हैं और त्वरित पलटवार की स्थिति में रहते हैं। हालांकि बबेले पर्दे के पीछे रहना ज्यादा पसंद करते हैं, वे पार्टी प्रवक्ताओं और मीडिया टीम को लगातार भाजपा और सरकार पर हमला बोलने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। चुनावों में एक-दूसरे को घेरने के लिए मीडिया सेंटर का कितना बड़ा महत्व है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वार रूम में राष्ट्रीय प्रवक्ता भी तैनात किए गए हैं। कांग्रेस द्वारा चुनाव के मद्देजनर भोपाल के अलावा ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर में भी वार रूम शुरू किए गए हैं। यहां एक-एक राष्ट्रीय प्रवक्ता को दायित्व सौंपा गया है।

हाईटेक मीडिया सेंटर

भाजपा और कांग्रेस के मीडिया सेंटर आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। राजधानी के रानी कमलापति स्थित नवनिर्मित कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स में भाजपा का अत्याधुनिक मीडिया सेंटर शुरू हो गया है। यहां पत्रकारों के लिए वाईफाई से लेकर कम्प्यूटर एवं अन्य डिजिटल सुविधा है। हर समय पार्टी की मीडिया टीम पत्रकारों के लिए उपलब्ध रहती है। इसके अलावा प्रदेश के अलग-अलग हिस्से में राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए टीमें तैनात हैं। मीडिया टीम के पदाधिकारी हर समय सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और विपक्ष पर तीखे हमलावर बने हुए हैं। इधर, कांग्रेस ने इस तरह का कोई मीडिया सेंटर नहीं बनाया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से ही प्रेस से जुड़ी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। कांग्रेस में मीडिया के लिए भाजपा जैसी सुविधाएं बढ़ाने की कोई योजना फिलहाल नहीं है।

भाजपा की मीडिया टीम में प्रदेश प्रभारी आशीष अग्रवाल, प्रदेश प्रवक्ताओं में गोविंद मालू, मिलन भार्गव, राजपाल सिसौदिया, शशिकांत शुक्ला, पंकज चतुर्वेदी, डॉ. दुर्गेश केसवानी, नेहा बग्गा, प्रहलाद कुशवाह, नरेंद्र सलूजा, ब्रजगोपाल लोया, गुलरेज शेख, यशपाल सिंह सिसौदिया (विधायक), अर्चना चिटनीस, महेंद्र सिंह सोलंकी (सांसद), सुमेर सिंह सोलंकी (सांसद), केपी यादव (सांसद), सनवर पटेल, राम डागोरे (विधायक), डॉ. हितेश वाजपेयी हैं। जबकि जुगलकिशोर शर्मा (प्रदेशाध्यक्ष के मीडिया समन्वयक), नरेंद्र शिवाजी पटेल, जवाहर प्रजापति, प्रशांत तिवारी, अनिल पटेल, अशीष तिवारी, सचिन सक्सेना, विवेक तिवारी और दीपक जैन सह मीडिया प्रभारी हैं। वहीं बृजेश पांडे, शिवम शुक्ला, मंजरी जैन, वंदना त्रिपाठी और सचिन वर्मा मीडिया पेनालिस्ट हैं। खास बात यह है कि इनमें कुछ पदाधिकारी सोशल मीडिया पर ही ज्यादा सक्रिय दिखते हैं। जिन्हें चुनाव लड़ना है वे ज्यादा सक्रिय नहीं हैं। जबकि कुछ प्रवक्ता ज्यादा तेजतर्रार हैं, जो कांग्रेस पर हर तरह से हमलावर हैं। जिनमें प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी, बृजगोपाल लोया, मिलन भार्गव, गुलरेज शेख, दुर्गेश केसवानी और नेहा बग्गा पार्टी के लिए अपेक्षाकृत ज्यादा समय दे रहे हैं और विरोधी दलों पर तीखे प्रहार कर रहे हैं।

कांग्रेस की मीडिया टीम में कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा हैं। अभय दुबे स्टेट मीडिया समन्वयक हैं। जबकि संगीता शर्मा, अजय सिंह यादव, अब्बास हफीज, भूपेंद्र गुप्ता, विभा बिंदु डागोर, अवनीश बुंदेला, संतोष सिंह गौतम, आरपी सिंह मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं। जबकि प्रदेश प्रवक्ताओं में मृणाल पंत, स्वदेश शर्मा, मिथुन अहिरवार, संतोष सिंह परिहार, राम पांडे, आनंद जाट, अजीत सिंह भदौरिया, दीप्ति सिंह, रोहित नायक, संजय महेंद्र, विक्की खोंगल, अवनीश भार्गव, केदार सिरोही, आनंद तारण, राजकुमार केलू, कुंदन पंजाबी, जीतेंद्र मिश्रा, योगेश यादव, संदीप सबलोक, अमिताल अग्निहोत्री, रवि वर्मा, विक्रम खंपरिया, अपराजिता पांडे, देवाशीष जरारिया, शहरयार खान, अभिषेक बिलगैया, निकिता खन्ना, प्रवीण धौलपुरे, नीलाभ शुक्ला, अमीनुल खान सूरी, योगेंद्र सिंह जादौन, अलमास सलीम, हिदायत उल्ला खान, निर्मल पुरोहित और नितिन दुबे हैं। इसके अलावा 17 संभागीय प्रवक्ताओं की टीम है। इनमें से अब्बास हफीज, आनंद जाट, मिथिन अहिरवार, अवनीश बुंदेला, धर्मेंद्र शर्मा खासे सक्रिय हैं। ये ज्यादा समय पार्टी के लिए दे रहे हैं। कांग्रेस की मीडिया टीम भाजपा से बड़ी है, लेकिन कई पदाधिकारी पद लेने तक सीमित हैं। चुनावी साल में भी अपेक्षाकृत कम सक्रिय हैं। कुछ पदाधिकारी तो महीनों से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय तक नहीं आए। हालांकि ये सोशल मीडिया पर जरूर सक्रिय दिखते हैं। पार्टी ने कुछ पदाधिकारियों को दूसरे दायित्व भी सौंप दिए हैं। इस वजह से वे मीडिया विभाग को समय नहीं दे पा रहे हैं।

● **जितेंद्र तिवारी**

ओबीसी जिसके साथ उसकी सरकार

इतिहास स्वयं को दोहराता है किंतु इस बार उल्टा हो रहा है। जातियों की जकड़न से हिंदू समाज को निकालने की मंशा से हिंदुत्ववादी राजनीति की शुरुआत हुई और अब हिंदुत्ववादी राजनीति के उभार को समाप्त कर हिंदू समाज को पुन: जातियों के फेर में बांटने की साजिश रची जा रही है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी का राग भी वे नेता अलापने में लगे हैं जिन्होंने हिस्सेदारी न होते हुए भी राजनीति में पूरी भागीदारी से अपना आधिपत्य स्थापित किया हुआ है।

हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मप्र के शाजापुर में ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना पर बोलते हुए कहा कि हिंदुस्तान को 90 अफसर चलाते हैं। यह लोग कानून बनाते हैं। कितना पैसा कहां जाना है, यह तय करते हैं। भाजपा की दस साल से सरकार है। ओबीसी की आबादी कितनी है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जातिगत जनगणना नहीं हुई है। ओबीसी की आबादी हिंदुस्तान में लगभग 50 प्रतिशत है। 90 अफसरों में सिर्फ तीन अफसर ओबीसी के हैं। यह देश की सच्चाई है। ओबीसी राजनीति को हवा देते हुए राहुल गांधी ने आगे कहा कि हिंदुस्तान का बजट लाखों-करोड़ों का है। ओबीसी अफसर की भागीदारी बजट में कितनी है? यह कितने रुपए पर निर्णय लेते हैं? तकरीबन 43 लाख करोड़ रुपए का बजट है। किसी को पता ही नहीं है। सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान के पूरे बजट में 5 प्रतिशत की भागीदारी ओबीसी के अफसरों के हाथ में है। सही में मोदी ओबीसी के लिए काम करते हैं तो 90 अफसरों में उनकी संख्या तीन क्यों है? ओबीसी की जेब से पैसा चोरी हो रहा है। राहुल गांधी के भाषण के अगले दिन ही बिहार सरकार ने **जातिगत जनगणना** के आंकड़ें सार्वजनिक कर देश की राजनीति में उबाल ला दिया। उबाल तो मप्र की राजनीति में भी आया है जहां अब ओबीसी केंद्रित चुनाव होना तय है।

2018 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक बयान माई का लाल ने 15 वर्ष बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनवा दी थी। गौरतलब है कि 2018 में आरक्षण विवाद के चलते अनुसूचित जातियों और सवर्ण जातियों का बड़ा हिस्सा सरकार से नाराज हो गया था। हालांकि डेढ़ वर्ष पश्चात ही मप्र में पुन: भाजपा की सरकार बनी किंतु उसके बाद सरकार ने जातीय समीकरण साध लिए। मप्र में उत्तर भारतीय राज्यों की भांति जातिवाद राजनीति में कम ही घुला था किंतु 2023 के विधानसभा चुनाव अब इससे अछूते नहीं रहे हैं। बीते एक वर्ष में भाजपा और कांग्रेस ने जमकर जातीय सम्मेलन किए हैं। यहां तक कि दोनों ही राजनीतिक दलों ने जातियों के हिसाब से उनके महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर सार्वजनिक अवकाश की चुनावी घोषणा भी कर दी है। 2011 की जनगणना के अनुसार मप्र की जनसंख्या में 21.1 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति और 15.6 प्रतिशत अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी है जबकि प्रदेश की 50.09 प्रतिशत जनसंख्या अन्य पिछड़ा वर्ग की है। 230 सीटों वाली विधानसभा में कुल 82 सीटें (47 अनुसूचित जनजाति और 35 अनुसूचित जाति) इन वर्गों के लिए आरक्षित हैं। विंध्य क्षेत्र सवर्ण बहुल है तो चंबल पिछड़ी जातियों का गढ़ है।

मालवा-निमाड़ वनवासी बहुल क्षेत्र है तो मध्य भारत और महाकौशल संभाग में ओबीसी अधिक हैं। ऐसे में हर क्षेत्र के हिसाब से राजनीतिक दलों को अपनी गोटियां फिट करनी पड़ रही हैं। प्रदेश की 20-25 अनारक्षित विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां राजनीतिक दल जीतने के लिए सवर्ण के बजाय ओबीसी प्रत्याशी उतारते रहे हैं। इस बार ओबीसी कार्ड के चलते ऐसी सीटों पर और अधिक ओबीसी प्रत्याशी उतारना मजबूरी बन गई है। प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता स्व. पंडित रविशंकर शुक्ल (1952-56) से लेकर प्रदेश के सातवें मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता स्व. श्यामाचरण शुक्ल (1969-72, 1975-77) तक प्रदेश की राजनीति ब्राह्मणों के इर्द-गिर्द घूमती रही, जिसका तिलिस्म स्व. अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में टूटा और प्रदेश में राजपूत समुदाय की राजनीति हावी होने लगी, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जमकर हवा दी। 2003 में भाजपा नेतृत्व ने ओबीसी में आने वाली लोधी जाति की उमा भारती को कमान सौंपी और उसके बाद बाबूलाल गौर (यादव) तथा शिवराज सिंह चौहान (किरार) के चलते उसे पिछड़ी जातियों का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ।

● **प्रवीण सक्सेना**

ओबीसी को आरक्षण देने में परेशानी क्यों?

राजनीतिक दलों और नेताओं ने अपनी सारी विफलताओं और अकर्मण्यताओं को छिपाने के लिए आरक्षण को अब एक ऐसा हथियार बना लिया है, जिसका प्रयोग वहां भी किया जाने लगा है, जहां वास्तव में इसकी कोई जरूरत है ही नहीं। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना एक ऐसा ही कदम है। बल्कि यूं कहें कि एक ऐसा असंवैधानिक कदम है, जिसे लगभग सभी राजनीतिक दलों ने एकमत से संविधानसम्मत होने का जामा पहनाकर देश के संविधान का हिस्सा बना दिया है। महिलाओं को समान अवसर मुहैया कराने के नाम पर यह हमारे लोकतंत्र में लिंगभेद का सीधा-सीधा उदाहरण है, जिसके तहत एक तिहाई लोकसभा और विधानसभा सीटों पर पुरुषों को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। देश के तमाम राजनीतिक दलों ने एक साथ मिलकर यह असंवैधानिक कदम इस तथ्य के बावजूद उठाया कि महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर मुहैया कराने के लिए उन्हें आरक्षण देने की नहीं, बल्कि चुनाव में टिकट देने की जरूरत थी। आज यदि लोकसभा में लगभग 15 प्रतिशत सांसद ही महिलाएं हैं, तो इसका एकमात्र कारण यह है कि प्रमुख राजनीतिक दलों ने लगभग इतने ही प्रतिशत टिकट महिलाओं को दिए। यदि वे उन्हें 33 प्रतिशत या 50 प्रतिशत टिकट देते, तो आज बिना किसी आरक्षण के ही 33 प्रतिशत या 50 प्रतिशत सांसद महिलाएं होतीं।

मेट्रो से मिलेगी अर्थव्यवस्था को रफ्तार

देश के तेजी से विकसित हो रहे प्रदेशों में मप्र इस समय सबसे आगे दौड़ रहा है। यहां होने वाले नवाचारों से अर्थव्यवस्था तो बेहतर हो ही रही है, आमजन के लिए सर्वसुविधाएं भी सुलभ होने लगी हैं। इसी कड़ी में मप्र ने विकास की राह में एक और कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। इंदौर में प्रदेश की पहली मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन के साथ ही लोक परिवहन के क्षेत्र में नए अध्याय की शुरुआत हो गई। इंदौर के बाद राजधानी भोपाल में भी मेट्रो का ट्रायल रन हुआ। अब इसके बाद जबलपुर और ग्वालियर को भी मेट्रो जैसे तेज परिवहन माध्यम की सौगात मिलेगी। इंदौर सहित प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में भी आईटी और औद्योगिक क्षेत्रों का तेजी से विस्तार हुआ है। इसके परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्र की आबादी में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बुनियादी ढांचे पर जबरदस्त दबाव बढ़ा है। प्रमुख शहरों में बढ़ रही आबादी के साथ ही सड़कों पर वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इससे सिर्फ यातायात का दम ही नहीं फूल रहा, बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी हम दिल्ली-बेंगलुरू जैसे शहरों की तरह ही अपने शहरों में खराब आबोहवा से जूझ रहे हैं।

प्रदेश की राजधानी भोपाल में 15 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं, तो वहीं इंदौर में 21.5 लाख दो पहिया और चार पहिया वाहन सड़कों पर होते हैं। इनकी संख्या हर माह तेजी से बढ़ भी रही है। 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के आंकडों पर गौर किया जाए तो अकेले इंदौर शहर में ही एक वर्ष में परिवहन विभाग के पास रजिस्टर्ड होने वाले वाहनों की संख्या 1 लाख 61 हजार है। उधर, भोपाल में भी इसी अवधि में 98 हजार 572 वाहन पंजीकृत हुए हैं। ग्वालियर में 70 हजार 928 और जबलपुर में 62 हजार 281 नए वाहन सड़कों पर आ गए। वाहनों की इस गति से बढ़ती संख्या को देखते हुए यह अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि भले ही प्रदेश का कोई शहर महानगर श्रेणी में फिलहाल नहीं हो लेकिन ट्रैफिक जाम, प्रदूषित हवा और सड़कों पर वाहनों की रेलमपेल में जल्द ही यहां के शहर महानगरों को टक्कर देने लगेंगे।

शहरों की बात करें तो यहां 20 प्रतिशत यात्री भी फिलहाल लोक परिवहन के साधनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 53 प्रतिशत लोगों के पास अपने दो व चार पहिया वाहन हैं, जिनका इस्तेमाल वे आधा-एक किमी के सफर के लिए भी करते हैं। यही कारण है कि सड़कों के हाल दिनों-दिन खराब होते जा रहे हैं। वाहनों की बढ़ती संख्या पर्यावरण के लिहाज से भी कितनी चुनौतीपूर्ण है इसी से समझा जा सकता है कि एक पेट्रोल या डीजल कार एक वर्ष में 4.6 मीट्रिक टन कार्बन डाई आक्साइड उत्पन्न करती है। अकेले इंदौर में रजिस्टर्ड कारों की संख्या ही चार लाख से अधिक है। इन्हीं से 18.2 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाई आक्साइड उत्सर्जित होती है। इसमें तिपहिया और लोडिंग वाहन भी शामिल कर लिए जाएं तो प्रदूषण की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। वाहनों की बढ़ती संख्या के लिहाज से सड़कें तो काफी पहले ही छोटी पड़ने लगी हैं, लेकिन अब प्रदेश के शहरी क्षेत्र में चलने वाले वाहनों की रफ्तार 15-17 किमी प्रति घंटा से अधिक नहीं रह गई है। जबकि दिल्ली-मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों में शहरी क्षेत्र में चलने वाले वाहनों की रफ्तार 25 किमी प्रतिघंटा है। शहरों के निरंतर आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हो गया है कि बेहतर सड़क नेटवर्क के साथ हम मेट्रो जैसे त्वरित परिवहन माध्यमों का जाल तेजी से बिछाएं।

बीते 10 वर्षों में इंदौर, भोपाल और ग्वालियर जैसे शहरों में विकसित हुए नए औद्योगिक क्लस्टर, स्टार्टअप और आईटी पार्क ने इन शहरों की आर्थिक के साथ ही भौगोलिक संरचना को भी बदल दिया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से तैयार हो रहे इस नए इको सिस्टम के कारण शहरों की सीमाओं ने अपना दायरा भी बढ़ा लिया है। यह भी आवश्यक हो गया है कि इन औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास बन रहे नए आबादी क्षेत्रों में रहने वालों को परिवहन के अच्छे साधन उपलब्ध करवाए जाएं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में उपलब्ध सड़कें और फ्लाइओवर के साथ ही बस, रिक्शा या अन्य लोक परिवहन के साधन इतने पर्याप्त नहीं हैं कि वे यात्रियों को सुविधा दे सकें। इंदौर सहित प्रदेश के बड़े शहरों में अब मेट्रो ही भविष्य की जरूरत है। उज्जैन में महाकाल-महालोक बनने के बाद इंदौर से सड़क मार्ग से उज्जैन पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या ही हर दिन एक लाख से अधिक है। इसी तरह इंदौर से पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में भी हर दिन डेढ़ लाख से ज्यादा लोग अप-डाउन करते हैं। नए आईटी पार्क में आने वाली अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भी शहरों में परिवहन और आवागमन के साधनों का अध्ययन कर निवेश के लिए कदम बढ़ाती हैं। यही हाल भोपाल में मंडीदीप, बैरागढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों में भी है। लेकिन इन शहरों में व्यवस्था को जिस चुनौती से जूझना है, वह है मेट्रो के रूट तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जोड़ना। बी-टाउन शहरों में लोक परिवहन के साधनों का इस्तेमाल इसलिए भी अधिक नहीं होता क्योंकि फीडर रोड से मुख्य मार्गों तक कनेक्टिविटी बेहतर नहीं मिल पाती। यही वजह है कि इन शहरों में लोग अपने वाहनों से सफर करना अधिक पसंद करते हैं। नए दौर की इस परिवहन सेवा को इन शहरों के रहवासी आत्मसात तभी कर पाएंगे जब उन्हें घर के नजदीक से मेट्रो स्टेशन तक की सीधी कनेक्टिविटी मिल जाए।

● लोकेंद्र शर्मा

अहमदाबाद जैसे शहर बेहतर उदाहरण

देश के सबसे स्वच्छ और सबसे स्मार्ट शहर इंदौर से इस नए कदम की शुरुआत के मायने भी यही है कि यह शहर नवाचार को न सिर्फ तुरंत स्वीकार करता है बल्कि उसे सफल कर दूसरों को बता भी देता है कि यह राह मुश्किल नहीं है। अहमदाबाद जैसे शहर इसका बेहतर उदाहरण भी हैं। मेट्रो ट्रेन के सफलतम संचालन से वहां की सड़कों से 70 लाख वाहन सालाना कम हुए हैं। इससे शहर का पर्यावरण तो बेहतर हुआ ही है बल्कि वर्षा का मौसम हो या क्रिकेट मैच का उल्लास, यात्रियों को आवाजाही में सुगमता मिली है। मप्र में भी हमें इस नेटवर्क को तेजी से विस्तारित करने के ईमानदार प्रयास करने की जरूरत है ताकि भविष्य में मप्र मेट्रो पर सवार होकर विकास की पटरियों पर आगे बढ़ता चले।

जंगल की गोद भरेगा बांध का पानी

52 गांवों में होना थी सिंचाई

कारम बांध के फूटने के 15 माह लगभग पूरे हो चुके हैं। अब तक इसमें एक भी कदम सुधार की दिशा में नहीं बढ़ाया गया है। इसका खामियाजा क्षेत्र के 52 गांवों के लोगों को सूखे के तौर पर भुगतना पड़ेगा। बांध के कारण एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि धार जिले के 52 गांव के लोगों को सीधे तौर पर सिंचाई का पानी मिल सकता था। इससे पीने के पानी की उपलब्धता हो सकती थी। क्षेत्र में भूजल स्तर बढ़ने से सिंचाई और पीने के पानी की उपलब्धता आसानी से हो सकती थी। सबसे बड़ी बात है कि करीब 10500 हेक्टेयर जमीन जो कि अभी असिंचित है, वह सिंचित हो जाती। इससे आदिवासी अंचल के लोगों की जमीन संचित होती। गत वर्ष 43 मिलियन घन मीटर पानी बर्बाद हुआ था। इस बार बांध में पानी को संग्रहित नहीं किया जा सकेगा। नालछा नदी के साथ कारम नदी का अपना एक व्यापक संग्रहण क्षेत्र है। इसी बांध पर यह पानी पहुंचता है। ऐसे में अभी जो सवा महीने बरसात हुई है। उस वर्षा का पानी बर्बाद हो रहा है। यह नर्मदा नदी में जा रहा है। गत अगस्त में यदि यह बांध नहीं फूटा होता तो संभवत नहर निर्माण का कार्य अब तक शुरू हो गया होता। टेंडर प्रक्रिया चालू कर दी गई थी लेकिन दुखद बात यह है कि जैसे ही बांध टूटा तो जल संसाधन विभाग ने इस पूरे मामले में नहर निर्माण की प्रक्रिया से भी हाथ खींच लिए। स्थिति यह है कि जिला अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है।

भूजल स्तर के मामले में रेड जोन में शामिल धार जिले को सूखे से बचाने के लिए हर स्तर पर जल संरचनाओं के विस्तार का काम चल रहा है। शासन से लेकर प्रशासन तक अलग-अलग माध्यम से जल संरचनाओं की मंजूरी और निर्माण पर फोकस किया जा रहा है। इसका नतीजा है कि पहाड़ों पर बसाहट वाले इलाके में आने वाले गंधवानी के गूंगीदेवी में जल संसाधन बांध बनने जा रहा है। यह बांध नर्मदा की सहायक नदी पर बनने जा रहा है। ताकि जल संरक्षण के लिए पानी को रोका जा सके और आपूर्ति बढ़ाई जा सके।

गंधवानी की गूंगीदेवी ग्राम पंचायत में जल संसाधन धार द्वारा इस बांध का निर्माण करवाया जा रहा है। बांध निर्माण का काम करीब 6 माह से जारी है। इस पर शासन द्वारा 19 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ताकि बारिश के पानी को सहेजा जा सके। इसके लिए काम जारी है। बांध को पूरा करने के लिए 2 वर्ष की समय सीमा रखी गई है। गुजरात की कंपनी द्वारा काम करवाया जा रहा है। अब तक बांध के लिए जरूरी पाल बनाने का काम लगभग 80 प्रतिशत हो चुका है। बारिश के बाद इसे पूरा कर लिया जाएगा। इस बांध के बनने से गूंगीदेवी, रूखी बावड़ी, गोलपुरा, मालगढ़, ढिकनिया बयड़ी, भूरियाकुंड, रामपुरा सहित 10 से अधिक गांव के सैकड़ों किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा।

वर्तमान में इन गांवों में सिंचाई के लिए कोई खास संसाधन और पानी उपलब्ध नहीं है। पहाड़ी बसाहट होने के कारण खेती भी सीमित है। लेकिन बांध बन जाने के कारण किसानों को पानी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इससे करीब 830 हेक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी। इन गांवों में पानी की उपलब्धता होगी। जल संसाधन विभाग के गंधवानी एसडीओ शिवम जौहरी के अनुसार इस बांध के बनने से 4.15 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को रोका जा सकेगा। बांध के बनने से भूजल स्तर में बढ़ोतरी होगी। साथ ही क्षेत्र के 500 से 700 किसानों को रबी फसल के लिए पानी मिल सकेगा। क्षेत्र के किसान गेहूं व चने की फसल ले सकेंगे। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, धार बीपी मीणा का कहना है कि जल संसाधन विभाग द्वारा बांध का निर्माण करवाया जा रहा है। इस पर 19 करोड़ रुपए खर्च होना है। बांध बनने के बाद 830 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। वर्ष 2024 तक बांध का काम पूरा करने की योजना है।

धार जिले में बन रहे इस बांध से जहां लोगों में खुशी है, वहीं कारम बांध की स्थिति को देखकर लोग अभी भी चिंतित और डरे हुए हैं। गौरतलब है कि आदिवासी बहुल धार जिले में करीब 15 माह पहले कारम बांध देशभर की सुर्खियों में बना हुआ था। 14 अगस्त 2022 को इस बांध के मिट्टी वाले हिस्से में कटाव करके आपदा का पानी बाहर छोड़ दिया गया था। बांध पूरी क्षमता के साथ भरा हुआ था और ऐसे में न केवल यह पानी बह गया था बल्कि 10500 हेक्टेयर में सिंचाई करने की उम्मीदें भी टूट गई थी। मप्र सरकार ने बांध के सुधार की बात कही थी। घटना के करीब 15 माह बीत चुके हैं। अभी भी यहां पर सुधार कार्य की बुनियादी पहल भी नहीं हो पाई है। ऐसे में एक बार फिर 52 गांव में 10500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की उम्मीदें टूटी जा रही हैं। दूसरी ओर क्षेत्र में भूजल स्तर के सुधार से लेकर अन्य कई फायदे भी आपदा के पानी में बह गए हैं। जिस कारम बांध के निर्माण के बाद सिंचाई के लिए नहर निर्माण का कार्य शुरू हो जाना था। वह पूर्ण रूप से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। गौरतलब है कि गत वर्ष 11 अगस्त को अचानक से इस बात की जानकारी प्रकाश में आई थी कि कारम बांध के मिट्टी वाले बांध से पानी का रिसाव शुरू हो गया है। पहले तो इस रिसाव को संबंधित इंजीनियरों ने गंभीरता से नहीं लिया। उनका कहना था कि मिट्टी बांध से इस तरह का पानी का रिसाव होना स्वाभाविक है। लेकिन 12 अगस्त को यह रिसाव जिस तेजी से बढ़ने लगा, उससे यह तय हो गया कि यह बांध एक बड़ी आपदा लेकर आ सकता है। ऐसे में प्रशासन के अधिकारी से लेकर केंद्र व राज्य सरकार के जिम्मेदार अलर्ट हो गए। इस बांध से पानी की निकासी कर आसपास के 42 गांव में भीषण आपदा से बचाने की जुगत शुरू हुई। इसके लिए खुद मुख्यमंत्री लगातार निगरानी रख रहे थे। यहां तक कि प्रधानमंत्री भी स्वयं इस बात की प्रतिपल जानकारी ले रहे थे। ऐसे में गत 14 अगस्त को बांध से पानी की निकासी करते हुए भले ही आपदा को रोक दिया गया था। इस तरह की स्थिति तकनीकी लोगों की लापरवाही के कारण बनी थी। ऐसे में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 9 अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। इस तरह की सख्त कार्रवाई के साथ यह भी कहा गया था कि इसकी सुधार के लिए एक बड़ी पहल भी की जाएगी।

● **राकेश ग्रोवर**

मप्र में निवेश के लिए उमड़ी कंपनियां

> पीथमपुर सेवन स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी में अंतरराष्ट्रीय स्तर के विकास कार्य अभी जारी हैं, जिनके पूरा होने में और समय लगेगा, मगर इसके पहले ही देश के कई बड़े नामचीन उद्योग समूह और संचालकों ने करोड़ों रुपए निवेश करने के लिए कई हेक्टेयर जमीन आरक्षित करवा ली है। इससे साबित होता है कि इंदौर-पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र देश-विदेश के बड़े नामचीन उद्योगों की पहली पसंद बन चुका है।

मप्र में अब तक छह इन्वेस्टर्स समिट हुई हैं। छठी समिट इस साल जनवरी में आयोजित की गई थी। इस समिट के बाद से ही प्रदेश में निवेश करने के लिए देशी-विदेशी कंपनियां लगातार आ रही हैं। पीथमपुर सेवन स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी में अंतरराष्ट्रीय स्तर के विकास कार्य अभी जारी हैं, जिनके पूरा होने में और समय लगेगा, मगर इसके पहले ही देश के कई बड़े नामचीन उद्योग समूह और संचालकों ने करोड़ों रुपए निवेश करने के लिए कई हेक्टेयर जमीन आरक्षित करवा ली है। इससे साबित होता है कि इंदौर-पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र देश-विदेश के बड़े नामचीन उद्योगों की पहली पसंद बन चुका है। एमपीआईडीसी इंदौर के पीथमपुर सेवन इंडस्ट्रियल सिटी में 8 बड़े उद्योगों ने 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक निवेश करने के लिए 250 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन आरक्षित करवा ली है।

निवेशकों ने एमपीआईडीसी से वादा किया है कि इंडस्ट्रियल पार्क का विकास कार्य खत्म होते ही वह अपने मेगा इंडस्ट्रियल प्लांट डालने, यानी उद्योग लगाने का काम शुरू कर देंगे। इनका दावा है कि इन सभी उद्योगों की वजह से लगभग 12 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। एमपीआईडीसी (औद्योगिक विकास निगम) इंदौर लगभग 2232 हेक्टेयर में पीथमपुर सेवन स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क सिटी बना रहा है। फिलहाल इस पार्क में विकास से संबंधित योजनाओं के कार्य जारी हैं, मगर अभी तक 8 बड़े उद्योगों ने 255.95 हेक्टेयर जमीन की अग्रिम बुकिंग करवा ली है। इंडस्ट्रियल पार्क एंड सिटी पीथमपुर सेवन में जमीन आरक्षित करवाने वाले यह सभी उद्योग संयुक्त रूप से लगभग 10 हजार 533 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहे हैं। जिन बड़े उद्योगों के लिए इतनी जमीन रिजर्व की गई, जिन्होंने इतने करोड़ रुपए के निवेश का दावा किया है, इनमें 8 उद्योग हैं।

एक्सिओ लॉजिस्टिक पार्क के लिए एमपीआईडीसी इंदौर, पीथमपुर सेवन इंडस्ट्रियल सिटी में 19.73 हेक्टेयर जमीन रिजर्व कर चुकी है, जिसका भूखंड नंबर ए-वन है। यह प्राइवेट कंपनी 309 करोड़ रुपए का निवेश कर 4000 लोगों को रोजगार देगी। यह कंपनी लॉजिस्टिक पार्क और वेयर हाउस बनाती है। टीवीएस इंडस्ट्री ने ए-2 नंबर का 12.20 हेक्टेयर का भूखंड बुक कराया है। यह कंपनी 750 करोड़ रुपए का निवेश कर वेयर हाउस और लॉजिस्टिक पार्क बनाकर 1250 लोगों को रोजगार देगी। अवाडा इलेक्ट्रो कंपनी ने 40 हेक्टेयर जमीन बुक कराई है, जिसका भूखंड नंबर ए-3 है। यह कंपनी सोलर मॉड्यूल प्लांट के लिए लगभग 4500 करोड़ रुपए का निवेश कर 3000 लोगों को रोजगार देगी। जेएसडब्ल्यू पेंट्स कंपनी ने पेंट्स इमलशन और कोटिंग संबंधित निर्माण के लिए 40 हेक्टेयर जमीन बुक कराई है। इसका भूखंड नंबर ए-4 है। यह कंपनी लगभग 750 करोड़ रुपए का निवेश कर 1000 लोगों को रोजगार देगी। एशियन पेंट्स कंपनी ने 67.41 हेक्टेयर जमीन बुक कराई है, जिसका भूखंड नंबर ए-5 है। यह कंपनी लगभग 2000 करोड़ रुपए का पेंट्स बनाने प्लांट डालकर 1000 लोगों को रोजगार देगी। शक्ति सर्क्युलेटरी सॉल्यूशन कंपनी ने एडवांस्ड मैकेनिकल प्लास्टिक और रीसाइकिलिंग प्लांट के लिए 16.28 हेक्टेयर जमीन बुक कराई है, जिसका भूखंड नंबर ए-6 है। यह कंपनी 1025 करोड़ रुपए का निवेश कर 739 लोगों को रोजगार देगी। पिनाकल मोबिलिटी सॉल्यूशन कंपनी इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक लाइट

6 कंपनियां करेंगी 1920 करोड़ रुपए का निवेश

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद मप्र में निवेश प्रस्ताव आना शुरू हो गए हैं। जिससे बेरोजगार युवाओं में रोजगार मिलने की संभावना जगेगी। 24 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से फार्मा लॉजिस्टिक पार्क खाद्य प्रसंस्करण, आयरन एंड स्टील और प्लास्टिक के क्षेत्र में कार्यरत उद्योग समूह ने मंत्रालय में मुलाकात की। मप्र में निवेश और इकाइयों के विस्तार के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन उद्योगपतियों से चर्चा की है। देश की छह बड़ी कंपनियों में टीवीएस इंडस्ट्रीज एंड लॉजिस्टिक्स पार्क के सीईओ रामनाथ सुब्रमण्यम और रीजनल हेड कुशल मोतियानी, इप्का लेबोरेट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजित कुमार जैन, सात्विक एग्रो प्रोसेसिंग के नीलेश गर्ग और माणिक गर्ग, सर्वा फोम के कुणाल ज्ञानी, हिंदुस्तान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के राघवेंद्र मोदी और बैरलोकर इंडिया ऐडिटिव्स के ज्येन मोदी एवं अंकुर कुमार ने मुख्यमंत्री के समक्ष मप्र में 1920 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव रखे। इससे प्रदेश में 2850 लोगों के लिए नए रोजगार सृजित होंगे।

मोटर व्हीकल बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। इस कंपनी ने 21.40 हेक्टेयर जमीन बुक कराई है, जिसका भूखंड नंबर ए-7 है। यह कंपनी 500 लोगों को रोजगार देगी। फेंगल टेक्नोलॉजी कंपनी, जो कि वेयर हाउस और लॉजिस्टिक पार्क बनाती है, ने 180 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए 8.93 हेक्टेयर जमीन बुक करवाई है, जिसका भूखंड नंबर ए-8 है। यह कंपनी 200 लोगों को रोजगार देगी।

गौरतलब है कि पिछली पांच इन्वेस्टर्स समिट में 1 लाख 7 हजार करोड़ का निवेश आया और 2 लाख 40 हजार युवाओं को रोजगार मिला। प्रदेश में फिलहाल 320 बड़ी औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं। वहीं छोटे और मध्यम उद्योगों की संख्या 26 लाख तक पहुंच गई है। पहली समिट अक्टूबर 2007 में हुई, 102 एमओयू हुए, 17,311.19 करोड़ का निवेश आया और 49 हजार 750 को रोजगार मिला। दूसरी समिट अक्टूबर 2010 में हुई, 109 एमओयू हुए, 26,879.23 करोड़ का निवेश आया और 25 हजार को रोजगार मिला। तीसरी समिट अक्टूबर 2012 में हुई, 425 एमओयू हुए, 26,054.85 करोड़ का निवेश आया और 31 हजार 530 को रोजगार मिला। चौथी समिट अक्टूबर 2014 में हुई, 3,160 एमओयू हुए, 49,272.5 करोड़ का निवेश आया और 38 हजार 750 को रोजगार मिला। पांचवीं समिट अक्टूबर 2016 में हुई, 2,635 एमओयू हुए, 32,597.66 करोड़ का निवेश आया और 92 हजार 700 को रोजगार मिला। छठवीं समिट के बाद तो प्रदेश में निवेश की बहार आ गई है। प्रदेश में रेडीमेड गारमेंट्स के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। आटोमोबाइल के क्षेत्र में अनेक कंपनियां यहां काम कर रही हैं।

कोविड के दौरान मप्र के फार्मा सेक्टर ने विदेशों में दवाइयों का एक्सपोर्ट किया है। मप्र में आटोमोबाइल सेक्टर पहले से है, अब इथनाल पॉलिसी भी बनाई गई है। मप्र में कई तरह के खनिज हैं। कोयला, मैंग्नीज, कापर हैं, इससे जुड़े उद्योग की स्थापना लक्ष्य है। भोपाल में सिंगापुर के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय स्तर की कौशल प्रशिक्षण सुविधाओं वाला ग्लोबल स्किल पार्क बनाया गया है, ताकि यहां से उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप मानव संसाधन प्राप्त हो सके। अलग-अलग सेक्टर्स के लिए अलग-अलग पॉलिसी है। कई इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, आईटीआई को अपग्रेड किया गया है।

मप्र में इंडस्ट्री सेक्टर में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने और हजारों की संख्या में रोजगार पैदा करने के लिए एमएसएमई विभाग 100 एमएसएमई क्लस्टर विकसित करने के प्लान पर काम कर रहा है। हर जिले में कम से कम एक क्लस्टर होगा, जिसमें एक ही तरह के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग होंगे। एक जिला-एक उत्पाद के तहत बनाए जा रहे इन एमएसएमई क्लस्टर में 2 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 13 क्लस्टरों को स्वीकृति मिली है। 11 और क्लस्टर भी स्वीकृत किए जाएंगे। वहीं राज्य सरकार 76 क्लस्टर विकसित करेगी। इनमें से 31 क्लस्टर को स्वीकृति मिल चुकी है। जानकारी के अनुसार मप्र का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 100 औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करेगा। सरकार का अनुमान है कि इन क्लस्टरों से 2 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। फिलहाल 95 क्लस्टर चिन्हित किए जा चुके हैं। राज्य सरकार के तय 76 में से 27 क्लस्टर स्वीकृत हो चुके हैं और 27 स्वीकृति के लिए प्रक्रियाधीन हैं। शेष क्लस्टर के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और भूमि का चिन्हांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्लस्टर का उद्घाटन कराने की तैयारी की जा रही है। क्लस्टरों के माध्यम से प्रदेश में स्टार्टअप को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्र की एमएसई सीडीपी योजना के तहत कुल 13 क्लस्टर्स प्रदेशभर में स्वीकृत हो चुके हैं।

प्रदेश में अब तक औद्योगिक विकास चुनिंदा क्षेत्रों जैसे इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, देवास, पीथमपुर के आसपास होता रहा है, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन रहा है। नए क्लस्टर खुलने से दूरदराज और छोटे शहरों, ब्लॉक तथा तहसील तक उद्योगों का विकास होगा। प्रगति की समीक्षा हर 15 दिनों में होती है। विभाग के पास एमएसएमई अधोसंरचना के लिए 129 करोड़ का बजट उपलब्ध है। भोपाल में 2 निजी क्लस्टर्स को मंजूरी मिल चुकी है। इसमें खाद्य प्रसंस्करण (बैरसिया) और मल्टी स्टोरी मेडिकल डिवाइस क्लस्टर (गोविंदपुरा) शामिल है। जबलपुर का रेडीमेड गारमेंट, शिवपुरी में नेहरू जैकेट, छतरपुर में 2 फर्नीचर क्लस्टर, इंदौर-रतलाम में कई नमकीन क्लस्टर, सागर-विदिशा में कृषि उपकरणों सहित कई जिलों में फूड प्रोसेसिंग के क्लस्टर शामिल हैं।

● **कुमार राजेन्द्र**

1970 करोड़ का निवेश करेगी रिलायंस

वहीं रिलायंस, हेतिच इंडिया और पेप्सिको प्रदेश में चार हजार करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। गत दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हेतिच इंडिया और पेप्सिको इंडिया उद्योग समूह के प्रतिनिधियों ने भेंट की तथा प्रदेश में बायो गैस, फर्नीचर फिटिंग्स और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के संबंध में चर्चा की। रिलायंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष फरहान अंसारी तथा उपाध्यक्ष विवेक तनेजा ने बताया कि उनका समूह प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर लगभग 1970 करोड़ रुपए के निवेश से 10 कम्प्रेस्ड बायो गैस और 15 बायो गैस सघनीकरण संयंत्र स्थापित कर जैव ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश का इच्छुक है। इसी तरह फर्नीचर हार्डवेयर उत्पादों के निर्माण में विशेषज्ञता रखने वाली जर्मन कंपनी हेतिच इंडिया के प्रबंध संचालक आंद्रे अकोल्ट ने भेंटकर पीथमपुर में 700 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित हो रही कंपनी की नई इकाई की जानकारी दी। इकाई में लगभग 500 लोगों के लिए रोजगार सृजित होगा। कंपनी द्वारा पीथमपुर में वर्ष 2020 में 300 करोड़ रुपए के निवेश से एक इकाई स्थापित की जा चुकी है, जिससे लगभग 600 लोगों के लिए रोजगार सृजित हुआ है। हेतिच इंडिया इस इकाई का भी 270 करोड़ रुपए के निवेश के साथ विस्तार कर रही है। कब्जे (हिंज) बनाने की इस इकाई से भी लगभग 600 लोगों के लिए रोजगार सृजित होगा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पेप्सिको इंडिया के प्रेसिडेंट अहमद अल शेख, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किशोर मित्रा और चीफ कारपोरेट अफेयर्स गरिमा सिंह ने भेंट की। पेप्सिको इंडिया लगभग एक हजार 155 करोड़ रुपए के निवेश के साथ विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में खाद्य प्रसंस्करण (कार्बोनेटेड पेय) इकाई स्थापित करने की इच्छुक है, जिसमें लगभग 150 लोगों के लिए रोजगार सृजित होंगे।

नक्सलवाद पर नकेल

देश में नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर नीति बनाई है। इस संदर्भ में 6 अक्टूबर को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बैठक में कहा कि अगले दो साल में नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म कर देंगे। गृहमंत्री ने ये भी कहा कि 2022 में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सबसे कम हिंसक घटनाएं हुईं। इसके चलते होने वाली मौतों का आंकड़ा भी पिछले 4 दशक में सबसे कम रहा। शाह ने ये भी कहा कि नक्सलवाद मानवता के लिए अपवाद है। हम इसके हर रूप को जड़ से खत्म कर देंगे। वहीं, अफसरों ने बताया कि 2022 में नक्सली हिंसा में 77 प्रतिशत तक की कमी देखी गई। 2010 में यह काफी ज्यादा थी।

रीव्यू मीटिंग में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, और झारखंड के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मीटिंग में पहुंचे। वहीं, ओडिशा, बिहार, मप्र और छत्तीसगढ़ के मंत्री बैठक में शामिल हुए। अफसरों ने बताया कि पिछले 5 सालों में नक्सलवादी इलाकों में सिक्योरिटी में खासा सुधार हुआ है। केंद्र सरकार ने 2015 में नक्सली हिंसा मामले में राष्ट्रीय स्तर की नीति और एक्शन प्लान बनाया था। अफसरों ने बताया कि 2010 से तुलना करें तो 2022 में नक्सली हिंसा के चलते सिक्योरिटी फोर्सेस और आम लोगों की होने वाली मौतों में 90 प्रतिशत तक कमी आई। गृह मंत्रालय के डेटा के मुताबिक, 2004 से 2014 तक 17 हजार 679 नक्सली घटनाएं हुईं और 6984 मौतें हुईं। केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने कहा कि वर्ष 2022 में पिछले चार दशकों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा और मौतों की सबसे कम घटनाएं देखी गईं। उन्होंने कहा नक्सलवाद मानवता के लिए अभिशाप है और हम इसे इसके सभी रूपों में उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अधिकारियों ने कहा कि नक्सल प्रभावित राज्यों में हिंसक घटनाओं में 2010 की तुलना में 2022 में 77 प्रतिशत की कमी आई है।

अधिकारियों ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में देश में वामपंथी सुरक्षा स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। केंद्र सरकार ने 2015 में एलडब्ल्यूई से निपटने के लिए **राष्ट्रीय नीति** और कार्य योजना को मंजूरी दी थी। अधिकारियों ने कहा कि नीति में सुरक्षा संबंधी उपायों, विकास हस्तक्षेपों, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकदारियों को सुनिश्चित करने आदि को शामिल करते हुए एक बहु-आयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है। उन्होंने कहा कि इस नीति के दृढ़ कार्यान्वयन से देशभर में वामपंथी हिंसा में लगातार गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि वामपंथी हिंसा में सुरक्षा बलों और नागरिकों की मौत की संख्या भी 2010 की तुलना में 2022 में 90 प्रतिशत कम हो गई है।

आतंकी घटनाओं की संख्या कम हुई

बता दें कि एनआईए द्वारा आयोजित दो दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि मोदी सरकार ने हमेशा आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और उसका ही नतीजा है कि आज आतंकी घटनाओं में भारी कमी आई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2001 में आतंकी घटनाओं की संख्या 6 हजार थी जो 2022 में घटकर 900 रह गई हैं। पिछले 9 वर्षों में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में जम्मू-कश्मीर ने विकास और शांति की एक नई सुबह देखी है। अमित शाह ने जून 2004 से मई 2014 तक तत्कालीन सरकार और मोदी सरकार के जून 2014 से अगस्त 2023 के बीच हुईं आतंकी घटनाओं के तुलनात्मक आंकड़े पेश किए। जिसकी तुलना में मोदी सरकार के दौरान आतंकी घटनाओं में 70 प्रतिशत, इनमें नागरिकों की मृत्यु में 81 प्रतिशत और सुरक्षा बलों के जवानों की मृत्यु में 48 प्रतिशत की कमी आई है। शाह ने साफ किया कि अब आतंकवाद के पूरे ईकोसिस्टम को खत्म करने का समय आ गया है और एजेंसियों को इसके लिए रणनीति पर काम करना चाहिए।

गृह मंत्रालय द्वारा तैयार आंकड़ों के अनुसार, 2004 से 2014 के बीच वामपंथी उग्रवाद से संबंधित 17,679 घटनाएं हुईं और 6,984 मौतें हुईं। इसके विपरीत, आंकड़ों से पता चलता है कि 2014 से 2023 (15 जून 2023) तक 7,649 वामपंथी उग्रवाद से संबंधित घटनाएं और 2,020 मौतें हुई हैं। बिहार, झारखंड और मप्र में नक्सलियों के सफाए के बाद केंद्र सरकार अब छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में सिमटे नक्सलियों के खिलाफ अंतिम प्रहार की तैयारी में जुट गई है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बैठक में नक्सल विरोधी अभियानों और आगे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अमित शाह ने इस साल मार्च में सुकमा में नक्सलियों के गढ़ में स्थित कोबरा बटालियन के फारवर्ड पोस्ट का दौरा कर ग्रामीणों से सीधे बात की थी। शाह ने साफ किया था कि छोटे से इलाकों में सिमटे नक्सलियों के खिलाफ अंतिम प्रहार का समय आ गया है और जल्द ही देश की दशकों पुराने नक्सलवाद से मुक्ति मिल जाएगी। इस सिलसिले में मानसून खत्म होने के बाद हुई नक्सलरोधी अभियान से जुड़ी एजेंसियों की बैठक अहम थी। अमित शाह के साथ बैठक के बाद एजेंसियों के नक्सलरोधी अभियान को नई धार मिली है। आतंकवाद पर काफी हद तक लगाम लगाने के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने इसके पूरे ईकोसिस्टम को सख्ती से कुचलने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में कोई आतंकी संगठन खड़ा ही न हो पाए, इसके लिए सभी आतंकरोधी एजेंसियों को सख्त रुख अपनाना होगा। उन्होंने एनआईए, एटीएस और एसटीएफ जैसी एजेंसियों को आतंकी घटनाओं की जांच के दायरे से निकलकर आतंकवाद को जड़मूल से खत्म करने पर काम करने की सलाह दी।

अमित शाह ने बताया कि आतंकवाद खत्म करना किसी एक राज्य या एजेंसी के लिए संभव नहीं है। इसके लिए सभी को समन्वय के साथ काम करना होगा। उन्होंने देश में मौजूद सभी आतंकरोधी एजेंसियों के लिए एक समान ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाने और इसके लिए एनआईए और खुफिया ब्यूरो को पहल करने को कहा। शाह ने बताया कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार ने डाटाबेस तैयार किया है। इनमें ई-प्रिजन पर लगभग 2 करोड़ कैदियों का, ई-प्रोसिक्यूशन पर 1 करोड़ से अधिक अभियोजन का, ई-फोरेंसिक पर 17 लाख से अधिक फोरेंसिक का, नेशनल फिंगर प्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पर 90 लाख से अधिक फिंगर प्रिंट का, इंटिग्रेटेड मॉनीटरिंग ऑफ टेररिज्म पर 22 हजार आतंकी मामलों का, नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को आफेंडर पोर्टल पर 5 लाख से अधिक ड्रग तस्करों का, नेशनल डाटाबेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग आफेंडर्स पोर्टल पर 1 लाख मानव तस्करों का, क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर पर 14 लाख से अधिक आपराधिक अलर्ट और नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर 28 लाख साइबर क्राइम का डाटा उपलब्ध है।

● **अरविंद नारद**

पड़ोसी छीन रहा पानी

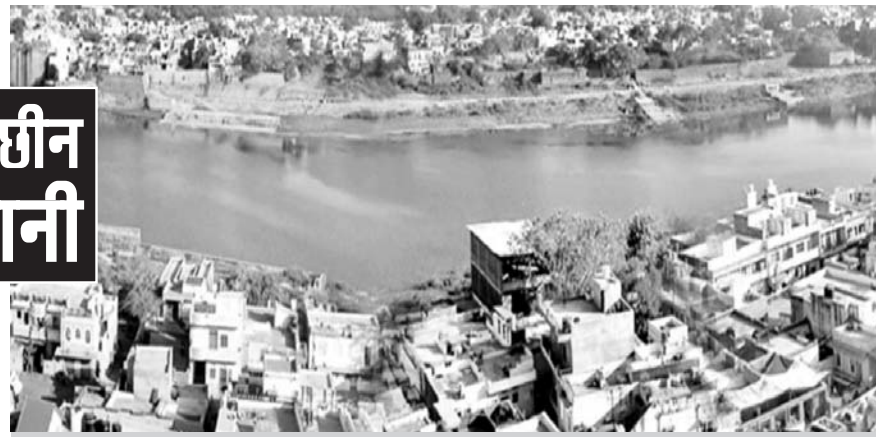

मप्र सरकार ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

चंबल नदी के पानी को लेकर मप्र और राजस्थान में विवाद बढ़ सकता है। दरअसल, राजस्थान सरकार ने बिना पर्यावरणीय मंजूरी के चंबल की सहायक नदी काली सिंध पर कोटा जिले में विशाल नौनेरा बैराज बना दिया है। उसने नहर के जरिए इसका पानी चंबल से डायवर्ट करने की तैयारी कर ली है। यदि भविष्य में कम बारिश हुई तो भिंड-मुरैना की सीमा पर बने राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी में पाए जाने वाले घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन की पानी नहीं मिलने से मौत हो सकती है। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए मप्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मप्र ने दलील दी है कि राजस्थान ने मनमाने ढंग से बनाए इस बैराज और नहरों के जरिए अंतरराज्यीय नदियों के लिए बनी केंद्रीय गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। यह बैराज और नहरें राजस्थान की ईस्टर्न कैनाल परियोजना का हिस्सा है। इस निर्माण के लिए न तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की क्लीयरेंस ली गई है, न ही पर्यावरणीय मंजूरी ली गई है। केंद्रीय जल आयोग से इस प्रोजेक्ट की टेक्नो-इकोनॉमिक क्लीयरेंस भी नहीं ली गई है। इस नियम विरूद्ध परियोजना के कारण भविष्य में मप्र के ग्वालियर-चंबल में कम बारिश हुई तो श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले में न केवल अकाल के हालात पैदा हो सकते हैं, बल्कि राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी में घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन के अस्तित्व पर भी संकट खड़ा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मप्र सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार, राजस्थान और उप्र सरकारों समेत, सेंट्रल वॉटर कमीशन और केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को नोटिस जारी कर एक माह के भीतर जवाब तलब किया है।

मप्र ने राजस्थान से अपने हिस्से का 3900 क्यूसेक पानी मांगा है। दरअसल, चंबल जल बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों की बैठक हुई। दोनों राज्यों ने चंबल पर अपनी-अपनी सीमा में मौजूद बांध और जल भराव के आंकड़ों को साझा किया है। इस दौरान मप्र ने चंबल जल बंटवारे पर सख्ती दिखाते हुए राजस्थान से 3900 क्यूसेक पानी की मांग की है। प्रदेश में मानसून के बाद चंबल घाटी की उपलब्धता और जल शेयरिंग पर मप्र और राजस्थान के जल संसाधन विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई। वर्चुअल मोड में हुई बैठक में दोनों राज्यों ने चंबल पर अपनी-अपनी सीमा में मौजूद बांधों और जलभराव के आंकड़े साझा किए। चुनावी साल में मप्र ने चंबल जल बंटवारे पर सख्ती दिखाते हुए राजस्थान से 3900 क्यूसेक पानी की मांग रख दी है।

मप्र और राजस्थान के बीच हुए एग्रीमेंट के मुताबिक, मप्र को कोटा बैराज से हर साल करीब 3900 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए। जिससे चंबल संभाग के जिलों में सिंचाई होती है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार नवंबर में दोनों राज्यों में रबी सीजन के दौरान सबसे ज्यादा पानी की डिमांड होती है, लेकिन राजस्थान 2800 से 2900 क्यूसेक पानी ही देता है। बहुत ज्यादा सख्ती दिखाने पर 3100 क्यूसेक ही पानी मिल पाता है। यानी करीब 1000 से 1100 क्यूसेक पानी पर अपने हिस्से में सिंचाई के लिए उपयोग करता है। चंबल संभाग के जिलों तक जल संसाधन विभाग ने करीब 350 किलोमीटर लंबा नहरों का जाल बिछा रखा है। पूरा पानी नहीं मिलने से इन जिलों के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पाता। इसमें ऊपरी हिस्से में पानी रोक नीचे के छोर तक पहुंचाया जाता है। सबसे ज्यादा लहार-अटेर वाला इलाका प्रभावित होता है। राजस्थान हर साल 1200 क्यूसेक पानी रोकता है। नहरों में सीपेज का बहाना बनाकर पानी रोक देता है। दोनों राज्यों को इसके मेंटनेंस पर 50-50 प्रतिशत राशि खर्च करते हैं। कोटा बैराज दोनों राज्यों को कुल 6656 क्यूसेक पानी सिंचाई के लिए मिलता है। किसान हर साल स्थानीय स्तर पर पानी नहीं मिलने की शिकायत भी करते हैं, लेकिन उन्हें पूरा पानी नहीं मिल पाता।

मप्र की अनुमति के बिना पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) में निर्माण कर रहा राजस्थान, चंबल पर बने कोटा बैराज से भी मप्र के हिस्से का पानी नहीं दे रहा। 25 साल से राजस्थान सरकार प्रदेश के किसानों का हक मार रही है। इसके बावजूद मप्र सरकार राजस्थान से गुहार ही लगाती नजर आ रही है। दोनों राज्यों की फिर हुई बैठक में जल संसाधन विभाग ने प्रदेश के हिस्से का पानी मांगा। राजस्थान ने हर साल की तरह हां कर दी है। राजस्थान ने मप्र से निकलने वाली चार नदियों पार्वती, कालीसिंध, क्यूल व कूनो पर अपनी सीमा में बैराज बनाकर पानी को चंबल नदी में जाने से रोककर नहरों के जरिए डायवर्ट करने की योजना तैयार की है। ये चारों चंबल की सहायक नदियां हैं। इसके लिए पिछले 50 साल की बारिश के आधार पर वर्षा जलग्रहण क्षमता को आधार मानकर बैराज बनाए जा रहे हैं। जबकि अंतर्राज्यीय नदियों के लिए बीते 75 वर्ष की बारिश के औसत के आधार पर वर्षा जल संग्रहण क्षमता पर ही बांध या बैराज बनाए जा सकते हैं। श्योपुर, भिंड और मुरैना तक 350 किमी लंबा नहरों का जाल बिछा है। पूरा पानी नहीं मिलने से तीनों जिलों के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पाता। ऐसे में ऊपरी हिस्से में पानी रोककर नीचे के छोर तक पहुंचाया जाता है। सबसे ज्यादा लहार-अटेर वाला इलाका प्रभावित होता है।

किसानों को पानी नहीं मिलने का मुद्दा तीनों जिलों की 13 सीटों को प्रभावित करता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 13 में से 10 सीटें कांग्रेस को मिली थीं। 25 साल में दोनों राज्यों में भाजपा और कांग्रेस की सरकार रही। समान पार्टी की सरकार होने के बाद भी राजस्थान ने कभी मप्र की इस मांग का ध्यान नहीं रखा। राजस्थान हर साल नहरों में सीपेज का बहाना बनाकर पानी रोकता है। दोनों राज्य मेंटेनेंस पर 50-50 प्रतिशत राशि खर्च करते हैं। कोटा बैराज से दोनों राज्यों को 6656 क्यूसेक पानी सिंचाई के लिए मिलता है। ईएनसी जल संसाधन शिशिर कुशवाह का कहना है कि राजस्थान के अफसरों से मप्र के हिस्से का पूरा पानी मांगा है। राजस्थान समझौते का पालन नहीं करता। मुरैना विधायक राकेश मावई का कहना है कि रबी सीजन में पानी की दिक्कत होती है। जल संसाधन विभाग के अफसरों के साथ बैठकर समस्या का समाधान कराते हैं। प्रदेश के हिस्से का पूरा पानी मिलना चाहिए।

विजयपुर विधायक सीताराम आदिवासी का कहना है कि राजस्थान सरकार हर साल कम पानी देती है। इस बार पानी कम दिया तो हम प्रमुखता से मुद्दा उठाएंगे। राजस्थान-मप्र अंतरराज्यीय कंट्रोल बोर्ड कोटा के सचिव संदीप सोहल ने बताया कि मप्र ने 19 अक्टूबर तक पानी पहुंचाने की मांग की है। चंबल से मप्र तक पानी पहुंचने में दो-तीन दिन लगते हैं। ऐसे में 16 या 17 अक्टूबर को नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। दाईं मुख्य नहर का सालाना रखरखाव समय पर कराने का मुद्दा भी उठा। राजस्थान ने मप्र फंड का हिस्सा मांगा। मप्र ने कहा कि दो वर्ष में कोई रखरखाव नहीं कराया गया, ऐसे में फंड नहीं दिया गया।

● **डॉ. जय सिंह सेंधव**

खाली बांधों ने बढ़ाई चिंता

इस बार कम समय में अतिवृष्टि और सूखे की स्थिति वाले अप्रत्याशित मानसून ने न सिर्फ बुआई में देरी की है बल्कि यह फसल की उपज को भी प्रभावित कर सकता है। बीते 123 साल में सबसे कम वर्षा इस बार अगस्त महीने में दर्ज की गई। इसके बाद भी सितंबर में हालात बहुत बेहतर नहीं हुए हैं। स्टैंडर्डाइज्ड प्रेसिपिटेशन इंडेक्स (एसपीआई) डाटा का विश्लेषण करने पर पाया गया कि देश के कुल 718 जिलों में से 500 से अधिक जिले वर्तमान में मौसम संबंधी सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं। इन 500 जिलों में हल्के शुष्क से लेकर अत्यधिक शुष्क तक की स्थितियां हैं। वहीं विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि सितंबर महीने में सूखे की ऐसी स्थिति फसल की उपज को नुकसान पहुंचा सकती है। एसपीआई सूखे की निगरानी के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अपनाया गया एक उपकरण है जो संभावित स्थितियों को दर्शाता है। सूचकांक में नकारात्मक मूल्यों का मतलब सूखे जैसी स्थिति और सकारात्मक मूल्यों का मतलब आद्र स्थिति से है।

मप्र में अब मानसून की विदाई शुरू हो गई है। लेकिन वर्तमान में स्थिति यह है कि प्रदेश के 55 में से 47 जिलों में सूखे जैसे हालात हैं। जिन जिलों में अगस्त में बाढ़ जैसे हालात थे और वहां के बांध और तालाब लबालब थे, वहां अब सूखे के हालात बनने लगे हैं। प्रदेश के 44 में से 37 डैम पूरी तरह भरे नहीं हैं। वहीं सिर्फ 7 फुल लेवल तक भरे हैं। इससे सिंचाई की समस्या खड़ी हो सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक मप्र के 55 में से 47 जिलों में सूखे के हालात बन रहे हैं। 27 जिलों में इस साल 46 प्रतिशत कम बारिश हुई जिसके चलते सूखे की स्थिति बनी हुई है। बड़ी बात तो ये है कि इस साल प्रदेश के अधिकांश डैम 100 प्रतिशत नहीं भर पाए हैं।

मानसून विदा होने के बाद जो स्थिति है उसके अनुसार प्रदेश के 84 प्रतिशत डैम खाली रह गए हैं। मप्र में कुल 44 डैम रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 37 के कंठ प्यासे हैं। सिर्फ जबलपुर, बैतूल, देवास, टीकमगढ़, खरगौन, रतलाम और नर्मदापुरम के डैम फुल लेवल तक भराए हैं। पिछले साल की बात करें तो अच्छी बारिश की वजह से भोपाल और उसके आसपास के डैम फुल हो चुके थे। 8 अक्टूबर से पहले ही ये सभी डैम एफटीएल लेवल तक आ गए थे, लेकिन इस साल 8 अक्टूबर तक कलियासोत डैम 1 फीट, केरवा डैम 1.6 फीट और कोलार डैम 4.8 फीट खाली है। छतरपुर का उर्मिल डैम 26 प्रतिशत, खंडवा का ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट 33 प्रतिशत, सीधी का माहन डैम 36 प्रतिशत, छतरपुर का रंगावन डैम 42 प्रतिशत, श्योपुर का अपर काकेतो डैम 44 प्रतिशत और विदिशा का संजय सागर डैम 49 प्रतिशत खाली है।

प्रदेश के कई हिस्से सूखे की कगार पर हैं। इनमें सतना, अशोकनगर, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, भोपाल, सीधी, गुना, शाजापुर और रीवा में कम बारिश हुई है। इसके इतर विंध्य और बुंदेलखंड में सबसे बुरे हालात हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, आगर-मालवा, अलीराजपुर, अशोकनगर, बड़वानी, बैतूल, बुरहानपुर, दतिया, देवास, धार, गुना, हरदा, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, नर्मदापुरम, नीमच, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, सीहोर, शाजापुर, श्योपुरकलां, शिवपुरी, विदिशा, बालाघाट, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, मंडला, नरसिंहपुर, रीवा, सतना, सागर, सिवनी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली और टीकमगढ़ इन जिलों में पानी बहुत कम मात्रा में गिरा है। शाजापुर, नीमच, उज्जैन, राजगढ़, मंदसौर, खंडवा और आगर-मालवा जिलों में 80 प्रतिशत तक कम पानी गिरा है। भारत का अधिकांश भाग यानी करीब 718 जिलों में करीब 53 फीसदी जिले हल्के सूखे श्रेणी में हैं। वहीं, मध्यम से अत्यंत सूखे वाली श्रेणी जो कि हॉटस्पॉट है उसमें लगभग संपूर्ण उत्तर पूर्व भारत, पूर्वी भारत के कुछ हिस्से और जम्मू-कश्मीर शामिल है। वहीं, इसके अलावा दक्षिणी प्रायद्वीप का बड़ा हिस्सा, पूर्वी तट पर महाराष्ट्र, कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश तक यही स्थिति है। एसपीआई सूखे की निगरानी के लिए एक मजबूत संकेतक है, लेकिन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पूर्व सचिव माधवन राजीवन के अनुसार सूचकांक के इन आंकड़ों की व्याख्या जटिल है। उन्होंने कहा, एसपीआई श्रेणियां अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग होती हैं और बाहरी तौर पर सूखा घोषित करने से पहले मौजूदा जमीनी हकीकत को भी ध्यान में रखना पड़ता है।

दरअसल, अगस्त 2023 में 21वीं सदी में तीसरा सबसे बड़ा मॉनसून ब्रेक देखा गया। मानसून ब्रेक 7 अगस्त से 18 अगस्त, 2023 तक चला। इतने लंबे ब्रेक के कारण बारिश में 36 प्रतिशत की कमी हुई, जिससे अगस्त 2023 रिकॉर्ड किए गए 123 वर्षों के इतिहास में अब तक का सबसे शुष्क वर्ष बन गया। राजीवन के अनुसार, मानसून 2023 की शुरुआत के बाद से ही वर्षा वितरण में अत्यधिक विषमता रही है। राजीवन का कहना है कि जून में हमारे पास 10 प्रतिशत की कमी थी, फिर जुलाई में 13 प्रतिशत की अधिकता और उसके बाद अगस्त अब तक का सबसे शुष्क महीना था।

● **राजेश बोरकर**

2023 में बुआई क्षेत्र 33 प्रतिशत अधिक रहा

क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप के अनुसार, 2022 की तुलना में 2023 में बुआई क्षेत्र 33 प्रतिशत अधिक रहा है, लेकिन इसका मतलब स्वचालित रूप से अधिक उपज नहीं है। कृषि जिंस विशेषज्ञ राजेश शर्मा का कहना है कि कटाई का मौसम अभी भी एक महीने दूर है, यह अनुमान लगाना मुश्किल होगा कि 2023 तक उत्पादन कैसा रहेगा। लेकिन शुरुआती रुझानों के अनुसार सोयाबीन के अलावा धान, तिलहन, मूंगफली और दालें जैसे सभी खाद्यान्न में गिरावट की आशंका है। शर्मा का कहना है कि पिछले साल की तुलना में संचयी बुवाई क्षेत्र में तीन फसलों - चावल, गन्ना और मोटे अनाज के कारण वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उत्पादन भी पिछले साल की तुलना में बढ़ेगा। शर्मा के मुताबिक, फसल उत्पादन में गिरावट का सबसे बड़ा कारण 2023 में कम बारिश बन सकती है। वर्तमान में (1 जून से 25 सितंबर, 2023) आईएमडी के वर्षा वर्गीकरण के आधार पर केवल 5 राज्यों से कम बारिश की सूचना है। एक विस्तृत विश्लेषण से पता चलता है कि 20 राज्यों से कम बारिश की सूचना है। भले ही वे सभी आईएमडी की सामान्य वर्षा श्रेणी में आते हैं। वहीं, अभी तक संचयी रूप से भारत ने 1971-2020 के दीर्घकालिक औसत वर्षा की तुलना में 5 प्रतिशत की कमी दर्ज की है।

अटक गया मास्टर प्लान

3 हजार आपत्तियां दरकिनार कर दी गईं

मास्टर प्लान-2031 के फाइनल ड्राफ्ट पर आईं 3000 आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया है। जून में जारी हुए ड्राफ्ट में केवल एक छोटा सा बदलाव किया गया है। आरजी-4 यानी शहर के बाहरी नव विकसित इलाकों में जहां बेस एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) 0.25 प्रस्तावित था, उसे बढ़ाकर 0.50 किया गया है। डेवलपर्स और टाउन प्लानर्स ने इसे कम से कम 1.25 करने की मांग की थी। बड़े तालाब और केरवा व कलियासोत के कैचमेंट एरिया में भी लैंडयूज और एफएआर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अरेरा कॉलोनी और चूना भट्टी में भी बेस एफएआर बढ़ाने की मांग को नामंजूर कर दिया गया है। इसके बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अफसरों ने फाइल विभागीय मंत्री भूपेंद्र सिंह के कार्यालय में भेज दी है। हालांकि, अभी इसकी मंजूरी नहीं मिल सकी है और अब चुनाव आचार संहिता भी लग गई है। वहीं, जनप्रतिनिधियों की नाराजगी भी है।

आखिरकार एक बार फिर भोपाल के मास्टर प्लान-2031 पर चुनावी ग्रहण लग गया है। सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है और उधर, विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई है। ऐसे में मास्टर प्लान पर विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार ही फैसला लेगी। इधर, मास्टर प्लान को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि भी नाराज हैं। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा तो खुले तौर पर विरोध कर चुके हैं।

दरअसल, भोपाल का मास्टर प्लान जारी होते-होते चौथी बार अटकने की स्थिति में है। 2 साल पहले भी दावे-आपत्तियों पर सुनवाई की गई थी, लेकिन मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ। इस बार 2 जून को सरकार ने ड्राफ्ट जारी किया था। 3005 आपत्तियों की सुनवाई के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अफसरों ने फाइल विभागीय मंत्री भूपेंद्र सिंह के कार्यालय में भेज दी थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। न ही नोटिफिकेशन जारी हुआ। अब इसकी मंजूरी को लेकर भी संशय बना हुआ है। मास्टर प्लान को लेकर अब कवायद चुनाव बाद यानी अगले साल जनवरी में ही होगी। प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद ही मास्टर प्लान को लेकर फिर से चर्चा की जाएगी। ऐसे में नगरीय प्रशासन विभाग के अफसर भी रिलैक्स मूड में आ गए हैं।

मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर 3005 आपत्तियां और सुझाव मिले थे। इनकी सुनवाई 6 चरणों में हुई। प्रथम चरण में 9 से 11 अगस्त तक, द्वितीय चरण में 16 से 18 अगस्त तक, तीसरा चरण 21 से 25 अगस्त, चतुर्थ चरण 28 से 29 अगस्त तक, पांचवें चरण में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक और 6वें चरण में 4 से 5 सितंबर तक सुनवाई की गई। आपत्तियों को लेकर जनप्रतिनिधियों, किसानों, आमजनों और क्रेडाई के सदस्यों ने भी अपनी नाराजगी जताई थी। सुनवाई के दौरान करीब 3000 आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया। ड्राफ्ट में केवल एक छोटा सा बदलाव किया गया। आरजी-4 यानी शहर के बाहरी नव विकसित इलाकों में जहां बेस एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) 0.25 प्रस्तावित था, उसे बढ़ाकर 0.50 किया गया। डेवलपर्स और टाउन प्लानर्स ने इसे कम से कम 1.25 करने की मांग की थी। बड़े तालाब और केरवा व कलियासोत के कैचमेंट एरिया में भी लैंड यूज और एफएआर में कोई बदलाव नहीं किया गया। अरेरा कॉलोनी और चूना भट्टी में भी बेस एफएआर बढ़ाने की मांग को नामंजूर कर दिया गया। इसके बाद विभाग ने मंत्री के कार्यालय को फाइल भेजी थी, जो बाद में अटक गई। भोपाल मास्टर प्लान-2031 पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने फिर सवाल उठाए हैं। शर्मा का कहना है कि इस मास्टर प्लान को हमने रद्द करने की बात कही है और यह रद्द होगा। मास्टर प्लान पर हम नए सिरे से काम करेंगे। इससे पहले आपत्तियों की सुनवाई के दौरान भी विधायक शर्मा नाराजगी जता चुके हैं।

विधायक शर्मा का कहना है कि जिन्होंने तालाब बचाया है, उन किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। किसानों की जमीन कृषि क्षेत्र में ही रहेगी। निर्माण की अनुमति मिलेगी तो ठीक, नहीं तो मास्टर प्लान नहीं आएगा। प्लान में कैचमेंट, एफएआर, उद्योग एवं कृषि उद्योग आदि पर पुनर्विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान या नागरिक को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस मास्टर प्लान को हमने रद्द करने की बात कही है और यह रद्द होगा। नए सिरे से मास्टर प्लान पर हम काम करेंगे। किसान की जमीन एग्रीकल्चर थी और होगी। उसे आवासीय या दूसरे क्षेत्र में लाया जाएगा। जिससे किसान के परिवार को लाभ हो। जीवन छिनने का काम सरकार नहीं करेगी। बल्कि उसका जीवन बनाने का काम करेगी। किसानों को आंदोलन करने की जरूरत भी नहीं है, मैं उनके साथ हूं। भोपाल के मास्टर प्लान का ड्राफ्ट 2 जून को सरकार ने जारी कर दिया था। ड्राफ्ट जारी होने के 30 दिन के अंदर कुल 3005 आपत्ति और सुझाव मिले थे। इनकी सुनवाई छह चरणों में हुई। प्रथम चरण में 9 से 11 अगस्त तक, द्वितीय चरण में 16 से 18 अगस्त तक, तीसरे चरण की सुनवाई 21 से 25 अगस्त, चतुर्थ चरण 28 से 29 अगस्त तक, पांचवें चरण में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक और छठवां एवं अंतिम चरण में 4 से 5 सितंबर तक सुनवाई की गई। आपत्तियों को लेकर जनप्रतिनिधियों, किसानों, आमजनों और क्रेडाई सदस्यों ने भी अपनी नाराजगी जताई थी। सुनवाई के दौरान 17 अगस्त को प्लान के प्रस्तावों पर विधायक शर्मा ने भी नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि प्रस्तावित मास्टर प्लान बिना भौतिक सत्यापन किए, शहर की परिस्थितियों को समझे बिना ही आंख बंद करके बना दिया गया है। यह शहर की 35 लाख आबादी के साथ धोखा है। 60-70 वर्षों से लेकर 100 साल तक पुराने गांव हैं, जो कि अब नगर निगम सीमा में हैं। उनकी भूमि एग्रीकल्चर थी। अब उनकी भूमि को ग्रीन बेल्ट और कैचमेंट में डाल दिया गया है। जिसके कारण वह अपनी भूमि पर खेती से संबंधित भी कोई उपक्रम या डेयरी आदि भी संचालित नहीं कर पाएंगे। ऐसे में उनके बेटा-बेटी कहां जाएंगे। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। ऐसे किसानों के परिवार का जीवन-यापन कैसे होगा? मास्टर प्लान इंसानों के लिए होता है लेकिन प्रस्तावित प्लान से इंसानों को बेघर किया जा रहा है। कलेक्टर के आदेश से जिन बस्तियां को पुन: बसाया गया है, उसे भी कैचमेंट में डाल दिया गया है। विधायक ने अन्य मुद्दों पर भी नाराजगी जताई थी।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

वन्य प्राणी हो रहे हादसों का शिकार

एक तरफ आम जनता के खिलाफ वन विभाग कड़े और सख्त कानून के साथ पेश आता है और दूसरी तरफ रिजर्व फॉरेस्ट और वनभूमि पर होने वाले निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतता है, इसी वजह से हर साल दर्जनों वन्य प्राणी जहां हादसों का शिकार हो रहे हैं। वहीं हजारों पेड़ काटे गए हैं, इसका खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है, जिससे पता चला है कि पिछले 10 सालों में वनक्षेत्र में होने वाले निर्माण कार्यों के लिए जो वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस दी गई है, उसका वन विभाग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालत ये है कि अब वन विभाग ने सभी टाइगर रिजर्व और सेंचुरी के अलावा रिजर्व फॉरेस्ट को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। वहीं दूसरी तरफ वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट वन विभाग के लापरवाह रवैये के खिलाफ भारत सरकार को शिकायत करने के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं।

दरअसल वन और वन्यजीवों के लिए समर्पित संस्था प्रयत्न ने आरटीआई के जरिए वन विभाग से जानना चाहा था कि पिछले 10 सालों में वन विभाग ने वनक्षेत्र खासकर टाइगर रिजर्व, सेंचुरी और नेशनल पार्क में निर्माण कार्य के लिए वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस दिए हैं, उनका रिकॉर्ड उपलब्ध कराएं। लेकिन वन विभाग के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि किन आधार पर इन प्रोजेक्ट्स के लिए वन विभाग ने क्लीयरेंस दिया है। जबकि वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भी भेजना होती है, ये खुलासा होने के बाद वन विभाग ने आनन-फानन में सभी वनमंडल, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क और सेंचुरी के लिए आदेश जारी कर जानकारी मांगी है।

मप्र की बात करें तो देश में सर्वाधिक वनक्षेत्र होने के साथ टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट और चीता स्टेट के अलावा कई वन्यजीवों के संरक्षण के लिए जाना जाता है, ऐसी स्थिति में मप्र के वनक्षेत्र जिनमें टाइगर रिजर्व, अभयारण्य, वनमंडल के वनक्षेत्र में रेललाइन, सड़क, बांध, पावर प्रोजेक्ट जैसी निर्माण परियोजनाओं के लिए वन विभाग से क्लीयरेंस लेना होता है, जो शर्तों के आधार पर दिया जाता है, तब जाकर वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस जारी होता है। क्लीयरेंस की शर्तों का प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी मुख्यालय और मैदानी अमलों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है और कमी पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है, इसके बाद वन विभाग सर्टिफिकेट जारी करता है, जिसे भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय को भी भेजा जाता है।

दरअसल वनक्षेत्र में होने वाले निर्माण कार्य और विभिन्न विकास परियोजनाओं में वन एवं वन्य प्राणियों को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए मिटीगेशन मिसर्स निर्धारित किए गए हैं। जैसे- सड़क और रेल लाइन के निर्माण के साथ वन्य प्राणियों के सुरक्षित आवागमन के लिए भी स्थायी व्यवस्था की जाए, जिनमें अंडर ब्रिज और अन्य तरह के निर्माण किए जाते हैं। वहीं निर्माणाधीन परियोजना में हरे वृक्षों की न्यूनतम कटाई करने के अलावा जरूरत पड़ने पर पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने का भी प्रावधान है, लेकिन मप्र वन विभाग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है।

भारत सरकार का वन मंत्रालय 2021 से मप्र वन विभाग से जानकारी मांग रहा है, लेकिन मप्र वन विभाग अभी तक जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाया। ऐसे में मप्र वन विभाग ने सभी टाइगर रिजर्व, अभयारण्य और डीएफओ को नोटिस जारी किया है। हाल ही में मप्र वन्य प्राणी मुख्यालय ने 15 सितंबर 2023 को नोटिस जारी कर शीघ्र जवाब मांगा है। वाइल्डलाइफ और आरटीआई एक्टिविस्टों का कहना है कि मप्र के वन विभाग के पास **वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस** की शर्तों के पालन के संबंध में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, ये जवाब हमें आरटीआई के संबंध में दिया गया है। वन विभाग का कहना है कि हमने सारे टाइगर रिजर्व, सेंचुरी और डीएफओ से जानकारी मांगी है। इस मामले में दुखद पहलू ये है कि 10 सालों में मप्र सरकार के वन विभाग ने ध्यान ही नहीं दिया कि वन और वन्यजीवों की सुरक्षा और सुविधा के संबंध में निर्माण कार्यों में क्या शर्तें रखी गई हैं। इनके मापदंडों को सुरक्षा के लिहाज से कड़ाई से पालन होना चाहिए, इस रिकॉर्ड का वन विभाग के पास मौजूद ना होना बड़ी लापरवाही है। वन्य प्राणी मुख्यालय की गंभीर लापरवाही को लेकर मप्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिख कार्यवाही की मांग करेंगे और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे, क्योंकि इस गंभीर लापरवाही से विगत वर्षों में कई दुर्लभ वन्यजीव रेल लाइन और सड़क मार्ग पर हुई दुर्घटना में जान गवां चुके हैं।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

वन्य प्राणी संरक्षण में मप्र नंबर वन

वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का घर मप्र जैव विविधता से इतना संपन्न है कि एनिमल्स के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। प्रदेशभर में 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और आपको यह जानकर और खुशी होगी कि वन्य प्राणी संरक्षण में मप्र पहले नंबर पर आता है। राज्य वन विभाग की बात करें तो मप्र न केवल टाइगर स्टेट, बल्कि घड़ियाल स्टेट, तेंदुआ स्टेट, भेड़िया स्टेट और गिद्ध स्टेट के नाम से भी दुनियाभर में जाना जाता है। वहीं 17 सितंबर 2022 से मप्र को चीता स्टेट होने का गौरव भी मिल चुका है। चीता और टाइगर स्टेट के साथ ही मप्र कैट प्रजाति के तेंदुआ (लेपर्ड) के लिए भी नंबर वन पर है। लेपर्ड को बेहद चालाक जानवर माना जाता है। 2018 लेपर्ड गणना के मुताबिक मप्र में 3,427 लेपर्ड हैं। यही कारण है कि इसे लेपर्ड स्टेट भी कहा जाता है। यहां लेपर्ड लगभग प्रदेश के हर कोने के जंगल में पाया जाता है। इसी तरह भेड़िया संरक्षण के मामले में भी मप्र नंबर वन पर है। राज्य में भेड़िए की आबादी 772 है। इसके बाद राजस्थान का नंबर आता है, जहां संख्या 532 है। कहा जाता है कि मप्र की आबोहवा और यहां का वातावरण भेड़ियों को भी बहुत पसंद है। यही कारण है कि लगातार इस वन्यजीव का कुनबा यहां बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मप्र को भेड़िया या वुल्फ स्टेट का खिताब भी मिला हुआ है। मप्र गिद्ध संरक्षण के मामले में भी देश में सबसे आगे है। पिछली गणना के अनुसार मप्र में 9,448 गिद्ध मिले। इसी के चलते इसे गिद्ध स्टेट का दर्जा भी हासिल है। भोपाल के केरवा इलाके में 2013 में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया गया था। इसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी और मप्र सरकार द्वारा संयुक्त तौर पर संचालित किया जा रहा है। मप्र में कुल सात प्रजातियों में गिद्ध पाए जाते हैं। इनमें से चार स्थानीय और तीन प्रजाति प्रवासी हैं, जो शीतकाल समाप्त होते ही वापस चली जाती हैं। प्रदेश में सबसे अधिक गिद्ध पन्ना, मंदसौर, नीमच, सतना, छतरपुर, रायसेन, भोपाल, श्योपुर और विदिशा में पाए जाते हैं। इन जिलों के जंगलों में गिद्धों की संख्या तेजी से बढ़ी है।

5500 करोड़ में बनेगा ढोढ़न बांध

केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण भोपाल ने केन नदी पर 5500 करोड़ रुपए से ढोढ़न बांध के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया है। बांध निर्माण के लिए जारी किया गया टेंडर जल्द ही खोला जाएगा। 8 साल की प्रस्तावित अवधि में बांध का निर्माण होगा। हालांकि टेंडर हो जाने के बाद भी केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। इसके लिए टेंडर में शर्त भी रखी गई है।

बिजावर एसडीएम राकेश शुक्ला ने बताया कि छतरपुर जिले के 14 गांव विस्थापित किए जा रहे हैं। इन गांवों में भरकुआं, ढोढ़न खरियानी, कुपी, मैनारी, पलकोंहा, शाहपुरा, सुकवाहा, पाठापुर, नैगुवां, डुंगरिया, कदवारा, घुघरी, बसुधा शामिल हैं। इन गांवों के विस्थापित परिवारों को भैंसखार, राइपुरा, नंदगांयबट्टन और किशनगढ़ में बसाया जाएगा। इन चारों स्थानों पर जमीन को चिन्हित कर लिया गया है। केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना में पन्ना जिले के 11 गांव विस्थापित किए जाएंगे। पहले 8 गांवों को विस्थापित करने के लिए चिन्हित किया गया था। इनमें पन्ना तहसील के गहदरा, कटहरी बिलहटा, मझौली, **कोनी और डोंडी** और अमानगंज तहसील के खमरी, कूड़न और मरहा गांव शामिल हैं। इसके अलावा ललार, रमपुरा, जरधोबा और कंडवाहा गांवों की भी शासकीय राजस्व भूमि विस्थापित करने का फैसला लिया गया है, तीनों गांवों में लोक सुनवाई की जा चुकी है। विस्थापित होने वाले सभी 11 गांव पीटीआर के अंदर बसे हुए हैं। इन गांवों की जमीनों को पन्ना टाइगर रिजर्व को सौंप दिया जाएगा।

प्राधिकरण ने परियोजना के तहत अब तक पन्ना और छतरपुर जिला प्रशासन के माध्यम से 4 हजार हेक्टेयर जमीन पन्ना टाइगर रिजर्व (पीटीआर) को सौंप दी है। इसमें से 3400 हेक्टेयर छतरपुर जिले में और 600 हेक्टेयर पन्ना जिले में सौंपी गई है। इसके अलावा एक हजार हेक्टेयर राजस्व भूमि को छतरपुर जिले में सौंपने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इसके अलावा जंगल में बसे गांवों को भी विस्थापित किया जा रहा है। विस्थापन से खाली होने वाली 1300 हेक्टेयर निजी जमीन भी पीटीआर को सौंप दी जाएगी। केन-बेतवा लिंक परियोजना का निर्माण कार्य आठ साल में पूरा होगा। निर्माण कार्य की कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। परियोजना के प्रीकंस्ट्रक्शन और इनवेस्ट सर्वे के लिए 243 दिन का समय तय किया गया है। वहीं 730 में जमीन अधिग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। जबकि पहुंच मार्ग के लिए 487 दिन, प्रोजेक्ट रोड के लिए 488 दिन, ऑफिस व कर्मचारी निवासी के लिए 518 दिन और निर्माण के लिए बिजली उपलब्ध कराने के लिए 549 दिन का लक्ष्य रखा गया है।

कटनी, सतना और पन्ना को मिलेगा इसका फायदा

यही स्थिति 1909 में बने गंगऊ बांध को लेकर भी है। केन-बेतवा लिंक परियोजना में ढोढ़न बांध विकल्प बन जाएगा। इससे निकली नहर बेतवा में मिलेगी। वहीं, मप्र सरकार की कोशिश है कि ढोढ़न बांध पर पूरी तरह से मप्र सरकार का ही नियंत्रण हो। जल संसाधन विभाग के अनुसार इसमें 6590 एमसीएम इल्ड है। 2066 एमसीएम रिजर्व कोटा है। इसकी लाइव स्टोरेज क्षमता 2683 एमसीएम तथा 2853 एमसीएम ग्रॉस स्टोरेज है। इससे 19633 वर्ग किलोमीटर एरिया में पीने के पानी और सिंचाई की जरूरत पूरी हो सकेगी। कटनी, सतना और पन्ना जिले को इसका फायदा मिलेगा। रबी सीजन में 2634 एमसीएम पानी मप्र को और 750 एमसीएम पानी उप्र को मिल सकेगा। पहले उप्र सरकार इस बांध से आधा पानी मांग रही थी। जल संसाधन विभाग के अनुसार बांध केन नदी पर 2.5 किलोमीटर ऊपर अपस्ट्रीम में बनाया जाएगा। वहीं, 1965 में बने बरियारपुर बांध का भी रिनोवेशन किया जाएगा। तकनीकी कमेटी इसके लिए बजट तैयार कर रही है। इसके कुछ खसरे उप्र में दर्ज हैं। 1972 में हुए एग्रीमेंट के अनुसार इसका मेंटनेंस का काम उप्र देखता है। ढोढ़न बांध निर्माण को लेकर वन विभाग ने अपनी सहमति दे दी है।

वहीं विस्तृत डिजाइन व ड्राइंग के लिए 730 और टेंडर प्रक्रिया के लिए 640 दिन का समय तय किया गया है। यानि 2 साल बाद ही निर्माण कार्य शुरू होगा।

टेंडर की प्रक्रिया के बाद डाइवर्जन नहर की खुदाई का काम शुरू होगा। जिसके लिए 182 दिन का समय तय किया गया है। वहीं कांक्रीट व कॉफर डैम निर्माण के लिए भी 182 दिन का समय लगेगा। इसके बाद परियोजना के मुख्य बांध ढोढ़न का अर्थवर्क शुरू होगा। बांध के फाउंडेशन कार्य में ही 1917 दिन यानि 5 साल का समय लगेगा। वहीं बांध का कांक्रीट वाला हिस्सा निर्माण करने के लिए 2098 दिन यानि इसमें भी 5 साल से ज्यादा का समय लगेगा। सबसे अंत में पावर हाउस का कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। जिसके निर्माण में 912 दिन का समय लगेगा। इस तरह से मुख्य बांध का संपूर्ण निर्माण कार्य 8 साल में पूरा होगा।

परियोजना के मुख्य बांध ढोढ़न में पन्ना टाइगर रिजर्व की 6017 हेक्टेयर वन भूमि डूब रही है, जिसमें कोर एरिया की 4141 हेक्टेयर भूमि शामिल है। इसकी भरपाई के लिए प्लान तैयार किया गया है। इस प्लान के तहत पन्ना और छतरपुर जिले के गांव कटहरी-बिल्हारा, कोनी, मझौली, गहदरा, मरहा, खमरी, कूडन, पाठापुर, नैगुवां, डुंगरिया, कदवारा, घुघरी, बसुधा की 4396 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। ये गांव पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित है, जिसे अब कोर एरिया में परिवर्तित किया जाएगा। इसके अलावा 1621 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में 3242 हेक्टेयर राजस्व जमीन छतरपुर जिले में चिन्हित की गई है। इस भूमि पर वनीकरण किया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बनाए गए प्रारंभिक डीपीआर के मुताबिक 637 कच्चे घर, 1252 आधे कच्चे-पक्के मकान, और 24 पक्के मकान डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। प्रभावित घरों के मालिकों को पक्के मकान के बदले डेढ लाख, आधा कच्चा-पक्का मकान का एक लाख और कच्चा मकान का 50 हजार रुपए मुआवजा दिया जाएगा। 10 गांव के डूब क्षेत्र में जाने से न केवल वहां के लोग बल्कि पालतू मवेशी भी प्रभावित होंगे। 9317 गाय, 249 भैंसा, 3387 भैंसे, 345 भेड़, 11957 बकरी, 1378 मुर्गा-मुर्गी और 1952 अन्य पालतू जानवर भी प्रभावित हो रहे हैं।

● **सिद्धार्थ पांडे**

5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की बिसात बिछ गई है, जिसके नतीजे निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करेंगे, लेकिन इन चुनावों को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल नहीं कहा जा सकता है। निश्चित रूप से, इन चुनावों के नतीजे कई नेताओं के राजनीतिक भविष्य की पटकथा लिखेंगे। इन चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, छग के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तथा तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का भविष्य तय होगा।

● राजेंद्र आगाल

भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 5 राज्यों- मप्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही इन राज्यों में चुनावी बिगुल बज गया है। इन चुनावों के बारे में जैसा कि अक्सर कहा जाता रहा है कि यह अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेताओं का भविष्य तय करेंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि इन चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी भाजपा का चेहरा बने हुए हैं, वहीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी साख दांव पर है। वहीं विपक्ष के नेता जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उनकी भी अग्निपरीक्षा होनी है। ऐसे में ये चुनाव देश के 5 राज्यों के कद्दावर नेताओं की राजनीति का भविष्य तय करेंगे। हार के बाद कई नेताओं की राजनीति ठंडे बस्ते में बंद हो जाएगी, इसका अनुमान अभी से लगाया जा रहा है।

मोदी बनाम मुद्दे का पहला ट्रायल रन हैं ये चुनाव...

5 राज्यों के चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही सभी दल और नेता अपने-अपने दावों, वादों और इरादों के साथ मैदान में डट गए हैं। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों ने भी माहौल बनाना शुरू कर दिया है। इन चुनावों को अगले साल अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। हालांकि, हर चुनाव की परिस्थिति मद्दे और मतदाताओं की मानसिकता अलग-अलग होती है, लेकिन फिर भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव विशेषकर उत्तर भारत के तीनों राज्य मप्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को उन मुद्दों का ट्रायल रन जरूर माना जा सकता है, जिनको धार देकर सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी गठबंधन इंडिया विशेषकर कांग्रेस लोगों के बीच जा रही है, क्योंकि अक्सर जब विपक्षी इंडिया गठबंधन से पूछा जाता है कि अगले लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उसका नेता कौन होगा, तो जवाब आता है कि वो मोदी के मुकाबले मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेंगे। इन चुनावों में भाजपा-कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, इसलिए भाजपा के महिला आरक्षण कानून और कांग्रेस के जातीय जनगणना और पिछड़ा कार्ड की पहली परीक्षा इन विधानसभा चुनावों में ही होगी।

गौरतलब है कि पिछली बार भी लोकसभा चुनाव से पहले इन राज्यों के विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना गया था। मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में कांग्रेस को अच्छी सीटें मिलीं, लेकिन लोकसभा चुनाव में इन राज्यों में नतीजे ठीक इसके विपरीत रहे। दूसरी बात, भाजपा ने किसी भी राज्य में अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और उसने कलेक्टिव लीडरशिप (सामूहिक नेतृत्व) की बात की है, जबकि कांग्रेस के पास तीन राज्यों-मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्रमशः कमलनाथ, भूपेश बघेल और अशोक गहलोत जैसे बहुत स्पष्ट और दमदार चेहरे हैं। तेलंगाना में भी केसीआर बहुत दमदार नेता हैं। विडंबना देखिए, कि जो भाजपा राष्ट्रीय चुनाव में विपक्षी दलों की इस बात के लिए आलोचना करती है कि उनके पास मोदी से मुकाबला करने के लिए चेहरा नहीं है, वहीं विधानसभा चुनाव में सामूहिक नेतृत्व की बात करती है, उसके पास राज्यों में मुकाबले के लिए कोई दमदार चेहरा नहीं है।

मोदी बनाम कांग्रेस

5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चेहरा हैं। ऐसे में इन चुनावों में लड़ाई मोदी बनाम कमलनाथ, मोदी बनाम बघेल, मोदी बनाम गहलोत, मोदी बनाम केसीआर ही होने वाला है। इन विधानसभा चुनावों का परिणाम मिला-जुला हो सकता है। फिलहाल मप्र में कांग्रेस आगे नजर आ रही है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मतदाताओं में भारी आक्रोश है और सबसे ज्यादा सत्ता विरोधी रूझान इस बार सभी क्षेत्रों में विधायकों के खिलाफ है। कांग्रेस के प्रति लोगों में यह सहानुभूति भी है कि उसकी सरकार भाजपा ने गिरा दी थी। छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल की स्थिति बेहतर कही जा सकती है। उन्होंने न केवल पार्टी के अंदरूनी असंतोष को खत्म किया, बल्कि टीएस सिंहदेव को उपमुख्यमंत्री बनाकर सरगुजा संभाग की 14 सीटों पर भी अपनी स्थिति मजबूत बना ली। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में उन्होंने नरवा, गरुवा, घुरवा बाड़ी योजना के जरिए विकास का जो मॉडल पेश किया, उससे लोग खुश हैं। इसमें कई योजनाएं हैं, जो लोगों द्वारा पसंद की गई हैं। सरकार द्वारा गोबर खरीदने की योजना से महिलाओं की जिंदगी पर असर पड़ा है और उनके हाथों में पैसा आया है।

अपनी कद्दावर छवि, ग्रामीण जनता से संपर्क, महिलाओं का भरोसा और संस्कृति से जुड़ाव के साथ-साथ बघेल के पक्ष में एक यह बात भी जाती है कि उनके सामने कोई कद्दावर नेता नहीं है, जो उन्हें चुनौती दे सके। राजस्थान में भी विधायकों के खिलाफ सत्ता विरोधी रूझान है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले वर्षों में जो सामाजिक कल्याण योजनाएं चलाई हैं, उसका असर पड़ा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के हस्तक्षेप के बाद राजस्थान में अब सचिन पायलट भी शांत हो गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या इसका उस हद तक फायदा होगा कि सरकार बनाने लायक सीटें निकाली जा सकें। हालांकि दूसरी तरफ कोई स्पष्ट चेहरा नहीं है।

साख दांव पर

भाजपा का चेहरा राजस्थान में कौन होगा, इसको लेकर चर्चा तो है, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया भाजपा का चेहरा तो नहीं ही होंगी। उसी तरह मप्र में शिवराज सिंह चौहान भाजपा का चेहरा नहीं होंगे। इसका संकेत तो भाजपा हाईकमान ने दे ही दिया है। मप्र में शिवराज सिंह चौहान मेहनत कर रहे हैं और उन्हें टिकट भी मिला है, लेकिन भाजपा नेतृत्व उन्हें वहां चेहरा नहीं बना रहा। उसी तरह छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सामने नहीं आए, जिसकी अपेक्षा की जा रही थी। राज्यों में भाजपा के पास लीडरशिप की कमी है, लेकिन कहा जा रहा है कि अंतिम क्षण में ध्रुवीकरण का खेल खेला जाएगा। पाठकों को याद होगा कि राजस्थान में कन्हैयालाल नामक एक दर्जी की हत्या हुई थी, जिसका हाल में प्रधानमंत्री ने भी अपनी एक सभा में जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उसी दिन से ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में अंदर ही अंदर

ध्रुवीकरण चल रहा है। अब यह किस हद तक काम करेगा और कई चुनौतियों को पार करने वाले अशोक गहलोत इससे कैसे निपटेंगे, यह देखने वाली बात होगी।

पांच-छह महीने पहले तक तेलंगाना में लोग बीआरएस बनाम भाजपा की बात कर रहे थे, लेकिन पिछले दिनों तेलंगाना में बीआरएस बनाम कांग्रेस की बातें हो रही थीं। यानी कांग्रेस ने वहां अपनी जमीन मजबूत की है, तो भाजपा चर्चा से बाहर हो गई है। केसीआर के खिलाफ भी सत्ता विरोधी रूझान है, पर क्या कांग्रेस खुद को इतना मजबूत कर पाएगी कि केसीआर को सत्ता से हटा दे, क्योंकि उन्होंने भी सामाजिक कल्याण योजनाएं खूब चलाई हैं, जिन्हें फ्रीबी कहा जाता है और जिसका जिक्र चुनाव आयोग ने भी किया है। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) की सरकार है, जो एनडीए में शामिल है। लेकिन वहां मुख्य लड़ाई एमएनएफ और कांग्रेस के बीच है, हालांकि एक नई पार्टी जोरम पीपुल्स मूवमेंट का राज्य में प्रवेश हुआ, जो युवाओं को लुभा रहा है। ऐसे में, देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस मिजोरम में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाती है या नहीं। हालांकि मणिपुर की अशांति का मिजोरम के चुनाव पर असर पड़ना लाजिमी है, क्योंकि कुकी जनजाति के बहुत से लोग वहां से भागकर मिजोरम पहुंचे हैं। अब यह देखना भी दिलचस्प होगा कि मणिपुर की घटनाओं का असर इन चुनावों पर कितना पड़ता है।

एक और बात है, विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल आम आदमी पार्टी ने मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पूरे दम-खम के साथ चुनाव लड़ने की बात की है, जो जाहिर है, कांग्रेस के लिए परेशानी पैदा करेगी। इससे इंडिया गठबंधन के भविष्य पर भी असर पड़ सकता है। बहरहाल, विधानसभा चुनावों की बिसात बिछ गई है, जिसके नतीजे निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करेंगे, लेकिन इन चुनावों को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल नहीं कहा जा सकता है। निश्चित रूप से, इन चुनावों के नतीजे कई राजनेताओं के राजनीतिक भविष्य की पटकथा लिखेंगे।

मप्र के चुनावी समीकरण

मप्र में पिछला विधानसभा चुनाव 28 नवंबर 2018 को हुआ था। इस चुनाव के लिए कुल 2,899 उम्मीदवार मैदान में थे। चुनाव आयोग के मुताबिक, प्रति निर्वाचन क्षेत्र में औसतन 12 प्रत्याशी थे। राज्य में मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 3,78,54,811 थी। इनमें से 1,99,94,060 पुरूष, 1,78,60,401 महिलाएं

भितरघात की आशंका

भाजपा और कांग्रेस में टिकट की चाह रखने वाले नेता अपनी ही पार्टी के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। मप्र में भाजपा ने 4 सूचियों के माध्यम से 136 और कांग्रेस ने पहली ही सूची में 144 प्रत्याशियों की घोषणा किया है। लेकिन दोनों पार्टियों में अधिकांश सीटों पर बगावत और असंतोष सामने आने लगा है। हालांकि पार्टियां डैमेज कंट्रोल में जुट गई हैं, लेकिन जिन सीटों पर प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है वहां भितरघात का डर सताने लगा है। गौरतलब है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप के बाद असंतुष्ट नेता ऊपरी तौर पर तो मान जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे घात कर देते हैं। इसलिए टिकट वितरण के बाद भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को भितरघात का डर सताने लगा है। भाजपा और कांग्रेस जैसे दलों में इस तरह के हालात तब हैं, जब दोनों दलों ने जीतने वाले उम्मीदवारों का सर्वे कराया है। सर्वे में अपनी पार्टी नहीं, दूसरी पार्टी के संभावित उम्मीदवारों की भी खोजबीन की गई है। उम्मीदवारों की स्थिति का पूरा आंकलन किया गया है।

2018 में किसी को बहुमत नहीं

केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इन 5 राज्यों में एक राज्य मप्र भी है, जहां इस बार भी भाजपा और कांग्रेस के मध्य ही मुख्य मुकाबला है। पिछला विधानसभा चुनाव 2018 में हुए थे, जिनमें कांग्रेस 114 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में जरूर उभरी थी, लेकिन फिर भी वह बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई थी। कांग्रेस ने सपा, बसपा व निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई थी। भाजपा को उन चुनावों में 109 सीटें मिली थीं। हालांकि, यह भी दिलचस्प था कि भाजपा को 41 प्रतिशत वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 40.9 प्रतिशत मत हासिल हुए थे। राज्य में 15 साल के बाद वर्ष 2018 में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी और कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि उनकी यह सरकार महज 15 महीने ही चल पाई। 2020 की शुरुआत में जब देश में कोरोना पांव पसारने लगा था, उसी दौरान प्रदेश में कांग्रेस सरकार के भी बुरे दिन शुरू हो गए। 2-3 मार्च 2020 की दरमियानी रात अचानक कांग्रेस के ऐंदल सिंह कंसाना, रणवीर जाटव, कमलेश जाटव, रघुराज कंसाना, हरदीप सिंह, बिसाहूलाल सिंह समेत कमलनाथ सरकार को समर्थन दे रहे कुछ अन्य विधायक गुरुग्राम के एक होटल में जमा हुए। उस समय पहली बार लगा कि कांग्रेस सरकार में बगावत की तैयारी हो रही है। तब दिग्विजय सिंह उनके मंत्री बेटे जयवर्धन सिंह, जीतू पटवारी उसी होटल में पहुंचे और बागी विधायकों को मनाकर ले आए। तब लगा कि मामला शांत हो गया, लेकिन फिर सियासी उठापठक तेज हुई और ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के 22 विधायकों ने अचानक बगावत करते हुए बेंगलुरु पहुंचकर डेरा डाल दिया। उधर सिंधिया भी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए और इन विधायकों के इस्तीफे के साथ कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई। कमलनाथ ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया।

और 350 थर्ड जेंडर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। पुरूषों के लिए मतदान 75.84 प्रतिशत, महिलाओं के लिए 74.01 प्रतिशत और कुल मतदान 74.97 प्रतिशत रहा।

मप्र में चुनाव नतीजे 11 दिसंबर 2018 को आए थे। 230 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत से दो कम 114 सीटें मिलीं थीं। वहीं, भाजपा 109 सीटों पर आ गई थी। हालांकि, यह भी दिलचस्प था कि भाजपा को 41 प्रतिशत वोट मिले जबकि कांग्रेस को 40.9 प्रतिशत वोट मिले थे। बसपा को दो जबकि अन्य को पांच सीटें मिलीं। नतीजों के बाद कांग्रेस ने बसपा, सपा और अन्य के साथ मिलकर सरकार बनाई। इस तरह से राज्य में 15 साल बाद कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने।

वहीं अब 2023 मप्र विधानसभा की बात करें तो इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच, राज्य में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया। इसमें करीब 17 लाख मतदाता बढ़े हैं। प्रदेश में सामान्य मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 60 लाख 60 हजार 925 हो गई है। इसमें पुरूष मतदाता 2 करोड़ 88 लाख 25 हजार 607 और महिला मतदाता 2 करोड़ 72 लाख 33 हजार 945 और थर्ड जेंडर 1373 हैं। प्रदेश में कुल 5 करोड़ 61 हजार 36 हजार 229 मतदाता दर्ज हैं। 18-19 साल की उम्र के पहली बार मतदान करने वाले 22 लाख 36 हजार 564 वोटर हो गए हैं, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे। वहीं, 80 या इससे अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 6 लाख 53 हजार 640 है। इसमें 100 वर्ष की उम्र पार करने वाले 5124 मतदाता हैं। इस बार चुनाव में एक हजार पुरूषों पर 945 महिला मतदाता हैं। इस बीच, विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने अब तक 136 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप ने भी अपने 39 प्रत्याशी घोषित किए हैं। वहीं कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है।

पिछले 4 चुनावों का ट्रेंड

2003 से लेकर 2018 के विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा और उम्मीदवारों की सूची की विस्तार से पड़ताल की गई, तो सामने आया कि भाजपा-कांग्रेस दोनों ने श्राद्ध में प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। लेकिन 2023 के चुनाव में यह पहला मौका है जब भाजपा ने पितृपक्ष में अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। लेकिन चुनाव आयोग जरूर 2023 की तरह 2018 में श्राद्ध के दौरान जरूर चुनाव की घोषणा कर चुका है। चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि आयोग को श्राद्धपक्ष से कोई लेना देना नहीं होता है। आयोग का फोकस सिर्फ चुनाव की तैयारियों पर होता है। राज्यों में चुनाव संबंधी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, इसलिए आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी। पिछले चार विधानसभा चुनावों में आचार संहिता लगने के ट्रेंड को देखें, तो सामने आता है कि 2018 के चुनाव को छोड़कर बाकी के 2013, 2008 और 2003 के चुनावों की आचार संहिता श्राद्धपक्ष के बाद लगी है। इन तीनों ही चुनावों में भाजपा को जबरदस्त जीत हासिल हुई थी। जबकि 2018 के चुनावों में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा था। अब सबकी निगाहें एक बार फिर 2023 के चुनाव पर हैं। क्योंकि 2018 की तरह इस बार भी आचार संहिता श्राद्धपक्ष (9 अक्टूबर) में लगी है। इस साल 29 सितंबर से शुरू हुआ पितृपक्ष 14 अक्टूबर तक चलेगा। राज्य में मतदान 17 नवंबर को होगा। जबकि मतगणना 3 दिसंबर को होगी।

राजस्थान के चुनावी समीकरण

राजस्थान में पिछला विधानसभा चुनाव 28 नवंबर 2018 को संपन्न हुआ था। इस चुनाव के लिए कुल 2,294 उम्मीदवार मैदान में थे। राज्य में प्रति निर्वाचन क्षेत्र में औसतन 11 प्रत्याशी मैदान में थे। मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 3,53,90,876 थी। इनमें से 1,83,44,351 पुरूष, 1,70,46,450 महिलाएं और 75 थर्ड जेंडर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। पुरूषों के लिए मतदान 73.49 प्रतिशत, महिलाओं के लिए 74.67 प्रतिशत और कुल मतदान 74.06 प्रतिशत रहा। राज्य में चुनाव नतीजे 11 दिसंबर 2018 को घोषित किए गए थे। अलवर की रामगढ़ सीट छोड़कर बाकी 199 सीटों पर मतदान हुआ। रामगढ़ सीट पर बसपा के प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह के निधन के कारण चुनाव स्थगित हो गया था। इस चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को पटखनी देते हुए 99 सीटें जीतीं। इसके साथ ही प्रदेश में हर पांच साल में सत्ता परिवर्तन का रिवाज कायम रहा। भाजपा को 73, मायावती की पार्टी बसपा को छह तो अन्य को 20 सीटें मिलीं। कांग्रेस को बहुमत के लिए 101 विधायकों की जरूरत थी। कांग्रेस ने निर्दलियों और अन्य की मदद से जरूरी आंकड़ा जुटा लिया। इसके साथ ही कांग्रेस ने राज्य की सत्ता में वापसी की और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने।

अब 2023 राजस्थान विधानसभा की बात करें तो इसको लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इस बीच, राज्य में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया। अंतिम सूची के अनुसार प्रदेश में 5 करोड़ 26 लाख 80 हजार 545 मतदाता पंजीकृत किए गए हैं। इनमें से 2 करोड़ 73 लाख 58 हजार 627 पुरूष और 2 करोड़ 51 लाख 79 हजार 422 महिला मतदाता शामिल हैं। मतदाता सूची में 80 साल से अधिक आयु के 11.78 लाख मतदाता और 100 वर्ष से अधिक आयु के 17,241 मतदाता पंजीकृत हैं। 5.61 लाख विशेष योग्यजन मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इन मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। इसी प्रकार 606 ट्रांसजेंडर मतदाता भी पंजीकृत हैं। प्रदेश के मतदान केंद्र की बात करें तो 601 मतदान केंद्र नए बनाए गए हैं और 32 मतदान केंद्रों का समायोजन किया गया है। 569 मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं। मतदान केंद्र की संख्या 51 हजार 187 से बढ़कर 51 हजार 756 हो गई है।

छत्तीसगढ़ के चुनावी समीकरण

छत्तीसगढ़ में पिछला विधानसभा चुनाव दो चरणों में कराया गया था। इस चुनाव के लिए कुल 1,269 उम्मीदवार मैदान में थे। राज्य में प्रति निर्वाचन क्षेत्र में औसतन 14 प्रत्याशी मैदान में थे। मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 1,42,11,333 थी। इनमें से 71,36,626 पुरूष, 70,74,636 महिलाएं और 191 थर्ड जेंडर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। पुरूषों के लिए मतदान 76.58 प्रतिशत, महिलाओं के लिए 76.33 प्रतिशत और कुल मतदान 76.45 प्रतिशत रहा।

2018 में राज्य में दो चरणों में मतदान कराए गए थे। पहले चरण का मतदान 12 नवंबर 2018 और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर 2018 को संपन्न हुआ था। छत्तीसगढ़ के चुनाव नतीजे 11 दिसंबर को आए थे। चुनाव नतीजे आए तो 90 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 68 और भाजपा को 15 सीटें मिलीं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने पांच सीटें जीती थीं और दो सीटें बसपा के खाते में गई थीं।

अब 2023 राजस्थान विधानसभा की बात करें तो इसको लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इस बीच, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन जारी कर दिया है। सूची के अनुसार राज्य में कुल 2 करोड़ 3 लाख 60 हजार 240 मतदाता हैं। इनमें 1 करोड़ 1 लाख 20 हजार 830 पुरूष मतदाता, 1 करोड़ 2 लाख 39 हजार 410 महिला मतदाता और 790 ट्रांस जेंडर मतदाता शामिल हैं।

तेलंगाना के चुनावी समीकरण

तेलंगाना में पिछले चुनाव 7 दिसंबर 2018 को हुए थे। इस चुनाव के लिए कुल 1,821 उम्मीदवार मैदान में थे। राज्य में प्रति निर्वाचन क्षेत्र में औसतन 15 प्रत्याशी मैदान में थे। मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 2,05,99,739 थी। इनमें से 1,03,28,078 पुरूष, 1,02,71,470 महिलाएं और 191 थर्ड जेंडर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। पुरूषों के लिए मतदान 72.90 प्रतिशत, महिलाओं के लिए 73.86 प्रतिशत और कुल मतदान 73.37 प्रतिशत रहा। मतदान केंद्रों की संख्या 32,814 थी। 2018 में राज्य में 7 दिसंबर 2018 को चुनाव संपन्न हुआ था। तेलंगाना के चुनाव नतीजे 11 दिसंबर को आए थे। इस चुनाव में 119 सदस्यीय विधानसभा में बीआरएस को 88, कांग्रेस को 19, आईएमआईएम को 7, टीडीपी को 2, भाजपा को 1, एआईएफबी को 1 सीट मिली थी। इसके अलावा एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली थी।

इस बीच चुनाव आयोग द्वारा राज्य के लिए अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। यहां 3.17 करोड़ से अधिक मतदाताओं में से पुरूष और महिला मतदाता क्रमशः 1,58,71,493 और 1,58,43,339 हैं, जबकि 2,557 तीसरे लिंग के हैं। इस वर्ष की शुरुआत में 17,42,470 मतदाताओं की वृद्धि के साथ राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

मिजोरम के चुनावी समीकरण

मिजोरम में पिछले चुनाव 28 नवंबर 2018 को हुए थे। इस चुनाव के लिए कुल 209 उम्मीदवार मैदान में थे। राज्य में प्रति निर्वाचन क्षेत्र में औसतन 5 प्रत्याशी मैदान में थे। मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 6,20,008 थी। इनमें से 2,99,746 पुरूष और 3,20,262 महिलाओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। पुरूषों के लिए मतदान 78.92 प्रतिशत, महिलाओं के लिए 81.09 प्रतिशत और कुल मतदान 80.03 प्रतिशत रहा। मतदान केंद्रों की संख्या 1,170 थी। पिछले चुनाव 28 नवंबर 2018 को हुए थे। इस चुनाव में 40 सदस्यीय विधानसभा में एमएनएफ को 27 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने 4 सीटें, जबकि भाजपा को 1 सीट पर विजय मिली थी। इसके अलावा 8 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत मिली थी। इसके साथ ही राज्य में मुख्यमंत्री जोरमथंगा के नेतृत्व में एमएनएफ की सरकार बनी थी।

इस बीच चुनाव आयोग द्वारा राज्य के लिए अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। यहां 8,51,895 मतदाताओं में से पुरूष और महिला मतदाता क्रमशः 4,12,969 और 4,38,925 हैं, जबकि एक तीसरे लिंग के हैं। वहीं 4,884 पुरूष और 89 महिला सर्विस वोटर हैं, जिनमें कुल 4,973 सेवा मतदाता हैं। मिजोरम में इस बार 1,276 मतदान केंद्र हैं।

नवरात्रि में आएगा पार्टी का घोषणा पत्र

भाजपा और कांग्रेस का घोषणा पत्र नवरात्रि में आएगा। पितृपक्ष के चलते ही भाजपा ने घोषणा पत्र को टाल दिया है। पहले पार्टी की ये तैयारी थी कि चुनाव की घोषणा होने के 48 घंटे बाद ही घोषणा पत्र का ऐलान किया जाएगा, लेकिन ज्योतिषियों की राय पर पार्टी ने ये फैसला आगे बढ़ा लिया है। संभवतः अब भाजपा नवरात्रि में ही पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेगी। नवरात्रि में घोषणा पत्र जारी करने को भी पार्टी एक बड़ा इवेंट बना सकती है। इसमें भाजपा ये बताएगी कि कैसे उनकी सरकार ने महिलाओं और बेटियों की बेहतरी के लिए काम किया है। आमतौर पर भाजपा ने कभी भी कोई शुभ काम पितृपक्ष में नहीं किया। ताजा उदाहरण देखें तो नई संसद में कार्यकाल भी गणेश चतुर्थी के दिन शुरू किया गया। भाजपा के बड़े नेता इस बात का जिक्र भी अपनी सभाओं में करते हैं। मगर इस बार तो शिवराज सरकार ने एक ही दिन में 53 हजार करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन एक ही दिन में कर दिया। इसे लेकर भाजपा के पास कोई खास जवाब भी नहीं था। यहां तक कि महाकाल कॉरिडोर दो का उद्घाटन भी हो गया।

भारत में बढ़ी भूखमरी

हाल ही में 116 देशों के लिए जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 101वें पायदान पर रखा गया है, जो स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि देश में भुखमरी की स्थिति कितनी गंभीर है। स्थिति यह है कि भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान (92), बांग्लादेश (76) और नेपाल (76) से भी पीछे है। गौरतलब है कि 2020 के लिए जारी हंगर इंडेक्स में भारत को 94वें स्थान पर रखा गया था। यह इंडेक्स 14 अक्टूबर, 2021 को कंसर्न वर्ल्डवाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा प्रकाशित किया गया था। यदि इस इंडेक्स को देखें तो जहां 2020 की तुलना में बाल मृत्यु दर के मामले में 2021 के दौरान देश की स्थिति में सुधार आया है। वहीं चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग के मामले में स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस इंडेक्स में केवल 15 देशों की स्थिति भारत से बदतर बताई गई है। इनमें पापुआ न्यू गिनी (102), अफगानिस्तान (103), नाइजीरिया (103), कांगो (105), मोजाम्बिक (106), सिएरा लियोन (106), तिमोर-लेस्ते (108), हैती (109), लाइबेरिया (110) शामिल हैं। वहीं मेडागास्कर (111), कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (112), चाड (113), मध्य अफ्रीकी गणराज्य (114), यमन (115) और सोमालिया को सबसे अंतिम 116वें पायदान पर रखा गया है।

हालांकि देश में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए टिप्पणी की है कि यह चौंकाने वाला है कि ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2021 ने कुपोषित आबादी के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुमानों के आधार पर भारत को निचले पायदान पर स्थान दिया है, जो तथ्यात्मक आधार के बजाय एक गंभीर प्रणालीगत समस्या है। वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट को प्रकाशित करने से पहले पब्लिशिंग हाउस कंसर्न वर्ल्डवाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ ने सही काम नहीं किया है। सरकार के अनुसार एफएओ द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विधि अवैज्ञानिक है। उन्होंने गैलप द्वारा फोन पर किए गए फोर क्वेश्चन पोल के परिणामों का मूल्यांकन किया है। इस अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति भोजन की उपलब्धता जैसे कुपोषण को मापने के लिए किसी वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग नहीं किया गया है। जबकि कुपोषण की माप के लिए वजन और ऊंचाई संबंधी माप की आवश्यकता होती है, यहां शामिल विधि पूरी तरह से आबादी के एक टेलीफोन अनुमान, गैलप पोल पर आधारित है।

यही नहीं इस रिपोर्ट में कोविड काल के दौरान पूरी आबादी की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयासों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है, जिस पर सत्यापित आंकड़े उपलब्ध हैं। सर्वेक्षण के उत्तरदाताओं के पास ऐसा कोई प्रश्न नहीं था कि उन्हें सरकार या अन्य स्रोतों से क्या खाद्य सहायता मिली या नहीं। इस पोल में प्रतिनिधित्व भारत और अन्य देशों के लिए भी संदिग्ध है। इससे पहले ऑक्सफेम द्वारा जारी रिपोर्ट द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज में भी वैश्विक स्तर पर भुखमरी की समस्या पर चिंता जताई थी, जिसके अनुसार दुनियाभर में हर मिनट करीब 11 लोग भूख के कारण दम तोड़ रहे हैं। करीब 15.5 करोड़ लोग गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में भी भारत को एक हंगर हॉटस्पॉट के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यदि 2020 के आंकड़ों को देखें तो भारत में करीब 19 करोड़ लोग कुपोषण का शिकार हैं। वहीं पांच वर्ष से कम उम्र के करीब एक तिहाई बच्चों का विकास ठीक से नहीं हो रहा है।

दुख की बात तो यह है जहां एक तरफ सरकार इस समस्या को लेकर गंभीर नहीं है वहीं लोग भी अपनी आदतों में बदलाव नहीं कर रहे हैं। अनुमान है कि देश में हर व्यक्ति प्रतिवर्ष करीब 50 किलोग्राम भोजन बर्बाद कर देता है, जबकि विडंबना देखिए की 18.9 करोड़ लोगों (14 फीसदी आबादी) को आज भी पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में हर वर्ष करीब 6.88 करोड़ टन भोजन बर्बाद कर दिया जाता है। इस बर्बादी को रोकना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस इसके लिए हमें अपनी आदत बदलनी होगी। अपनी प्लेट में उतना ही भोजन लें जितना हम खा सकते हैं। उतना ही खरीदें जितना हमारे लिए पर्याप्त है। बेवजह खाद्य पदार्थों को जमा करना बंद कर दें। भोजन के महत्व को समझें। यह इंसान के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। अगली बार जब भी अपनी थाली में खाना बाकी छोड़ें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि कहीं इसी खाने की वजह से कोई भूखा सोने को मजबूर है।

गौरतलब है कि आबादी के मामले में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट कहती है, भारत की आबादी बढ़कर 142.86 करोड़ पहुंच गई और 142.57 करोड़ जनसंख्या के साथ चीन दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। इस तरह भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी का वाला देश बन गया है। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव पूनम मुतरेजा का कहना है कि भारत जैसी आबादी वाले देश में बढ़ती जनसंख्या भविष्य में खुशहाल और स्वस्थ जीवन के लिए कई चुनौतियां पैदा करेगी।

● **विकास दुबे**

20 साल में 1 करोड़ भारतीयों ने छोड़ा देश

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज की प्रोफेसर अपराजिता चट्टोपाध्याय का कहना है कि अगर आबादी के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट का दायरा नहीं बढ़ा तो बेरोजगारी और बढ़ेगी। इससे इस बात को समझा जा सकता है कि हर 4 में से 3 भारतीय विदेश का रुख कर रहा है। दूसरे विकासशील देशों के मुकाबले यह आंकड़ा कहीं ज्यादा है। 2000 से लेकर 2020 तक करीब 1 करोड़ भारतीयों ने भारत छोड़ दिया। बेरोजगारी दर के आंकड़ों पर नजर डालें तो इसमें बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव नहीं दिखा है। पिछले साल बेरोजगारी 8.30 फीसदी हो गई थी। सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) की रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी में यह घटकर 7.14 फीसदी, फरवरी में 7.45 फीसदी और मार्च में 7.8 फीसदी तक पहुंच गई। आबादी यूं ही बढ़ती रही तो रोजगार मिलना मुश्किल और चुनौतीभरा हो जाएगा। भारत की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा युवाओं का है। यहां 55 फीसदी ऐसे युवा हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। एक चौथाई ऐसे युवा हैं जिनकी उम्र 15 साल से भी कम है। 55 फीसदी युवाओं की आबादी ही तेजी से बढ़ती जनसंख्या की सबसे बड़ी वजह है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। इसकी एक वजह यह भी है कि यहां पर फैमिली प्लानिंग के तरीकों को उतने प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है, जितना आबादी को देखते हुए होना चाहिए।

आरक्षण बनाम जनगणना की पहली परीक्षा

लोकसभा के चुनाव अप्रैल-मई 2024 में होने हैं, लेकिन बिसात अभी से बिछ रही है। इसी साल नवंबर में होने वाले मप्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा के चुनावों को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने ऐसी तैयारी शुरू कर दी है, मानों ये चुनाव लोकसभा के चुनाव हों। मीडिया में भी वैसी ही हलचल है। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों की बाढ़ है और दलों की रणनीति भी उसी हिसाब से लगातार बदल रही है।

कर्नाटक के उलट भाजपा ने मप्र में अब तक 4 सूचियां जारी कर 136 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कई नाम सामने आ चुके हैं। उधर, कांग्रेस ने अभी पहली सूची जारी कर 144 लोगों को टिकट दिया है। दोनों पार्टियों में बगावत के सुर उठ रहे हैं, इससे अन्य सीटों पर माथापच्ची हो रही है। उधर, जातिगत सर्वे का मुद्दा उठाकर विपक्ष को लगता है कि उन्होंने बढ़त हासिल कर ली। पर राजनीति में जातियों का वोटिंग पैटर्न इतना जिग जैग है कि इतनी आसानी से रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता।

आम तौर पर ज्यादातर चुनावों में एक बड़ा चेहरा उतार कर कांग्रेस से उसका चेहरा पूछने वाली भाजपा इस बार मप्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सामूहिक नेतृत्व के नारे के साथ चुनाव में उतरेगी, जबकि कांग्रेस तीनों राज्यों में कमलनाथ, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के मुकाबले में भाजपा से उसके चेहरों के नाम पूछेगी। इसी बीच बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने राज्य की जातिवार जनगणना के आंकड़े जारी करके राजनीति को एक नया आयाम दे दिया है। बिहार सरकार के इस कदम से जातीय जनगणना कराने का दबाव केंद्र सरकार पर बढ़ गया है और विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव आदि अपने पिछड़े कार्ड के साथ मैदान में उतर आए हैं।

भाजपा अगर हिंदुत्व और महिला आरक्षण कानून को मुद्दा बना रही है तो विपक्ष जातीय जनगणना और पिछड़ों के आरक्षण के मुद्दे को हवा दे रहा है। विपक्ष के इस दांव के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हिंदुओं को बांटने और जात-पात की जगह गरीब को उसका हक देने का मुद्दा उठा दिया है। छत्तीसगढ़ की जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर जिसकी जितनी आबादी उसको उतना ही हक की बात करनी है तो सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है तो सबसे ज्यादा हक उन्हें ही मिलना चाहिए। ऐसा करके क्या कांग्रेस अल्पसंख्यकों का हिस्सा खत्म करना चाहती है। अब कौनसा मुद्दा भारी पड़ेगा इसकी पहली परीक्षा नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों में होगी।

आईना दिखा देंगे मप्र-राजस्थान के नतीजे

जाति जनगणना का मुद्दा कितना चलता है, इन मप्र और राजस्थान के चुनाव परिणाम स्पष्ट कर देंगे। दरअसल जातियों का वोटिंग पैटर्न आंकड़ों से नहीं निकलता। न्यूटन के दूसरे और तीसरे नियम यहां भी चलते हैं। मतलब कि कई जातियां मिलकर एक तरफ होती हैं तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी लगता है। सीधे शब्दों में जैसे जाट अगर कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो निश्चित है कि गैर जाटों का वोट भाजपा को जाएगा। यही कारण जातिगत सर्वे के नतीजों का असर नहीं के बराबर होने वाला है। हां राजनीति में ओबीसी जातियों का वर्चस्व पहले से बढ़ रहा है जो अभी भी जारी रहेगा। दोनों राज्यों में कांग्रेस ने ओबीसी कार्ड खेलने के लिए जाति जनगणना कराने का वादा किया है मगर मप्र में उन्होंने एक सवर्ण कैंडिडेट को अपना सीएम कैंडिडेट बनाया हुआ है।

कर्नाटक के उलट भाजपा ने आनन-फानन में तेजी के साथ मप्र में 136 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की 4 सूचियां जारी कर दीं। और छत्तीसगढ़ में भी उसकी पहली सूची सामने आ गई है, जबकि कर्नाटक में भाजपा से काफी पहले आधे से ज्यादा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने वाली कांग्रेस ने हाल ही में 144 नामों की पहली सूची जारी की है और अभी सभी राज्यों में माथापच्ची कर रही है। भाजपा ने न सिर्फ जल्दी सूची जारी करके बल्कि अपनी दूसरी सूची में तीन केंद्रीय मंत्रियों, सात सांसदों और एक राष्ट्रीय महासचिव समेत आठ सीटों पर जिस तरह बड़े नेताओं को उतारकर सबको चौंका दिया है, उसे लेकर अलग-अलग राय है।

एक राय है कि मप्र को लेकर भाजपा बहुत आश्वस्त नहीं है, इसलिए उसने उन सीटों पर जो उसकी सबसे कमजोर सीटें हैं। अपने दिग्गज उतारकर उनको जिताने की रणनीति बनाई है। दूसरी राय है कि भाजपा ने यह कदम घबराकर अपने बचाव में उतारा है कि इससे सामने वाले पर दबाव बनेगा। जबकि लड़ाई में जो घबराता है उसका नुकसान होता है। एक अन्य राय है कि ऐसा करके भाजपा ने मप्र की जनता को यह संदेश दिया है कि पार्टी इस बार वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के बिना सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी और अगर सरकार बनी तो कोई अन्य मुख्यमंत्री हो सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री पद के तीन बड़े दावेदार नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल को मैदान में उतारकर उनके क्षेत्र की जनता और समर्थकों को यह संदेश दिया है कि उनका नेता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। इनसे इतर एक राय यह भी है कि पार्टी नेतृत्व ने मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को चुनाव मैदान में उतारकर उनकी हैसियत का इम्तिहान भी लिया है कि मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे आने के लिए उन्हें यह चुनावी अग्निपरीक्षा देनी होगी।

भाजपा की यह रणनीति कितनी कामयाब होगी इसे लेकर भी राय बंटी हुई है। कुछ विश्लेषक इसे भाजपा का मास्टर स्ट्रोक बताते हैं जबकि इसके उलट इसे डिसास्टर स्ट्रोक भी

मप्र में ओबीसी फैक्टर

मप्र विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस जातिगत जनगणना का मुद्दा जोर-शोर से उठा रही है। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग भाजपा की ताकत रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार प्रदेश की 50.9 प्रतिशत आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग की है। चंबल-ग्वालियर और बुंदेलखंड सहित मालवा, भोपाल में पिछड़ी जातियों के गढ़ हैं। भाजपा ने 2003 के चुनाव में जब उमा भारती पर दांव लोधी वोटों को ध्यान में रखकर ही लगाया था। उमा भारती मुख्यमंत्री बनीं, बाद में बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के साथ पिछड़े वर्गों के मुख्यमंत्रियों ने भाजपा की पहचान पिछड़ी जाति के पार्टी के रूप में बना दी। कांग्रेस भाजपा से ओबीसी को तोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। ओबीसी नेता पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को चुनाव अभियान समिति का सह अध्यक्ष बनाकर उनका कद बढ़ाया। विंध्य अंचल से आने वाले कमलेश्वर पटेल को राष्ट्रीय कार्यसमिति में स्थान दिया। पटेल को विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी समितियों में स्थान देकर ओबीसी वर्ग को खुश करने का संदेश दे दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से विवादों के बाद पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव किनारे लगा दिए गए थे। पर अब मुख्यधारा में उनकी वापसी हो गई है। ओबीसी नेता राजमणि पटेल को राज्यसभा भेजना भी इसी रणनीति का एक कदम था। कांग्रेस यह भी कहती है कि कमलनाथ सरकार ने ही नौकरियों में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया था। हालांकि कोर्ट में मामला फंस जाने से लागू नहीं हो सका। भाजपा सत्ता में आई और 27 प्रतिशत आरक्षण देने के आदेश भी जारी हो गए पर मामला अभी भी उलझा हुआ है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उसने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई?

कहा जा रहा है। रणनीति के समर्थकों का कहना है कि दिग्गजों को मैदान में उतारकर भाजपा ने सामूहिक नेतृत्व की बात को यथार्थ में बदल दिया है। इससे शिवराज सिंह को लेकर पिछले 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो अरुचि में बदल गई है, उससे निपटने में मदद मिलेगी और साथ ही मप्र में भाजपा का नया नेतृत्व भी विकसित हो सकेगा। फिर शिवराज की जगह मोदी का चेहरा सामने रहने से पार्टी को चुनावी फायदे की उम्मीद ज्यादा है, लेकिन इस रणनीति को डिसास्टर स्ट्रोक बताने वाले कहते हैं कि इससे एक तरफ तो भाजपा की निराशा और हताशा सामने आ गई है दूसरी तरफ जो बड़े नेता घूम-घूमकर पार्टी उम्मीदवारों की जीत का रास्ता आसान कर सकते थे, उन्हे खुद चुनाव में फंसाकर पार्टी ने अपना नुकसान कर लिया है। दूसरे इन सीटों पर जहां दिग्गजों को उतारा गया है वहां जो स्थानीय नेता टिकट के दावेदार थे, उनके विरोध और असंतोष का सामना भी इन दिग्गजों को करना पड़ेगा। फिर शिवराज सिंह जिन्होंने 15 साल से ज्यादा वक्त तक राज्य पर शासन किया है, उन्होंने अपना एक निजी जनाधार वर्ग भी तैयार किया है। सामूहिक नेतृत्व के नाम पर शिवराज की अनदेखी इस समूह को नाराज कर सकती है, जिसका भाजपा को नुकसान हो सकता है।

अब बात राजस्थान की जहां पिछले कई चुनावों से हर पांच साल में सरकार बदलने का रिवाज रहा है। भाजपा को इस रिवाज पर बेहद भरोसा है जबकि कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा। कहा जा रहा है कि यहां भी दिग्गजों को मैदान में उतारकर कांग्रेस को बचाव की मुद्रा में लाने की रणनीति है। लेकिन जैसे मप्र में शिवराज सिंह चौहान का पेंच फंसा है, वैसे ही यहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर भी भारी उहापोह है। शिवराज की ही तरह राजस्थान में भाजपा में वसुंधरा अकेली नेता हैं जिनकी पहचान और लोकप्रियता पूरे राजस्थान में है। कहा जाता है कि 40 से 50 सीटों पर वसुंधरा का अपना निजी असर है और उनकी अनदेखी व नाराजगी भाजपा को भारी पड़ सकती है। इसके बावजूद केंद्रीय नेतृत्व ने मप्र की ही तर्ज पर यहां भी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। यह दुधारी तलवार है जो दोनों तरफ मार कर सकती है। यहां भी भाजपा मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी।

उधर, कांग्रेस जो पिछले कई महीनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट की जंग से जूझ रही थी अब फौरी तौर पर उस पर काबू पा चुकी है। चुनाव पूरी तरह अशोक गहलोत के चेहरे और नेतृत्व पर ही लड़ा जाएगा। पिछले करीब एक साल से गहलोत सरकार की लोकलुभावन योजनाओं का जमीन पर पड़ने वाले असर को कांग्रेस अपनी ताकत मान रही है और इसी आधार पर राज्य में अपनी सरकार की वापसी का दावा भी कर रही है। चुनाव पूर्व सर्वेक्षण भी बता रहे हैं कि तीन महीने पहले कांग्रेस भाजपा से खासी पीछे थी, अब लगभग मुकाबले पर आ गई है और भाजपा उससे थोड़ा ही आगे है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भूपेश बघेल के नेतृत्व में पूरी तरह अपनी सरकार दोबारा बनाने के लिए आश्वस्त है। भाजपा नेता भी दबी जुबान से स्वीकारते हैं कि राज्य में उनकी सीटें तो बढ़ेंगी लेकिन कोई स्थानीय नेतृत्व न होने के कारण बघेल को चुनौती नहीं दी जा पा रही है और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा।

सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबरें दक्षिणी राज्य तेलंगाना से आ रही हैं। यहां मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली टीआरएस जो अब बीआरएस हो गई है, उसे सबसे कड़ी चुनौती कांग्रेस से मिल रही है। जबकि 2019 के लोकसभा चुनावों और विधानसभा चुनावों में भाजपा ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी, लेकिन कर्नाटक चुनावों में कांग्रेस की जीत के बाद तेलंगाना का माहौल बदल गया है। वहां राज्य की बीआरएस सरकार के खिलाफ जो रुझान है वो भाजपा की बजाय कांग्रेस की तरफ मुड़ता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद अल्पसंख्यक मतदाता जो टीआरएस का बड़ा जनाधार थे, कांग्रेस की तरफ एकमुश्त आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले को लेकर जब से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी और सांसद कविता से पूछताछ की है। चंद्रशेखर राव ने खुद को विपक्षी खेमेबंदी से दूर कर लिया और केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना भी लगभग बंद कर दिया। इससे राज्य में बीआरएस और भाजपा के बीच अंदरूनी दोस्ती का संदेश तेजी से गया है और बीआरएस विरोधी मतदाता भाजपा से दूर होने लगे हैं।

● **विपिन कंधारी**

5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। इन चुनावों को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। लेकिन इस सेमीफाइनल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा होनी है, क्योंकि भाजपा उन्हें अपराजेय मान रही है। अब देखना यह है कि क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपराजेय हैं या भाजपा अति विश्वास में है।

क्या अपराजेय रहेंगे मोदी...!

लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम पूरे जी-जान से लगे हैं। राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि ये मोदी के लिए अंतिम बड़ा चुनाव है। जीते तो भी, और हारे तो भी। अपनी छवि को बेदाग रखने की कोशिशों के साथ आगामी चुनावों की जीत में लगे प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार में अपने सभी विश्वसनीयों को हमेशा की तरह लगा दिया है। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, तो मोदी सरकार की छवि प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रियों के तमाम दावों के बाद भी बेदाग नहीं बन सकी है। हाल ही में आई केंद्रीय सतर्कता आयोग (कैग) की कुछ रिपोर्ट्स ने कई मंत्रालयों के काले चिट्ठे खोल दिए और मोदी सरकार की छवि चमकाने की कोशिशों पर पानी फिर गया।

भ्रष्टाचार की सबसे अधिक शिकायतें प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीबी अमित शाह के गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ थीं। केंद्र सरकार के विभागों और संगठनों में सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ वर्ष 2022 में ही कुल 1,15,203 शिकायतें आईं, जिनमें अकेले गृह मंत्रालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ 46,643 शिकायतें मिलीं। हालांकि केंद्र सरकार ने कैग की रिपोर्ट को अनदेखा किया है, वहीं केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने सड़क घोटाले के आरोप को नकार दिया है। मगर मोदी सरकार किसी भी हाल में अपनी नाकामियों और आरोपों को छिपाते हुए अपने शासन में हुए बड़े कामों के सहारे जनता के बीच उतरना चाहती है। मोदी सरकार यह जानती है कि अगर एक ओर उसकी कुछ उपलब्धियां हैं, तो दूसरी ओर उसकी कमजोरियां भी इन उपलब्धियों से कहीं ज्यादा हैं। यही वजह है कि उसे जल्दबाजी में महिला आरक्षण विधेयक विशेष सत्र बुलाकर संसद के दोनों सदनों में पास कराना पड़ा। लोकसभा चुनाव 2024 और उससे पहले पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में जीत के लिए भाजपा मेगा प्लान तैयार कर चुकी है। राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा दबाव उन राज्यों के प्रभारियों पर होगा, जहां भाजपा की स्थिति कमजोर है। जिस राज्य में स्थिति जितनी ज्यादा कमजोर होगी, उस राज्य के नेताओं पर उतना ही जीत का दबाव प्रधानमंत्री मोदी का होगा। जानकार कह रहे हैं कि भाजपा ने पहली बार पार्टी के कामकाज को उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के हिसाब से तीन हिस्सों में बांटा है, ताकि सरलता से जीत मिल सके। परंतु इस बार की जीत उसके लिए इतनी आसान नहीं है। लेकिन भाजपा की ओर से दावा किया जा चुका है कि तीसरी बार भी केंद्र में भाजपा आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे।

आगामी सभी चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई बड़े नेता और मंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं। जनता के बीच जाने का सिलसिला भी जारी हो चुका है। आरोप हैं कि विपक्षी दलों को बदनाम करने, आरोपित करने और विपक्ष के मजबूत नेताओं, सांसदों, विधायकों को डराने-धमकाने का काम भाजपा अंदर-ही-अंदर कर रही है। परंतु भाजपा के गिरते वोट बैंक को वापस लाने की कोशिश में भाजपा नेता जितनी शिद्दत से लगे हैं, उतनी ही शिद्दत इस आखिरी बड़ी जीत के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी लग गया है। लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख

मोदी के चेहरे पर ऐसा दांव क्यों?

यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा तो इन चुनावों में हार-जीत की जिम्मेदारी किसकी होगी? यदि जीत हुई तब तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन यदि हार हुई तो इसका मोदी की छवि पर क्या असर पड़ेगा? इसका असर लोकसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है। जिस समय यह अनुमान लगाया जा रहा है कि राजस्थान को छोड़कर इन सभी राज्यों में भाजपा के लिए परिस्थिति बहुत अनुकूल नहीं है, उस समय भाजपा ने मोदी के चेहरे पर ऐसा दांव क्यों खेला? जबकि कोई विपरीत परिणाम आने पर इंडिया गठबंधन इसे मजबूती से उछालने की कोशिश अवश्य करेगा, यह माना जा सकता है। विशेषकर यह देखते हुए कि कर्नाटक में भी यही रणनीति अपनाई गई थी। वहां भी येदियुरप्पा जैसे स्थानीय मजबूत चेहरे को किनारे रखकर मोदी के नाम पर ही वोट मांगा गया था। लेकिन पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली। इसके पहले हिमाचल प्रदेश में भी प्रेम कुमार धूमल जैसे मजबूत स्थानीय चेहरों को पीछे रखकर केवल मोदी के चेहरे पर वोट मांगा गया, लेकिन पार्टी जीत हासिल नहीं कर सकी। यदि इन परिणामों को देखने के बाद भी पार्टी ने मोदी को चेहरा बनाने की रणनीति अपनाई है तो यह समझने वाली बात है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया?

मोहन भागवत के द्वारा बैठक करना इसका एक प्रमाण है। लोकसभा चुनाव 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की जीत का आखिरी चुनाव इसलिए कहना उचित है, क्योंकि अमित शाह समेत कई बड़े भाजपा नेता संकेत दे चुके हैं कि 2024 के बाद देश में चुनाव नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी की उम्र को देखकर भी यही माना जा रहा है कि 2024 का चुनाव उनके लिए आखिरी लोकसभा चुनाव होगा। यह इसलिए, क्योंकि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के करीब हो जाएंगे और आगामी लोकसभा चुनाव अब सीधे 2029 में ही होगा और उस समय प्रधानमंत्री मोदी लगभग 80 साल के होंगे। जाहिर है वह 80 साल में चुनाव लड़ना उचित नहीं समझेंगे। आगे क्या होगा, इसकी चिंता छोड़कर भाजपा की पूरी टीम जीत के लिए कोशिशों में जुलाई से ही जुटी हुई है। इसी के मद्देनजर मप्र दौरे के बाद प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर 28 जून को भी हाई लेवल बैठक की थी।

सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में 2023 के आखिर में होने वाले मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई थी। परंतु कुछ जानकार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इस बैठक में राज्यों के विधानसभा चुनावों के अतिरिक्त सभी नेताओं को 2024 के लोकसभा चुनावों में जीत की तैयारी में जी-जान से जुट जाने का आदेश दिया है। जिन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उनमें गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा के संगठन मंत्री बीएल संतोष जैसे कद्दावर नेता हैं। जानकारों के मुताबिक, अगर जरूरत पड़ी, तो मोदी चुनावी तैयारियों के लिए संगठन में फेरबदल करने के मूड में हैं। संगठन में कई बदलाव होने के अतिरिक्त मंत्रिमंडल में भी चुनाव से पहले फेरबदल के संकेत हैं। राजनीति के कुछ जानकार प्रधानमंत्री मोदी और उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में मनमुटाव के दावे भी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनने की चाह रखते हैं। परंतु भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की जोड़ी उन्हें आगे आता नहीं देखना चाहती है।

स्पष्ट है कि अगर कोई दूसरा चेहरा प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करता है, तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह एक बड़े झटके की तरह होगा। हालांकि अभी तक भाजपा में किसी भी नेता की यह हिम्मत नहीं हुई है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा के बिना चुनाव मैदान में उतर सके। इसलिए भाजपा ने दावा किया है कि मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर यह दावा सही साबित हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले गैर-कांग्रेसी नेता होंगे, जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। परंतु मोदी के लिए ये चुनाव पिछले चुनावों की तरह आसान नहीं हैं। जी20, चंद्रयान-3, सूर्य पर आदित्य का प्रक्षेपण, महिला आरक्षण और कई अन्य योजनाओं को भुनाने में लगी भाजपा को अब इंडिया गठबंधन से डर लगने लगा है। इसी डर के चलते प्रधानमंत्री मोदी की सरकार संविधान में से इंडिया शब्द हटाने का निर्णय ले चुकी है। मगर विपक्ष के पास मोदी जैसा कद्दावर नेता नजर नहीं आ रहा है। राहुल गांधी को उनके सामने का चेहरा माना जा रहा है, परंतु विपक्षी गठबंधन ने अभी तक किसी चेहरे को प्रधानमंत्री मोदी के प्रतिद्वंद्वी के तौर पर जनता के सामने नहीं रखा है। कुछ जानकार विपक्षी गठबंधन के आपसी मतभेद के चलते कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बहुत दिन तक नहीं रह सकेगा। हालांकि ऐसा लगता नहीं है और इस बार एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन कम मजबूत नहीं है। पिछले समय में हुए गुजरात विधानसभा के चुनावों में 2019 प्रचंड जीत के बाद भाजपा नेता मोदी को अपराजेय मानने लगे हैं। परंतु भाजपा इस एक जीत को बड़ा करके दिखा रही है, नहीं तो इसी दौरान हिमाचल को भाजपा ने ही गंवाया है। परंतु प्रधानमंत्री मोदी का डर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वह आगामी चुनाव में जीतकर एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने इस बार 15 अगस्त को लाल किले से साफ कहा कि वह अगली बार भी लाल किले से तिरंगा फहराने फिर आएंगे।

प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से राजनीतिक पार्टियों ने ढेरों प्रश्न खड़े कर दिए। अब प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी दौरे पर पहुंचकर वहीं के निवासियों को कई योजनाओं के तोहफे दे रहे हैं। उन्होंने काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव में भी भाग लिया। पूरे उप्र में बने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का भी प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। राजनीति के जानकार मानकर चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा मां गंगा से आशीर्वाद लेने के लिए है। विदित हो कि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से ही सांसद हैं। तीसरी बार अगर वह प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वह और ताकतवर नेताओं में शुमार होंगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी ही फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, वे केंद्र की सत्ता में फिर से मोदी के आने के लिए अभी से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। इन सब गतिविधियों को देखकर प्रधानमंत्री मोदी का सीना और चौड़ा हो जाता है। हालांकि देश में मोदी के खिलाफ एक हवा चल रही है, जिसे लेकर वह चिंतित भी हैं। परंतु वह राजनीति में एक अपराजेय नेता की तरह हर चुनाव जीतकर इतिहास में अमर होने की चाह रखते हैं, जिसे पूरा करने के लिए ही वह सभी हथकंडे अपना रहे हैं।

● **इन्द्र कुमार**

2024 की अपनी लड़ाई मजबूत कर रही भाजपा!

यदि भाजपा इन राज्यों में मोदी की छवि पर चुनाव में नहीं जाती है, फिर भी मोदी इन राज्यों में पार्टी के प्रचार के लिए अवश्य जाएंगे। यदि इस परिस्थिति में पार्टी को हार मिलती है तो भी विपक्ष इसे भाजपा और मोदी की लोकप्रियता में कमी के रूप में ही प्रचारित करेगा। ऐसे में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़कर पार्टी की स्थिति सम्मानजनक स्कोर तक लाकर भाजपा 2024 की अपनी लड़ाई ही मजबूत कर रही है, ऐसा माना जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन चुनावी राज्यों में भाजपा के द्वारा मोदी को चेहरा बनाना बहुत सोचा-समझा हुआ और रणनीति के अनुसार उठाया गया निर्णय लगता है। इन्हीं राज्यों के पिछले विधानसभा चुनावों में हार के बाद भी भाजपा को लोकसभा चुनाव में जीत हासिल हुई थी। ऐसे में उन्हें लगता है कि इस बार भी इन चुनाव परिणामों का मोदी की छवि पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा।

मोदी और शाह की प्रतिष्ठा दांव पर

छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसलिए भाजपा 21 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची 17 अगस्त को ही जारी कर चुकी है। उसके बाद से लगातार भाजपा संगठन बची हुई 69 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रहा है। 1 अक्टूबर को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने दिल्ली में छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ बैठक की और उसके बाद शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ की दूसरी सूची पर मुहर लगी और भाजपा ने इसे जारी कर दिया।

छत्तीसगढ़ को लेकर अमित शाह ने विशेष रणनीति बनाई है। देशभर से 185 से ज्यादा भाजपा नेता मतदान के एक दिन पहले तक छत्तीसगढ़ में डेरा डाले रहेंगे। हर संभाग के लिए एक प्रभारी बनाया गया है। हर जिले के लिए भी एक प्रभारी बनाया गया है और हर विधानसभा सीट के लिए दो-दो प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। विस्तारक भी जमीनी स्तर पर काम देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मौजूद भाजपा के ये सभी नेता उड़ीसा, बिहार और झारखड से हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 39 सीटें आरक्षित हैं। जिसमें से 29 सीटें एसटी वर्ग के लिए और 10 सीटें एससी वर्ग के लिए हैं। बाकी 51 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं। सीटों के हिसाब से देखें तो रायपुर संभाग से 20 सीटें, बिलासपुर संभाग से 24 सीटें, सरगुजा संभाग से 14 सीटें, दुर्ग संभाग से 20 सीटें और बस्तर संभाग से 12 सीटें आती हैं। इन पांच संभागों की जिम्मेदारी पांच बड़े नेताओं को दी गई है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल इलाके बस्तर से 12 सीटें कांग्रेस के पास हैं। इसलिए भाजपा ने अपनी परिवर्तन यात्रा की शुरूआत बस्तर से ही की थी। 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी भी जगदलपुर पहुंचे और परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने के साथ ही एक रैली को भी संबोधित किया। तीन महीने में प्रधानमंत्री मोदी का यह चौथा छत्तीसगढ़ दौरा था। इसके पूर्व मोदी 30 सितंबर को बिलासपुर में भाजपा की परिवर्तन यात्रा का समापन करने और उससे पहले 14 सितंबर को रायगढ़ गए थे।

अपनी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उसकी नाकामियों को गिनाया। छत्तीसगढ़ में जहां अब तक के सर्वे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती दिख रही है, वहां मोदी का हमलावर होना भाजपा के लिए जरूरी भी है। असल में भाजपा हाईकमान मप्र में सरकार बचाने और राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को हटाने से ज्यादा बड़ी चुनौती छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने को मान रही है। छत्तीसगढ़ को अमित शाह और मोदी ने चुनौती के रूप में लिया है और इस छोटे राज्य के बड़े निर्णय खुद दिल्ली में ले रहे हैं। भाजपा मप्र की तर्ज पर जहां कोई विकल्प न हो वहां सांसद को उतारने की रणनीति पर छत्तीसगढ़ में भी काम कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरने के लिए पाटन से दुर्ग के सांसद विजय बघेल को भाजपा ने पहले ही मैदान में उतार दिया है। भूपेश बघेल और विजय बघेल पहले भी तीन बार आपस में टकरा चुके हैं जिसमें दो बार भूपेश बघेल और एक बार विजय बघेल जीत चुके हैं।

भाजपा बिलासपुर संभाग पर विशेष ध्यान दे रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग बिलासपुर ही है। 8 जिलों के संभाग में यहां छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा 24 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 14 पर कांग्रेस, 7 पर भाजपा, 2 पर बसपा और एक सीट पर जनता कांग्रेस का कब्जा है। प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में से चार लोकसभा सीट अकेले बिलासपुर संभाग से आती हैं। इसमें से तीन लोकसभा सीट पर भाजपा और एक पर कांग्रेस का कब्जा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और बिलासपुर से सांसद अरूण साव इस क्षेत्र के नेता हैं। बिलासपुर संभाग की लगभग सभी सीटों पर अनुसूचित जाति का बड़ा वोट बैक है। छत्तीसगढ़ की 10 एससी सीटों में से 4 सीटें बिलासपुर संभाग से ही हैं। यही वजह है कि बसपा के दो विधायक यहां से चुने गए हैं। इसलिए कांग्रेस दलित और आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जांजगीर में सभा करा चुकी है। दुर्ग संभाग की बात करें तो कभी भाजपा का गढ़ रहे दुर्ग संभाग में पिछले 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने अप्रत्याशित प्रदर्शन करते हुए 20 विधानसभा सीटों में से 18 सीटें जीत ली थीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग संभाग की पाटन विधानसभा सीट से विधायक हैं।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

जातीय समीकरणों को साधने की कवायद

2018 के विधानसभा चुनाव में सरगुजा संभाग से भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया था। सरगुजा संभाग की 14 की 14 विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती थीं। सरगुजा से कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हैं। भाजपा के इस क्षेत्र के आदिवासी नेता नंदकुमार साय का कांग्रेस का दामन थामने से भाजपा की जमीन कमजोर हुई है। सरगुजा लोकसभा सीट से सांसद और मोदी कैबिनेट में आदिवासी मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह को भाजपा विधानसभा चुनाव लड़वा सकती है। रेणुका सिंह दो बार विधायक रह चुकी हैं। वो केंद्र में छत्तीसगढ़ से अकेली मंत्री हैं। उनकी तेज तर्रार आदिवासी नेता वाली छवि है। बिलासपुर संभाग के बाद सबसे ज्यादा सीटें रायपुर संभाग से आती हैं। इस संभाग में 20 सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां की 20 सीटों में से कांग्रेस ने 14, भाजपा ने 5 तथा अजीत जोगी कांग्रेस ने एक जीती थी। जातिगत समीकरण की बात करें तो रायपुर संभाग में 32 फीसदी मतदाता अनुसूचित जनजाति से हैं, 13 फीसदी अनुसूचित जाति से हैं और 47 फीसदी ओबीसी वर्ग के मतदाता हैं। वहीं बस्तर संभाग से 12 सीटें आती हैं। फिलहाल कांग्रेस के पास 8 सीटें और भाजपा के पास 4 सीटें है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के आगामी विधानसभा चुनाव को मोदी शाह की जोड़ी ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। छत्तीसगढ़ को लेकर सभी फैसले दिल्ली से हो रहे हैं।

क्या फिर बनेंगे नए समीकरण?

शरद पवार को इतनी तवज्जो क्यों दे रही है कांग्रेस?

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में अजित पवार की बगावत के बाद झगड़ा चुनाव आयोग पहुंच चुका है। एनसीपी का असली बॉस कौन होगा? क्षेत्रीय क्षत्रपों में बड़ा कद रखने वाले शरद पवार क्या पार्टी बचा पाएंगे? या फिर शिवसेना जैसा हाल होगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका आने वाले दिनों में जैसे-जैसे चुनाव आयोग में सुनवाई आगे बढ़ेगी, वैसे-वैसे इसका उत्तर मिलेगा, लेकिन इस सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस आखिरकार शरद पवार को इतनी तवज्जो क्यों दे रही है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार केंद्रीय चुनाव आयोग में सुनवाई के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी से मिले थे। इन नेताओं की बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शरद पवार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बारामती स्थित एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट आने का भी निमंत्रण दिया। ऐसे में जब पवार अपने राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती का सामना कर रहे हैं तब कांग्रेस उन्हें क्यों तवज्जो दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पवार भले ही विधायकों और सांसदों के संख्याबल में कमजोर हो गए हों लेकिन उसके पास कैडर का बड़ा हिस्सा उनके साथ है। यही वजह है कि कांग्रेस को शरद पवार में अभी पावर दिख रही है। केंद्रीय चुनाव आयोग में सुनवाई के दौरान शरद पवार गुट की तरफ यही दलील भी दी गई कि 99 फीसदी संगठन उनके पास है। चुनाव आयोग में शरद पवार की तरफ से कहा गया था कि पार्टी में कोई फूट नहीं है। कुछ अपने स्वार्थ के चलते पार्टी छोड़कर गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर अजित पवार ने 53 में से 42 सांसदों के समर्थन का दावा किया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि 9 में से छह विधान परिषद सदस्यों, नागालैंड से सभी 7 विधायकों और लोकसभा एवं राज्यसभा के एक-एक सदस्य का समर्थन प्राप्त है।

ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में फिर हलचल देखने को मिल सकती है क्योंकि इन दिनों अजित पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच दूरियां साफ दिख रही है। बता दें कि बीते दिन अजित पवार कैबिनेट मीटिंग में भी शामिल नहीं हुए थे। अजित पवार की कैबिनेट मीटिंग में गैर-मौजूदगी से महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से किसी नए समीकरण की ओर इशारा करते दिखाई पड़ने लगे है। अपने समय और काम के पाबंद अजित पवार के बीते दिन मंत्रिमंडल की बैठक में गैर-मौजूदगी ने कई सवाल खड़े किए हैं। अपने राजनीतिक और मंत्रिपद के कार्यकाल में शायद ही अजित पवार मुंबई में होने के बाद भी गैरमौजूद रहे हों। बीते दिन कैबिनेट की मीटिंग में सबसे पहली चर्चा नांदेड के सरकारी अस्पताल में 24 मौतों पर हुई, जो एक ही दिन में दर्ज की गई थी। इन मौतों से सरकारी अस्पताल की बदइंतजामी फिर एक बार सामने आई है।

गौरतलब है कि यह अस्पताल मेडिकल एजुकेशन के अंतर्गत आता है और इस विभाग के मंत्री हसन मुशरिफ हैं और हसन मुशरिफ अजित पवार गुट के हैं। दवाईयां उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की है जिसके मंत्री तानाजी सावंत हैं और ये एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री हैं। मौत की वजह जरूरी दवाइयों का अभाव है या फिर डॉक्टर, नर्स का मौजूद न होना या कुछ और। इस सबकी जांच के लिए सरकार ने तीन सदस्यीय टीम का गठन किया गया हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री ने जल्द ही रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। कुछ महीने पहले जब ठाणे के अस्पताल में एक ही दिन में 18 मरीजों की मौत का मामला सामने आया था, तब राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर सवाल उठाए थे। सूत्र बताते हैं कि अजित पवार ने कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से पूछा था कि आपके ठाणे शहर के अस्पताल में क्या चल रहा है? इसे एकनाथ शिंदे ने हंसकर टाल दिया था। उस वक्त मौजूद देवेंद्र फडणवीस ने भी बीच-बचाव कर बहस को दूसरी दिशा में मोड़ दिया था, लेकिन इस विवाद का असर यह हुआ कि अजित पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे में कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। आइए नजर डालें उन घटनाक्रम पर जिस कारण अजित पवार और एकनाथ शिंदे में दूरियां बढ़ती नजर आईं।

बता दें कि जब जालना में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे पाटिल से मिलने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गए तो वहां अजित पवार साथ नहीं गए। फिर जब अमित शाह गणपति दर्शन के लिए मुंबई आए, उस वक्त भी अजित, अमित शाह से मिलने नहीं पहुंचे। वहीं, जेपी नड्डा मुंबई आए तब भी अजित पवार पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में व्यस्त रहे। अजित पवार के पास वित्त मंत्रालय होने की वजह से वह सभी विभागों के बड़े प्रोजेक्टों की फाइल देखने लगे, जो एकनाथ शिंदे को नागवार गुजरी।

उल्लेखनीय है कि अजित पवार की प्रशासन पर पकड़ है। कई सालों तक मंत्री बने रहने और कई मंत्रालयों में काम करने का उन्हें गाढ़ा अनुभव है। कहा जाता हैं कि मौजूदा सरकार में भले ही मुख्यमंत्री पद पर एकनाथ शिंदे हों लेकिन सरकार के अहम निर्णय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की रजामंदी के बिना पूरे नहीं होते। अब जबकि अजित पवार भी सरकार का हिस्सा है और वित्त मंत्रालय उनके पास होने की वजह से हर एक विभाग में अपना हस्तक्षेप रखते है, ऐसे में दूरियां तो बढ़ेंगी ही। सूत्रों की मानें तो मंत्रिमंडल का तीसरा विस्तार कुछ ही दिनों में हो सकता है क्योंकि अभी 14 मंत्री पद बाकी बचे हुए हैं, जिसमें से अजित पवार गुट के एक कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पद की मांग की जा रही है। अपना कुनबा संभालने के लिए एकनाथ शिंदे गुट को ज्यादा मंत्री पद की जरूरत है। वहीं भाजपा में भी कई ऐसे नेता हैं जिन्हें मंत्री पद की आस है इसलिए अब और मंत्री पद मांगा गया है।

बीते दिन एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे, लेकिन अजित पवार साथ नहीं आए। इसका कारण बताया गया उनकी तबियत ठीक नहीं है। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अजित पवार की तबियत ठीक नहीं है, इसीलिए वे मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं आए, उनकी गैर मौजूदगी का कोई और मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। अजित पवार ने हाल ही में बारामती दौरे पर कहा था कि आज उनके पास वित्त मंत्री पद है, वे सरकार में हैं, कल होंगे या नहीं, पता नहीं, कल किसी ने नहीं देखा है। राजनीतिक सूत्रों की मानें तो अजित पवार की नाराजगी सरकार में शामिल होने के दिनों से ही दिखाई दे रही थी जो अब और गहरी होती जा रही है। इसलिए अपने फैसले से हमेशा सभी को चौंका देने वाले अजित पवार कोई और चौंकाने वाला फैसला लें तो आश्चर्य नहीं होगा।

● **बिन्दु माथुर**

आश्वस्त गहलोत

विधानसभा की 200 सीटों वाले राजस्थान में 2023 के चुनाव की तैयारियां आखिरी दौर में हैं। पिछले तीस साल में पहली बार कांग्रेस सत्ता में होने के बावजूद आक्रामक दिख रही है और भाजपा नेतृत्वविहीन लग रही है। भाजपा पीढ़ीगत बदलाव की चाहत रखती है, लेकिन वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली पुरानी पीढ़ी को हाशिये पर धकेलने का साहस नहीं जुटा पा रही है। यह बात अलग है कि भाजपा आलाकमान ने एक नई पीढ़ी राजस्थान में तैयार कर दी है। ये चेहरे प्रदेश में कई इलाकों, वर्गों और जातियों से आते हैं, लेकिन वे खुद भी इस चुनाव में बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।

कांग्रेस के विधायकों के प्रति मतदाताओं का असंतोष जाहिर है, लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुले रोष से बचे हुए हैं। ढाई दशक पहले 1998 में जब भैरोंसिंह शेखावत के नेतृत्व में भाजपा बुरी तरह हारी थी, तब पार्टी के भीतर एक उद्वेलन हुआ था। उस नाकामी से वसुंधरा राजे नए चेहरे के रूप में उभरकर बड़ी ताकत बनी थीं। भाजपा का सियासी कारवां उनके माध्यम से ही सूबे में आज तक आगे बढ़ता रहा है। कांग्रेस की सरकार जब 1998 में बनी, तो पार्टी आलाकमान ने पुराने नेताओं की भीड़ को दरकिनार करके तेजतर्रार नए चेहरे अशोक गहलोत पर भरोसा किया और सरकार की कमान उन्हें दी। आज किसी को भी यह पच नहीं रहा है कि वसुंधरा के बिना भाजपा चुनाव में उतर सकती है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि वसुंधरा राजे इस चुनाव में उसी भूमिका में रहेंगी, जिसमें वे 2003 से लगातार दो दशक तक बनी रही हैं।

दस अलग-अलग दिलो-दिमाग वाले सियासी इलाकों में सिमटी प्रदेश की 200 सीटों की राजनीति को गहलोत ने कमाल तरीके से समझा और कांग्रेस पर कभी भी अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने दी, भले ही मतदाता उनसे दूर छिटकता रहा। उनकी पहली सरकार बुरी तरह हारी और कांग्रेस 153 से 56 सीटों पर आकर सिमट गई। वह 2003 का चुनाव था और भाजपा का नेतृत्व तब वसुंधरा राजे के हाथ में था। उस चुनाव से भाजपा को ही नहीं, राजस्थान को भी एक बड़ा चेहरा मिला। प्रदेश की पुरुष वर्चस्वशाली राजनीति में पार्टी के बाहर और भीतर वसुंधरा लगातार निशाने पर रहीं, लेकिन उन्होंने अपने आपको एक सशक्त नेता के रूप में स्थापित किया। 2013 के चुनाव में उनके नेतृत्व में भाजपा को 45.17 प्रतिशत वोट मिला और भाजपा की सरकार बनी। उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, लेकिन वे सत्ता में लौटने के लिए लड़ीं और करिश्माई कामयाबी पाई। इस बार इस कामयाबी की संभावनाएं धुंधलके में हैं।

यह सच है या सिर्फ कल्पना, यह तो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ही बता सकता है, लेकिन 2023 के चुनाव में भाजपा शायद किसी नए प्रयोग की ओर बढ़ रही है। इस बार कांग्रेस की सरकार को टक्कर देने उतरा प्रतिपक्ष चेहराविहीन है और इसे आलोचक बिना दूल्हे की बारात बता रहे हैं। यह वही तंज है, जो भाजपा अपने प्रतिपक्षी गठबंधन पर राष्ट्रीय स्तर पर करती आई है। वसुंधरा को लेकर भाजपा का रवैया असमंजस भरा है। इसे अगर एक साहित्यिक इबारत के रूप में समझा जाए, तो जिस समय वे मंजिल के बेहद करीब हैं, उन्हें कारवां से दूर रखा जा रहा है। उधर, गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान इस बार कांग्रेस के एक ऐसे आक्रामक मुख्यमंत्री को देख रहा है जो सादगी और शुचितावाद की राजनीति को परे रखकर जैसे को तैसे वाले रूप में सबके सामने है। अशोक गहलोत अपने प्रथम संस्करण (1998-2003) से द्वितीय (2008-2013) और तृतीय (2018-2023) तक एकदम अलग नजर आ रहे हैं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार 2013 का चुनाव बुरी तरह हारी और महज 21 सीटों पर सिमट गई थी। वसुंधरा के नेतृत्व में भाजपा को 163 सीटों का ऐतिहासिक बहुमत मिला था। यह ठीक वैसे ही था, जैसे 1998 में कांग्रेस को 44.95 प्रतिशत वोटों के साथ 153 सीटें मिली थीं, जबकि भाजपा 2013 में 45.17 प्रतिशत वोटों के साथ 163 सीटों तक पहुंची थी। प्रदेश की सियासत की हकीकत साफ बता रही थी कि 1998 राजस्थान की सियासत से भैरोसिंह शेखावत की विदाई की पुकार लेकर आया तो 2013 के चुनाव नतीजों ने गहलोत के प्रति पार्टी हाईकमान को गुस्से से भर दिया। इस हकीकत के बावजूद कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का निस्तेज नेतृत्व भाजपा के 31 प्रतिशत वोटों के साथ 282 सीटों के मुकाबले 19.31 प्रतिशत वोटों के साथ महज 44 सीटों पर सिमट गया। इस दौरान आलाकमान ने गहलोत की विदाई की सोची और प्रदेश में एक नए नेतृत्व के तौर पर सचिन पायलट को कमान सौंपी। अब चाहे गहलोत हों या वसुंधरा, राजस्थान के नेताओं का अपनी मिट्टी से प्रेम कहें या मुख्यमंत्री की कुर्सी से, उनका मोहभंग होना इतना आसान नहीं है।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

इस बार नए अंदाज से चुनाव लड़ेंगे गहलोत

राजस्थान 2023 का चुनाव एक नए ही अंदाज में लड़े जाने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न केवल अपनी सरकार की कई बेहद आकर्षक योजनाएं धरातल पर उतारी हैं, बल्कि वे पूरे देश में अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने भाजपा के ऑपरेशन लोटस को बुरी तरह फ्लॉप कर दिया। यही नहीं, जिस समय आलाकमान के भेजे दूतों ने उन्हें सत्ता से हटाकर केंद्र में बुलाने की कोशिश की तो वे इसे बहुत पहले भांप गए और उन्होंने बड़ी ही सफाई और नफासत से अपना पद बचाया। इस तरह गहलोत इस कार्यकाल में भीतरी और बाहरी लड़ाइयों में आश्चर्यजनक रूप से कामयाब रहे हैं। कांग्रेस के भीतर गहलोत ने अपने प्रतिद्वंद्वी सचिन पायलट को चुनाव संबंधी किसी भी कमेटी में प्रमुख पद नहीं लेने दिया है। मुख्यमंत्री बनने का स्वप्न देखने वाले पायलट को जब पद नहीं मिला और आलाकमान अशोक गहलोत के सामने बेबस नजर आया, तो उम्मीद की गई कि पायलट को चुनाव के समय कैंपेन कमेटी का चेयरमैन तो बना ही दिया जाएगा। आश्चर्यजनक रूप से इस पद पर अशोक गहलोत के समर्थक मंत्री और दलित नेता गोविंदराम मेघवाल को बैठा दिया गया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नए सिरे से गठित कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) में पायलट समेत राजस्थान कांग्रेस के सात नेताओं को शामिल करके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव से पहले राजस्थान के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं में संतुलन साधने की कोशिश की है।

क्या योगी पर है संघ की कृपा?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के लखनऊ में समन्वय बैठक करने से उप्र की राजनीति अचानक गरमा गई है। लखनऊ में हुई बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं भाजपा के बीच क्या मंत्रणा हुई, इसे लेकर तरह-तरह के कयास ही लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक दल, बहुजन समाज पार्टी एवं अन्य पार्टियों के कान खड़े हो गए हैं। सभी पार्टियों के नेता ये जानना चाह रहे हैं कि इस बैठक में क्या मंत्रणा हुई? मगर असल बात किसी को नहीं पता चल पा रही है। अपुष्ट सूत्रों की मानें, तो यही कहा जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर कमर कसी गई है। मगर कुछ सूत्र यह भी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख योगी आदित्यनाथ को भविष्य में कुछ बड़ा देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उनके निकटतम लोगों की इस अहम बैठक से दूरी से तो कुछ ऐसा ही लगता है।

लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की उपस्थिति के बीच वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना एवं अपने कार्यक्रमों को निपटाकर लौट आना, एक अनसुलझी गुत्थी बन गए हैं। प्रश्न उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत से क्यों नहीं मिले? इसे लेकर लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थक इसे अपने इस प्रिय नेता के लिए सुनहरे भविष्य की आहट के रूप में देख रहे हैं एवं मन-ही-मन प्रसन्न हो रहे हैं। राजनीति में रूचि रखने वाले लोग अभी इस तरह की चर्चाओं को विश्वासपूर्ण दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। उनका मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरूद्ध अभी नहीं दिख रहे हैं। अभी हर हाल में वह 2024 में तीसरी बार भी केंद्र में भाजपा की सरकार बनाने की सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर भाजपा 2024 में सत्ता में आई, तो भी कम-से-कम 2029 में योगी आदित्यनाथ केंद्र के लिए चुने जा सकते हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यह बात अच्छी तरह जानते हैं एवं उनकी तैयारियां भी उसी तरह की हैं। ये लोग ऐसा भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में मनमुटाव रहता है, जिसके चलते उनके समर्थक भी बंटे हुए दिखते हैं। योगी आदित्यनाथ अगर आज उप्र के मुख्यमंत्री हैं, तो यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की कृपा से हैं। जो भी हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख की ओर से लखनऊ में बुलाई गई समन्वय बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। विपक्षी पार्टियां इसे लेकर सकते में हैं। उधेड़बुन यह है कि आगामी चुनाव में जमीनी स्तर पर भाजपा एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता मिलकर कार्य कर सकते हैं। उनकी संख्या बढ़ाई जानी भी तय है। इस बार महिलाओं को भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जोड़ा जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए उप्र के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को कमर कस लेनी चाहिए।

भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव राम मंदिर के उद्घाटन, महिला आरक्षण एवं सनातन धर्म को लेकर जीतना चाहती है। मगर इतने पर भी भाजपा को भय है कि वो कहीं चुनाव हार न जाए। इसका कारण बीते दिनों हुए घोसी विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा की करारी हार है। चर्चा छिड़ गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उप्र में प्रभाव कम हो गया है। मगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की ओर से लखनऊ में अकस्मात बुलाई गई समन्वय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विशेष उपस्थिति कुछ और ही संकेत कर रही है। चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ अब और अधिक शक्तिशाली होंगे। मगर इसके लिए उन्हें लोकसभा, विधानसभा एवं पंचायती राज तक उप्र की हर स्तर की सत्ता को बचाकर रखना होगा। भाजपा के योगी समर्थक कार्यकर्ता उमेश गंगवार का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रभाव कम नहीं हुआ है। एक सीट उपचुनाव में किसी के जीतने से सत्ता का निर्णय नहीं हो जाता। आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा की प्रचंड बहुमत से जीत होगी एवं केंद्र में दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी।

उधर, समाजवादी समर्थक योगेंद्र सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी के कार्यों से जनता संतुष्ट नहीं है। उन्हें बुलडोजर चलवाने के अतिरिक्त कुछ नहीं आता। उनके कार्यकाल में विकास शून्य रहा है। जिधर देखो सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, मगर वाहनों के चालान तीव्रता से हो रहे हैं। हर वस्तु महंगी होती जा रही है। बिजली से लेकर यात्रा किराया तक बेहिसाब बढ़ाया हुआ है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

भागवत की बैठक में मोदी नहीं!

लोगों को आशंका है कि कहीं योगी आदित्यनाथ को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर तो नहीं देखा जाने लगा है? हालांकि ऐसी कोई चर्चा अभी कहीं नहीं है। मगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थक कई वर्षों से चुपके-चुपके इस प्रकार की चर्चा अवश्य करते दिख जाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद केंद्र का शासन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में ही जाएगा। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक भी उप्र में कम नहीं हैं, जो स्पष्ट कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ उप्र के लिए ही उपयुक्त हैं, केंद्र की सत्ता संभालने की योग्यता केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ही है। उप्र में भाजपा के इन दो गुटों में अंदर-ही-अंदर टूट पड़ी हुई है। इस टूट को अब और बल मिल गया है। इसका कारण यह है कि इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं उनके कुछ विश्वसनीय लोगों के साथ बैठक की, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में नहीं दिखे। वह भागवत की लखनऊ में उपस्थिति के समय ही वाराणसी पहुंच गए। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की बैठक में क्या कुछ हो रहा है? इसका पता लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के दाहिना हाथ माने जाने वाले देश के गृहमंत्री अमित शाह की इस बैठक पर पैनी दृष्टि रही।

मझधार में नीतीश कुमार

एक तरफ तो नीतीश कुमार के करीबी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी का कहना है कि इंडी एलायंस में नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला हो गया है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर बिहार में फिर से अटकलों का बाजार गर्म है कि वह एनडीए में जाने का रास्ता खोज रहे हैं। इसकी वजह यह है कि बिहार की लोकसभा सीटों को लेकर उनका लालू यादव के साथ समझौता नहीं हो पा रहा है। इसीलिए वह जी-20 के मौके पर राष्ट्रपति के रात्रिभोज में शामिल हुए थे, और प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की थी। वहीं हाल ही में उनकी लालू यादव से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में लोकसभा सीटों के बारे में कोई चर्चा हुई या नहीं, यह नहीं पता लेकिन उससे पहले से यह चर्चा चल रही थी कि लालू यादव ने जेडीयू को आठ सीटें देने की पेशकश की है। फिलहाल जेडीयू के 16 लोकसभा सदस्य हैं।

2014 में भाजपा को धोखा देने के बावजूद जब नीतीश कुमार 2017 में एनडीए में लौटे थे, तो भाजपा ने उन्हें समझौते में 17 सीटें लड़ने को दी थी, जिनमें वह 16 जीत गए थे। इसलिए उन जीती हुई 16 सीटों में से केवल आधी सीटों पर चुनाव लड़ने की लालू यादव की पेशकश नीतीश कुमार स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए दिल्ली में हुई कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में नीतीश कुमार ने फारूख अब्दुल्ला से यह फॉर्मूला पेश करवाया था कि हारी हुई सीटों पर बातचीत हो, जीती हुई सीटें उसी दल के पास रहें जिसने 2019 में जीती थीं। लेकिन लालू यादव ने यह फॉर्मूला ठुकरा दिया था। अब नीतीश कुमार की लालू यादव से मुलाकात के बाद यह अटकल दोबारा से शुरू हुई है कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ जाने का रास्ता खोज रहे हैं। राजनीति में कई बार दबाव बनाने के लिए भी अटकलों का इस्तेमाल होता है। यह अटकल लालू यादव पर दबाव बनाने के लिए खुद नीतीश कुमार कैंप से फैलाई हुई हो सकती है।

लालू यादव के बेटे और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इन अटकलों को सिरे से खारिज करते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने यह कहकर इन अटकलों को हवा दे दी कि अगर नीतीश कुमार वापस लौटते हैं, तो उनका स्वागत होगा। हालांकि नीतीश कुमार को एनडीए में वापस लेने का फैसला करना उनके हाथ में नहीं है। दूसरी तरफ भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार को एनडीए में वापस लिया गया तो भाजपा में बगावत हो जाएगी। सुशील मोदी उन लोगों में से एक हैं, जो नीतीश कुमार के लिए एनडीए का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाने की बात कह रहे हैं। हालांकि भाजपा के रणनीतिकार अमित शाह भी यह बात कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के वापस लौटने के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। फिर सुशील कुमार मोदी को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि अगर नीतीश को एनडीए में वापस लिया जाता है, तो भाजपा में बगावत हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि उन्हें भी कहीं से यह भनक लगी है कि नीतीश कुमार कुछ कोशिश कर रहे हैं, और इंडी एलायंस बनने के बाद 2024 के गंभीर संकट को देखते हुए मोदी-शाह की जोड़ी पिघल सकती है। तो सुशील कुमार मोदी का यह बयान भी मोदी-शाह पर दबाव बनाने के लिए है कि वे ऐसी गलती न करें।

सच यह है कि सालभर पहले नीतीश कुमार में जितना उत्साह था, इंडी एलायंस बनते ही वह ठंडा पड़ चुका है। सालभर पहले तो उन्होंने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी करवा दिया था। यह भी ऐलान करवा दिया था कि वह बिहार से नहीं, उप्र से लड़ेंगे।

उप्र से इसलिए क्योंकि उप्र से चुनाव लड़ने से प्रधानमंत्री बनने की संभावना बढ़ जाती है। नरेंद्र मोदी भी इसीलिए 2014 में गुजरात के साथ साथ उप्र से चुनाव लड़े थे। ललन सिंह ने यह भी बता दिया था कि वह उप्र की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। एनडीए छोड़ने और लालू यादव के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार ने फूलपुर का दौरा भी किया था। उस समय नीतीश बड़े सपने देख रहे थे। वह हवा उड़ा रहे थे कि वह उप्र की फूलपुर, मिर्जापुर या अंबेडकर नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे, इन तीनों सीटों पर उनकी कुर्मी जाति के वोट मायने रखते हैं। वह बिहार, झारखंड के अलावा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुर्मियों को भी अपने पक्ष में इकट्ठा करने की रणनीति बना रहे थे। वह बहुत बड़े सपने ले रहे थे कि विपक्ष के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनकर वह देशभर की कृषक जातियों कुर्मियों, पटेलों और जाटों को अपने पीछे लामबंद करेंगे। इसमें वे आंध्रप्रदेश के रेड्डी, कापू और नायडू जातियों को भी जोड़ते थे।

● **विनोद बक्सरी**

मंडल राजनीति को पुनर्जीवित करने की कोशिश

नीतीश कुमार ने उन दिनों ही मंडल राजनीति को पुनर्जीवित करने के लिए ही जातीय जनगणना का दांव भी चला था, जबकि उस दांव को भी अब कांग्रेस और राहुल गांधी ने उनसे हथिया लिया है। कांग्रेस और राहुल गांधी की आवाज निश्चित ही लालू यादव, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव से ज्यादा है। लोकसभा में जिस तरह राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की आवाज उठाई है, उस तरह कभी लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और शरद यादव भी नहीं उठा पाए थे। यह बात अलग है कि मंडल की जातियां अब कमंडल से जा मिली हैं, और उन्हें कमंडल से निकालना इतना आसान नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी हैदराबाद कार्यसमिति में जातीय जनगणना का प्रस्ताव पास करके प्रयास शुरू कर दिया है। इस बीच राहुल गांधी ने अपना तौर तरीका पूरी तरह बदल दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद वह पप्पू की छवि से बाहर निकल चुके हैं। उसके बाद लगातार जनता के बीच दिखाई देकर ट्विटर नेता की छवि भी तोड़ चुके हैं। नेहरू परिवार का कोई भी वारिस जनता में इतना दिखाई नहीं दिया, जितना राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। वह हर रोज अखबारों और सोशल मीडिया में नए अवतार में दिख रहे हैं। राहुल गांधी के इस नए रूप ने प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाले नीतीश कुमार की उम्मीदों पर चुनावों से पहले ही पानी फेर दिया है। अलबत्ता अब उन्हें अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाना भी भारी पड़ रहा है, क्योंकि लालू यादव जेडीयू को निगलने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। जेडीयू के कुछ सांसद भाजपा से टिकट मांग रहे हैं, तो कुछ लालू यादव से टिकट मांग रहे हैं।

एक ऐसा युद्ध जिसका कोई अंत नहीं

7 अक्टूबर की सुबह इजराइल पर हमास के भीषण हमले के बाद इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो पहला संदेश जारी किया उसमें कहा- हम युद्ध में हैं और हम इसे जीतेंगे। उन्होंने यह नहीं कहा कि हम पर हमला हुआ है। न ही उन्होंने यह कहा कि हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसके अर्थ बहुत गहरे हैं और इतिहास में हजार साल तक पीछे जाते हैं। इजराइल देश का नाम बाद में हुआ उसके पहले यह जैकब का उपनाम था। जैकब मतलब यहूदियों के पितामह माने जाने वाले इब्राहिम के पोते और इशाक के बेटे। जैकब ने जब-जब स्वर्गदूतों के साथ कुश्ती लड़ी तो उन्हें यह नाम दिया गया इजराइल, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का योद्धा। यहूदी मान्यताओं के मुताबिक जैकब के जो 12 बेटे हुए, उन्हीं से यहूदियों के 12 कबीले बने और सब अपने आप को इजराइल का वंशज यानी ईश्वर का योद्धा मानते हैं। इस्लामिक किताबों में इन्हीं की पहचान बनी इजराइल के तौर पर की जाती है।

इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े की शुरुआत भी इस्लाम के उदय के साथ ही हो गई। जो इस्लामिक किताबें लिखी गईं उनमें बनी इजराइल को अल्लाह का दुश्मन घोषित किया गया और उनसे लड़ने का आदेश दिया गया। कुरान हो या इस्लामिक हदीसें उनमें इस्लाम के मानने वालों को बताया गया कि वो इजराइल की संतानों से श्रेष्ठ हैं। हदीसें लिखी गईं कि कैसे उनके पैगंबर ने मदीना से इनका सफाया कर दिया था। इस्लामिक किताबों के मुताबिक मदीना में उस समय तीन यहूदी कबीले थे। बनू कुनैजा, बनू कुरैजा और बनू नादिर। इसमें से बनू कुरैजा के सफाये का विस्तृत विवरण हदीस की प्रामाणिक पुस्तकों में दिया गया है। ऐसे में यहूदियों से लड़ाई करना मुसलमानों के लिए अपने ईमान पर अमल करना है। वो दुनिया भर में जहां होते हैं इजरायलियों को लानते भेजते हैं। मौका मिलते ही मारने का प्रयास भी करते हैं। जैसे हमास के हमले के बीच मिस्र में एक पुलिसवाले ने ही दो यहूदी टूरिस्टों को गोली मार दी। खुद हमास के मुजाहिदों ने इजराइल के भीतर घुसकर जिस तरह की बर्बरता दिखाई है उससे यहूदियों के प्रति उनकी नफरत साफ दिखाई देती है।

याद करिए 2008 का मुंबई पर पाकिस्तानी आतंकवादियों का हमला। मुंबई हमले के दौरान यहूदी समुदाय के कॉफी हाउस लियोपोल्ड कैफे को भी निशाना बनाया गया था और आतंकियों ने 10 लोगों की हत्या कर दी थी। मतलब पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने जब मुंबई पर आतंकी हमले का प्लान बनाया तो उन्हें यह पता था कि मुंबई में कुछ यहूदी भी रहते हैं इसलिए उनके कॉफी हाउस को निशाना बनाया गया ताकि यहूदियों को मारकर सुन्नत पर अमल किया जा सके। इसलिए हमास के ताजा हमले के बाद बेंजमिन नेतन्याहू ने बहुत चुनकर हम युद्ध में हैं और हम इसे जीतेंगे शब्द का प्रयोग किया। यहूदी जानते हैं कि वो चाहें न चाहें उन्हें युद्धभूमि से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। इसलिए नेतन्याहू ने साफ-साफ हम युद्ध में हैं, शब्द का प्रयोग किया है। अब हर यहूदी यह समझ गया है जब तक धरती पर इस्लामिक किताबों पर ईमान लाने वाले मुसलमान हैं वो चाहें न चाहें उन्हें इस युद्ध में घसीटा जाता रहेगा। इसलिए 1948 में ब्रिटिश आधिपत्य वाले फिलिस्तीन से अलग करके ब्रिटिश शासकों ने जब यहूदियों को अपना देश इजराइल दे दिया उसके बाद उन्होंने एक कौम के रूप में नहीं बल्कि एक राष्ट्र के रूप में चुनौतियों का सामना करने की योजना पर काम शुरू किया।

1948 में एक देश के रूप में इजराइल को पा लेने के बाद यहूदियों ने समझ लिया कि वो एक ऐसे युद्ध में हैं जिसका कभी कोई अंत नहीं होगा। उन्हें इसी युद्ध में अपने आप को जिंदा रखना है इसलिए न केवल आर्थिक और वैज्ञानिक रूप से बल्कि सैन्य और सामरिक रूप से भी उन्होंने अपने आप को संगठित किया। इसलिए 1967 में पहली बार यहूदियों ने किसी युद्ध में ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। इस युद्ध में इजराइल की संतानों ने गाजा पट्टी, वेस्टबैंक, सिनाई और गोलान हाईट्स को कब्जे में ले लिया। इस युद्ध के बाद लगभग दस लाख अरब मुस्लिम यहूदियों के कब्जे में आ गए। इसके बाद 1995 में जो ओस्लो समझौता हुआ तो वेस्ट बैंक के तीन हिस्से कर दिए गए। एक हिस्सा वह जिस पर फिलिस्तीनियों का शासन है। एक हिस्सा वह जिस पर इजराइल का शासन है और एक हिस्सा वह जिस पर दोनों का संयुक्त शासन है।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

गाजापट्टी पर हमास का कब्जा

वेस्ट बैंक में 4.5 लाख यहूदी और लगभग 25 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। मेनलैंड इजराइल में 60 लाख यहूदी और 16 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। सिर्फ गाजापट्टी वो जगह है जो पूरी तरह से फिलिस्तीनियों के कब्जे में है और वहां एक भी यहूदी नहीं रहता। यही गाजापट्टी पर अब इखवानुल मुसलमीन (मुस्लिम ब्रदरहुड) से अलग होकर बने हमास का कब्जा है। वैसे तो वेस्टबैंक के इलाके में इजराइली और फिलिस्तीनियों के बीच रोजाना का संघर्ष रहता है लेकिन इस बार इजराइल के खिलाफ जो हमला गाजापट्टी की ओर से हुआ वो बहुत योजनाबद्ध तरीके से हुआ जिसमें 1967 के बाद पहली बार इजराइल को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े की जड़ 1948 में नहीं है जब ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने यहूदियों को इजराइल सौंपा था। इसकी जड़ें उससे अधिक गहरी हैं जो टेम्पल ऑन माउंट या फिर डोम ऑफ द रॉक में निहित हैं। वेस्टबैंक में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष भले ही कल को गाजापट्टी तक सिमट जाए लेकिन येरुसलेम पर जो इस्लामिक दावा है वह भला मुसलमान कैसे छोड़ देगा? अगर ओल्ड जेनेसिस (हिब्रू बाइबल) उसे किंग डेविड का शहर बता रहा है तो इस्लाम भी अपने पैगंबर के मेराज का सफर भी यहीं से करवा रहा है। बात अगर जमीन की हो तो एकबार को जीत हार से फैसला हो भी जाता है लेकिन यहां तो मसला मजहब और ईमान का है।

खालिस्तानियों का अड्डा बना कनाडा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को उत्तरी अमेरिकी राष्ट्र में जारी भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में नई दिल्ली की चिंताओं से अवगत करा रहे थे, उसी समय भारत में प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस द्वारा कनाडा में अलग खालिस्तान देश की मांग के समर्थन में भीड़ इकट्ठी की जा रही थी। 10 सितंबर की घटना है, जब कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के शहर सरी में गुरुनानक सिख गुरुद्वारे में खालिस्तान समर्थक सिखों को इकट्ठा किया गया था। सरी वही जगह है जहां इसी गुरुद्वारे के पूर्व अध्यक्ष और कनाडा में सिख फॉर जस्टिस तथा खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख चेहरा रहे हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

कनाडा की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के आह्वान पर एक लाख से अधिक लोग जनमत संग्रह में शामिल हुए। यह मतदान सरी के तमनवीस सेकेंडरी स्कूल में होना था, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा जनमत संग्रह से जुड़े पोस्टरों पर लगी एके 47 और कृपाण की तस्वीरें स्कूल अधिकारियों के ध्यान में लाए जाने के बाद इसे रद्द कर दिया गया। संगठित अपराध, ड्रग सिंडिकेट और मानव तस्करी के साथ खालिस्तानी ताकतों का गठजोड़ कनाडा के लिए भी चिंता का विषय हो सकता है। इनकी बढ़ती ताकत कनाडा की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकती है। खालिस्तानियों का विकास भले कनाडा-यूके में हो रहा है लेकिन उनकी जड़े भारत में हैं। इसलिए दोनों देश मिलकर इस अलगाववादी और हिंसक सोच को जड़ से खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जब जी20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत रवाना होने वाले थे, उसके कुछ दिन पहले, सरी में श्रीमाता भामेश्वरी दुर्गा मंदिर में भारत विरोधी और खालिस्तान समर्थक नारे लगाती हुई भीड़ ने तोड़फोड़ की। भारत की तरफ से कड़ा विरोध दर्ज कराने के बावजूद, कनाडा में खालिस्तानी समर्थक दीवारों पर नारों और पोस्टरों के जरिए पूरे कनाडा में भारतीय राजनयिकों और मंदिरों को निशाना बनाकर भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं। अधिक दिन नहीं हुए जब टोरंटो में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर खालिस्तानियों द्वारा किल इंडिया पोस्टर लगाया गया था। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक शोधपत्र में बताया गया है कि कनाडा और यूके जैसे देशों में जहां सिखों की संख्या अधिक है, वहां के गुरुद्वारों पर खालिस्तान समर्थकों का मजबूत नियंत्रण है। यही वजह है कि गुरुद्वारे के माध्यम से वे अपना प्रोपगेंडा आसानी से सिख समुदाय के बीच फैला देते हैं। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि गुरुद्वारा किसी भी सिख के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी सिख जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर बसा है, वह स्थानीय गुरुद्वारे के संपर्क में रहता है।

गुरुद्वारों पर खालिस्तानियों के नियंत्रण की वजह से ऐसा लगता है कि पूरा सिख समुदाय उनके समर्थन में खड़ा है। जबकि सच्चाई यह है कि खालिस्तानी इन गुरुद्वारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुरुद्वारों के जरिए उन्हें अपने उद्देश्य के लिए फंड मिलता है। अलगाववादी विचारधारा से जोड़ने के लिए लोग मिलते हैं। पिछले कुछ समय से ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है कि सेवा के नाम पर गुरुद्वारों में इकट्ठा किए गए पैसों का इस्तेमाल खालिस्तान समर्थकों ने अपने चरमपंथी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया है।

बढ़ती जा रही है ताकत

कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की राजनीतिक शक्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस बात का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 2018 में कनाडा की खुफिया रिपोर्ट में सूचीबद्ध शीर्ष के पांच आतंकवादी खालिस्तानी थे लेकिन ट्रूडो सरकार के भीतर सिख समुदाय के सांसदों की नाराजगी से बचने के लिए कनाडा सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादियों के मामले से किनारा कर लिया। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तानियों ने इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी निकाली। इस झांकी में ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 के सिख विरोधी दंगों के बैनर भी थे। भारत ने इस मामले पर अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त की लेकिन इससे खालिस्तानियों को कनाडा में कोई खास फर्क पड़ा नहीं। असल में कनाडा में 19 लाख भारतीय रहते हैं। उन 19 लाख भारतीय मूल के लोगों में करीब 50 प्रतिशत सिख हैं। ये सभी पंजाब से हैं। इस तरह कनाडा की राजनीति में पंजाब का दबदबा है। सिख वहां की राजनीति में खूब सक्रिय हैं।

खालिस्तान समर्थक ऐसे लोगों को अपने बीच पसंद नहीं करते जो उनसे सहमत नहीं हैं। रिपुदमन सिंह मलिक जिसकी पहचान एक खालिस्तानी की थी, पिछले साल जुलाई में उसकी हत्या कर दी गई थी। मलिक 1985 के एयर इंडिया बम विस्फोट मामले में नामजद आतंकी था। मलिक और दूसरे सह-अभियुक्त अजायब सिंह बागड़ी को वर्ष 2005 में इस मामले में बरी कर दिया गया था। मलिक की खालिस्तानी गतिविधियों की वजह से उसके भारत प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ था। सिख संगठनों के अनुरोध पर मोदी सरकार ने उसे 2020 में सिंगल एंट्री वीजा दिया। इसके बाद पिछले साल मल्टीपल वीजा दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि खालिस्तानियों ने उसकी हत्या की साजिश को अंजाम दिया क्योंकि वह भारत से अलग खालिस्तान देश बनाने के विचार के खिलाफ हो गया था। सिख समुदाय के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाने के लिए उसने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखा था। जिसके बाद से ही खालिस्तानी उसकी हत्या की ताक में थे। एसएफजे चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ऐलान किया है कि जो कोई भी दिल्ली पुलिस स्पेशल के अधिकारियों के इटली, यूके, कनाडा में रहने वाले रिश्तेदारों की पूरी जानकारी देगा, उसको इनाम दिया जाएगा। बता दें कि पुलिस की स्पेशल सेल ने पन्नू के स्लीपर सेल से जुड़े मॉड्यूल को 2 बार पकड़ा है। इस बात से वह थोड़ा अधिक ही परेशान चल रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि पन्नू द्वारा पंजाब को अस्थिर करने के चलते गृह मंत्रालय ने पहले ही एसएफजे को प्रतिबंधित संगठनों की सूची में डाला हुआ है। पन्नू पर भी इस समय यूएपीए लगा हुआ है और उसे डेजिग्नेटिड टेररिस्ट भी घोषित किया जा चुका है। पिछले दिनों पन्नू की अमेरिका में सड़क दुर्घटना में मौत की खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी लेकिन वह जिंदा निकला।

● **कुमार विनोद**

आधी आबादी का दिखेगा दम

मप्र में विधानसभा चुनाव की अधिकृत घोषणा अभी होना शेष है किंतु भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस तक ने आधी आबादी को अपने पक्ष में करने के लिए घोषणाओं के पिटारे खोल दिए हैं। और घोषणाएं भी क्यों न हों? आखिरकार मप्र में 48.20 प्रतिशत वोटर महिला हैं और यही आधी आबादी अब सत्ता बनाने और बिगाड़ने के खेल की वजीर बन गई हैं। एक ओर जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिलाओं के लिए लाड़ली बहना योजना लेकर मैदान में हैं, वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सत्ता में आने के बाद नारी सम्मान योजना लागू करने का वादा किया है। वर्तमान में प्रदेश की महिलाओं को लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत 1,000 रुपए दिए जा रहे थे, जिसे 10 अक्टूबर, 2023 से बढ़ाकर प्रतिमाह पहले 1,250 रुपए कर दिए गए और बाद में 1,600 रुपए करने की घोषणा की गई है। अंतत: प्रत्येक पात्र महिला को 3,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाने का प्रस्ताव है।

सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2023-24 में प्रदेश की भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के मद के लिए कुल 1 लाख 2 हजार 976 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जिसके अंतर्गत लाड़ली बहना योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 660 करोड़ रुपए, लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए, कन्या विवाह एवं निकाह योजना के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा शिवराज सरकार ने महिलाओं को सावन में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा भी किया गया है जिसके अंतर्गत सरकार गैस एजेंसियों से जानकारी लेकर महिलाओं के खाते में 600 रुपए ट्रांसफर करेगी।

वहीं कांग्रेस के 11 वचन वाले चुनावी घोषणा पत्र को देखें तो उसमें भी आधी आबादी को खासा महत्व दिया गया है। 27 अगस्त, 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार बनने पर महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, मुफ्त स्कूली शिक्षा जैसे वादे किए हैं। राजनीतिक शक्ति के तीसरे केंद्र के रूप में स्वयं को स्थापित करने में जुटी आम आदमी पार्टी भी महिलाओं को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। प्रदेश में पार्टी की एकमेव महापौर भी महिला हैं, अत: उनका चेहरा आगे कर महिलाओं को जोड़ने की कवायद जारी है। इन सबके अलावा पुलिस और दूसरी भर्तियों में महिलाओं का आरक्षण 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करना, शिक्षकों के पदों पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण, बहनों की स्कूल फीस माफ, पात्र महिलाओं को आजीविका मिशन के माध्यम से लोन जैसे वादों ने राजनीति में बढ़ती महिला वोट की ताकत का एहसास करवा दिया है।

दरअसल, बीते दशकों से महिलाओं के वोटों ने कई सरकारों को बनाया-बिगाड़ा है। राजनीतिक गुणा-भाग में अपना आर्थिक व घरेलू हित ढूंढती महिलाओं में अब जागृति आई है और कौन-सा राजनीतिक दल उन्हें लाभ देने के साथ ही उनकी किचन का आर्थिक भार कम कर रहा है, उन्हें बखूबी समझ में आ रहा है। वे मतदान के दिन घर की देहरी लांघकर अपनी हितैषी सरकार चुन रही हैं। मप्र की ही बात करें तो चुनाव आयोग के अनुसार, प्रदेश में 5.39 करोड़ मतदाता हैं जिनमें से 2.60 करोड़ यानी 48 प्रतिशत से अधिक महिला मतदाता हैं। पिछले पांच वर्ष में प्रदेश में 35 लाख से अधिक मतदाता बढ़े हैं जिनमें 19 लाख महिला मतदाता हैं। वहीं प्रदेश के 40 जिले तो ऐसे हैं जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है।

चुनाव आयोग के अनुसार, 2013 के विधानसभा चुनाव में 70 प्रतिशत महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था जबकि 2018 में यह आंकड़ा बढ़कर 74 प्रतिशत हो गया है, जिससे स्पष्ट है कि महिलाएं इस बार भी बढ़-चढ़कर मतदान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगी। इन सबसे इतना तो तय है कि राजनीतिक दल भले ही महिलाओं को टिकट देने के मामले में कंजूसी बरतें, 33 प्रतिशत आरक्षण पर कन्नी काटें, लेकिन वोटों के लिए उनकी अनदेखी तो नहीं कर सकते। हाल ही में, रक्षाबंधन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की छूट महिलाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करने का उपक्रम है। कुछ ऐसा ही वादा विपक्षी दलों का गठबंधन भी कर रहा है। राजस्थान में तो गहलोत सरकार ने 500 रुपए में सिलेंडर देना भी शुरू कर दिया है गोयाकि महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी दलों के बीच एक होड़ लगी है।

● **ज्योत्सना**

महिलाओं की राजनीतिक चेतना बढ़ी

नवंबर, 2021 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा था कि भारतीय लोकतंत्र ने पहले लोकसभा चुनावों के बाद से एक उल्लेखनीय दूरी तय की है और आज सात दशक और 17 आम चुनावों के बाद, मताधिकार का प्रयोग करने में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक हो गई है। उन्होंने यह भी इंगित किया कि भारत में 1971 के चुनावों के बाद से महिला मतदाताओं में 235.72 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि देखी गई है। उनके अनुसार, 2019 के आम चुनाव में अलग महिला बूथ स्थापित किए गए और 27,527 ऐसे बूथ महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए, जहां मात्र महिलाओं ने मतदान किया। महिलाओं के बढ़ते मत प्रतिशत के बाद एक प्रश्न भी उठता है कि क्या महिलाओं की राजनीतिक चेतना वास्तव में बढ़ी है? क्या राजनीति ने उन्हें उचित हिस्सेदारी दे दी है? इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिहेवियरल सोशल एंड मूवमेंट साइंस में छपे एक अध्ययन के अनुसार, यद्यपि महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है किंतु महिला उम्मीदवारों की संख्या अभी भी निराशाजनक ही है। राजनीतिक दल भी महिलाओं को बराबरी का मौका देने का दिखावा करते हैं जबकि उन्हें मत मिलने के अनुपात में उन्हें राजनीतिक रूप से अवसर भी देना चाहिए। बढ़ती राजनीतिक समझ और पंचायत चुनाव में प्राप्त आरक्षण ने महिलाओं को राजनीतिक रूप से अधिक मुखर कर दिया है जिसके चलते सभी राजनीतिक दल उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हैं। इसके लिए राजनीतिक दलों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ महिलाओं के जरिए पूरे परिवार को मिल रहा है।

देवी आराधना का महापर्व नवरात्रि

नवरात्रि का अर्थ है नौ रातें। नव का अर्थ है नौ और रात्रि का अर्थ है रात। रात्रि आराम और ताजगी प्रदान करती है। रात के दौरान, आप नींद के माध्यम से अंदर की ओर मुड़ते हैं, और सुबह आप तरोताजा और आराम महसूस करते हुए उठते हैं। उसी तरह, नवरात्रि या नौ रातें साल का वह समय होता है जब आपको गहन विश्राम का अनुभव करने का मौका मिलता है। यह गहन विश्राम सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति, गहन विश्राम और रचनात्मकता लाता है।

देवी सर्वव्यापी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। संपूर्ण सृष्टि इसी ऊर्जा से व्याप्त है। हम अपने दैनिक जीवन में जिस समृद्धि का आनंद लेते हैं वह देवी की अभिव्यक्ति है। देवी मां अनेक रूपों में हमारी सेवा करती हैं। हमारे माता, पिता, मित्र, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री और गुरु के भी रूप। घूमते ग्रह और चंद्रमा देवी हमारी आरती कर रहे हैं। पूजा के माध्यम से हम कहते हैं, हे मां, तुम मुझे जो भी दो मैं तुम्हें वापस देता हूं। उदाहरण के लिए, पूजा के दौरान, हम देवी को अनाज चढ़ाते हैं क्योंकि प्रकृति हमें भोजन प्रदान करती है। देवी पूजा संपूर्ण सृष्टि के प्रति श्रद्धा दिखाने वाली विस्तारित चेतना की अभिव्यक्ति है। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान हम जो पूजा करते हैं वह देवी का सम्मान करने और देवी मां के प्रति अपना आभार व्यक्त करने का एक तरीका है।

नवदुर्गा और नवरात्रि के प्रत्येक दिन का महत्व- देवी की पूजा 9 रूपों में की जाती है जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के प्रत्येक दिन का महत्व देवी मां के एक रूप से जुड़ा हुआ है।

पहला दिन-शैलपुत्री- पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस रूप में देवी पार्वती को राजा हिमालय की पुत्री के रूप में पूजा जाता है। शैला का अर्थ है असाधारण या महान ऊंचाइयों तक पहुंचना। देवी द्वारा प्रस्तुत दिव्य चेतना हमेशा शिखर से उभरती है। नवरात्रि के इस पहले दिन, हम देवी शैलपुत्री को प्रसन्न करते हैं ताकि हम भी चेतना की उच्चतम अवस्था प्राप्त कर सकें।

दूसरा दिन-ब्रह्मचारिणी- दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न किया जाता है। देवी ब्रह्मचारिणी देवी पार्वती का ही रूप हैं जिसमें उन्होंने भगवान शिव को अपनी पत्नी के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। ब्रह्म का अर्थ है दिव्य चेतना और आचार का अर्थ है आचरण। ब्रह्मचर्य वह व्यवहार या कार्य है जो दिव्य चेतना में स्थापित होता है। यह दिन विशेष रूप से ध्यान करने और अपनी आंतरिक दिव्यता का पता लगाने के लिए पवित्र है।

तीसरा दिन-चंद्रघंटा- तीसरे दिन की अधिष्ठात्री देवी चंद्रघटा हैं। चंद्रघटा वह विशेष रूप है जिसे देवी पार्वती ने भगवान शिव के साथ अपने विवाह के समय धारण किया था। चंद्र का तात्पर्य चंद्रमा से है। चंद्रमा हमारे मन का प्रतिनिधित्व करता है। मन बेचैन रहता है और एक विचार से दूसरे विचार की ओर घूमता रहता है। घंटा एक ऐसी घंटी है जो सदैव एक ही प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है। महत्व यह है कि जब हमारा मन एक बिंदु यानी दिव्य पर स्थापित होता है, तो हमारा प्राण (सूक्ष्म जीवन शक्ति ऊर्जा) समेकित हो जाता है जिससे सद्भाव और शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार यह दिन मन की सभी अनियमितताओं से दूर होकर, केवल देवी मां पर ध्यान केंद्रित करने का प्रतीक है।

चौथा दिन-कुष्मांडा- चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कुष्मांडा का अर्थ है कद्दू। कू का अर्थ है छोटा, ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा और अंडा का अर्थ है अंडा। ब्रह्मांडीय अंडे (हिरण्यगर्भ) से उत्पन्न यह संपूर्ण ब्रह्मांड देवी की एक अनंत ऊर्जा से प्रकट हुआ है। कद्दू भी प्राण का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि इसमें प्राण को अवशोषित करने और प्रसारित करने का अनूठा गुण है। यह सबसे प्राणिक सब्जियों में से एक है। इस दिन, हम देवी कुष्मांडा की पूजा करते हैं जो हमें अपनी दिव्य ऊर्जा प्रदान करती हैं।

पांचवां दिन-स्कंदमाता- स्कंदमाता का अर्थ है स्कंद की माता। पांचवें दिन, देवी पार्वती के मातृ स्वरूप की पूजा की जाती है। इस रूप में वह भगवान कार्तिकेय की माता हैं। वह मातृ स्नेह (वात्सल्य) का प्रतिनिधित्व करती हैं। देवी के इस रूप की पूजा करने से प्रचुर ज्ञान, धन, शक्ति, समृद्धि और मुक्ति मिलती है।

छठा दिन-कात्यायनी- छठे दिन, देवी कात्यायनी के रूप में प्रकट होती हैं। यह वह रूप है जिसे देवी मां ने ब्रह्मांड में राक्षसी शक्तियों का विनाश करने के लिए धारण किया था। उनका जन्म देवताओं के क्रोध से हुआ था। उन्होंने ही महिषासुर का वध किया था। हमारे शास्त्रों के अनुसार धर्म का समर्थन करने वाला क्रोध स्वीकार्य है। देवी कात्यायनी, देवी मां के उस दिव्य सिद्धांत और स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती हैं जो प्राकृतिक आपदाओं और आपदाओं के पीछे है। वह क्रोध है जो सृष्टि में संतुलन स्थापित करने के लिए उत्पन्न होता है। हमारे सभी आंतरिक शत्रुओं को समाप्त करने के लिए छठे दिन देवी कात्यायनी का आव्हान किया जाता है जो आध्यात्मिक विकास के मार्ग में बाधा हैं।

सातवां दिन-कालरात्रि- सातवें दिन, हम देवी कालरात्रि का आव्हान करते हैं। प्रकृति की दो चरम सीमाएं हैं। एक भयानक और विनाशकारी है। दूसरा सुंदर और शांत है। देवी कालरात्रि देवी का उग्र रूप हैं। कालरात्रि अंधेरी रात का प्रतिनिधित्व करती है। रात को देवी मां का एक पहलू भी माना जाता है क्योंकि यह रात ही है जो हमारी आत्मा को सांत्वना, आराम और सुकून देती है। केवल रात में ही हमें आकाश में अनंत की झलक मिलती है। देवी कालरात्रि वह अनंत अंधकारमय ऊर्जा हैं जिनमें असंख्य ब्रह्मांड स्थित हैं।

आठवां दिन-महागौरी- देवी महागौरी वह हैं जो सुंदर हैं, जीवन में गति और स्वतंत्रता देती हैं। महागौरी प्रकृति के सुंदर और शांत पहलू का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह ऊर्जा है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है और हमें मुक्त भी करती है। वह देवी हैं जिनकी पूजा आठवें दिन की जाती है।

नौवां दिन-सिद्धिदात्री- नौवें दिन, हम देवी सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। सिद्धि का अर्थ है पूर्णता। देवी सिद्धिदात्री जीवन में पूर्णता लाती हैं। वह असंभव को संभव बनाती है। वह हमें समय और स्थान से परे के दायरे का पता लगाने के लिए हमेशा तर्कशील तार्किक दिमाग से परे ले जाती है।

● **ओम**

एक रोटी और

सुमि रोटी बना रही थी उसने सबको आवाज दी चलो खाना बन गया। सब टेबिल पर आ गए। लंच का समय था, आज रविवार था सब साथ बैठकर खा रहे थे। सम्मिलित परिवार की बात ही कुछ और होती है पर बंदिशें भी होती हैं। सुमि की शादी को कुछ ही समय बीता था। घर में जेठानी, सास, ननद सभी तो थे, फिर भी कभी-कभी अकेला पन उसे घेर लेता था। सब खाना खा चुके थे। वह और उसकी जेठानी खाना खाने बैठी, पर वह अतीत की यादों में खो गई। उसका स्कूल से दोपहर को घर आना उस समय चूल्हे पर रोटी बनती थी। उसकी भाभी जो उसकी मां की तरह थी उम्र में उससे बहुत बड़ी थी। वह उसका इंतजार करती थी कि कब मैं आऊं और वह गर्म गर्म रोटियां खिलाए। वह भी चूल्हे के पास बैठकर स्कूल की सारी शैतानियां सुनाते- सुनाते खाना खाती थी। उसे तो पता भी नहीं लगा कि वह कब बड़ी हो गई, आकर भाभी से लिपटकर रोने लगी मां से डर लगता था। भाभी ने बड़े प्यार से समझाया सारी बातें जो आज टीवी के माध्यम से छोटी उम्र की लड़कियां भी जानती हैं पर भटक भी जाती हैं, क्योंकि वह मेरी हितैषी और मार्गदर्शक थी। नियति का खेल देखो उन्हें एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया और वह सबको रोता बिलखता छोड़ कर चली गईं पर नहीं गई तो एक याद। आज 28 साल बाद जब भी मैं दोपहर का खाना खाने बैठती हूं तो सोचती कोई मुझसे कहे एक गर्म रोटी और लेलो अरे बहुत छोटी सी बनाई है, पर कोई कहने वाला नहीं होता।

- डॉ. मधु आंधीवाल

अंतिम विदाई

आज घर की दहलीज छोड़ते हुए सुमित्रा की आंखें मानो पथरा गई हैं। आंखों से उसके आंसू का एक कतरा तक न निकला...! जिंदगी के जिन लम्हों के लिए लड़की लाखों सुनहरे सपने संजोए रहती है, वो सपने तो कब के मिट्टी में मिल गए।

अभी मां-पिताजी के चिता की आग ठंडी भी पड़ी नहीं थी कि भाई-भाभी ने एक साठ साल के बुड्ढ़े के साथ उसकी शादी तय कर दी। वैसे उसकी उम्र भी कमसिन नहीं थी, लेकिन एक बूढ़ा उसका जीवन साथी बने उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसे अपनी शादी की विदाई अपनी अंतिम विदाई के जैसी लग रही थी...!

- विभा कुमारी नीरजा

दीपक की ललकार

तुम दैदीप्यमान चमकती
अनुपम वाटिका,
मैं नन्हा सा दीपक हूं
मटमैली माटी का।

तुम आए तो प्रभात लाए,
अलख जगाया धरती का,
हम कवि हैं उपमा पाए,
तब गुब्बारा फूला छाती का।

तुम अस्ताचल का साथ छोड़,
निद्रा का दामन देते हो,
मैं लपलपाती ज्योति देकर
मार्ग बन जाता साथी का।

तुम अचल अविरल अक्षर हो
हर पाटी का,
मैं नन्हा सा दीपक हूं
मटमैली माटी का।

तुम आए तो खेतों में,
लख बरसता सोना ही,
श्रम के कण में दीप सा,
चमकता देह का कोना ही,

तब मेरे आगोश में बैठ,
चैन की चंद सांसें लेता,
वह कृषक भरता दम हुक्के का,
लगता मुझको बौना ही।

तुम बन जाते श्रृंगार
अनुपम हर दुर्गम घाटी का,
मैं नन्हा सा दीपक हूं,
मटमैली माटी का।

माना तेरे आने से,
मेरा एहसास भुलाया जाता है,
तेरी तपिश में जलकर,
खुद को छुपाया जाता है,

तब तमस के दामन में,
मेरा सहवास उनको भाता है,
तू निर्विकार सत्य है,
तो है मेरा भी एकाकी से नाता है,

तेरी पूजा आराधना करें,
हर जन सृष्टि का,
मैं नन्हा सा दीपक हूं,
मटमैली माटी का।

- नरेंद्र परिहार

खेल महाशक्ति बनता भारत

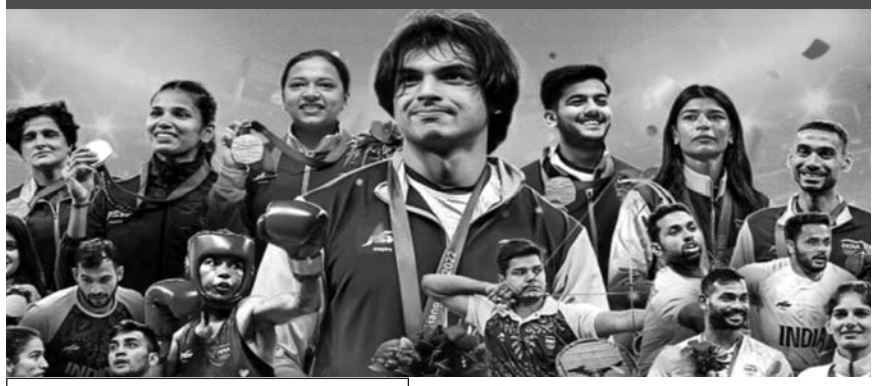

इरादे अगर मजबूत और बुलंद हों तो मंजिल जरूर मिलती है। भारतीय दल चीन के हांगझोउ में आयोजित 19वें एशियन गेम्स में बुलंद इरादों के साथ आया और नायाब इतिहास रच डाला। भारत का इस बार एशियन गेम्स में 100 पार का लक्ष्य था, जो उसने हासिल कर लिया। भारत ने 107 मेडल के साथ अपना अभियान खत्म किया। भारत ने 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। भारत एशियन गेम्स के 72 साल के इतिहास में पहली बार 100 पदक का आंकड़ा छुआ है। भारत ने इससे पहले एशियन गेम्स के एक संस्करण में सर्वाधिक पदक 5 साल पहले जीते थे। भारत ने जकार्ता एशियन गेम्स 2018 में 70 मेडल अपने नाम किए।

भारत ने हांगझोउ एशियन गेम्स में सर्वाधिक मेडल एथलेटिक्स में हासिल किए। भारत ने एथलेक्टिस में 6 गोल्ड, 14 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज सहित कुल 29 मेडल जीते। वहीं, भारत ने शूटिंग में 22 मेडल जीते, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज हैं। बता दें कि भारत की महिला और पुरुष क्रिकेट टीम ने गोल्ड अपने नाम किया। भारत को 41 साल बाद घुड़सवारी में गोल्ड मिला, जो ड्रेसाज इवेंट में आया। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारत से आगे दक्षिण कोरिया और जापान हैं, जो अब तक क्रमश: 183 और 177 मेडल पर कब्जा जमा चुके हैं। मेजबान चीन टॉप पर है, जिसके खाते में 360 से अधिक मेडल हैं। कभी भारत हॉकी की महाशक्ति था। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था और ओलंपिक दर ओलंपिक भारत जीत दर्ज करता जा रहा था। फिर आया क्रिकेट का दौर और उस समय ऐसा लगा कि भारत केवल क्रिकेट ही खेलना जानता है, लेकिन आज का दौर अलग है। नीरज चोपड़ा हों, साक्षी मलिक हों या पारुल चौधरी, एथलेटिक्स से लेकर भाला फेंक और कुश्ती से लेकर लंबी कूद तक में भारत के खिलाड़ी अपनी पहचान छोड़ रहे हैं। चीन में आयोजित एशियाड में इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है।

उप्र की पारुल चौधरी से जब पत्रकारों ने पूछा कि लंबी दूरी की दौड़ में वह इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर पाई, तो उसका मासूम सा जवाब था कि उप्र सरकार की नई नीति में विश्व चैंपियन खिलाड़ियों को सीधा डीएसपी बनाते हैं और मुझे वही चाहिए था, इसलिए स्वर्ण से नीचे समझौते की वजह नहीं थी। मेरठ की पारुल और अन्नू चौधरी ने एशियाड में इतिहास रच दिया है। पारुल ने भले ही भोलेपन में यह जवाब दिया है, लेकिन इतना तो तय है कि सरकारी प्रोत्साहन ने खेलों के लिए युवाओं-युवतियों में रुझान जगाया है। 1951 से खेले जा रहे इन खेलों में पहली बार भारत पदकों का शतक लगाएगा। हालांकि, चीनी अंपायरों के पक्षपात की भी खबरें आईं, इसके बावजूद भारतीय खिलाड़ी पूरी खेल भावना के साथ अपना उच्चतम प्रदर्शन कर रहे हैं।

भारत का एशियन गेम्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन

एशियन गेम्स का आगाज 1951 में हुआ था और इस बार 51 पदक भारत के खाते में थे। इसके बाद अगले कई सालों तक भारत इस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया और साल 1982 में कुल 13 गोल्ड के साथ 57 पदकों तक अपना आंकड़ा पहुंचाया। इस प्रदर्शन को भी टीम बरकरार नहीं रख पाई और 2006 में फिर से पदकों की फिफ्टी लगाई। 2010 में पहली बार 60 पदकों का आंकड़ा पार करते हुए टीम 65 तक पहुंची। 2014 में टीम को एक बार फिर से 56 पदक मिले। 2018 में भारतीय दल ने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए पहली बार 70 पदकों का आंकड़ा छुआ। यह भारतीय टीम का एशियन गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था। कमाल की बात अपने लगातार तीसरे खेल में भारत का प्रदर्शन बेहतर और बेहतर हो गया। अब 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने मेडल की संख्या 107 पर पहुंचाकर पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले।

पिछले 8 साल में मोदी सरकार ने खेलों का बजट बढ़ाया है, खेलों को रोजगार से जोड़ा है और नई शिक्षा नीति में खेलकूद बाकायदा एक विषय के तौर पर पढ़ाए जाने वाला है। जब कोई खिलाड़ी बनता है, तो वह केवल एक रोजगार नहीं पैदा करता है, बल्कि फिजियो, खेल के साजोसामान, उनसे जुड़े तमाम तरह के रोजगार को पैदा करता है। पिछले 8 वर्षों में देश का खेल-बजट 70 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। वहीं, जहां पहले भारत के खिलाड़ी कुछ ही खेलों में यानी 25-30 खेलों में 100 से भी कम अंतरराष्ट्रीय स्पर्द्धा में हिस्सा लेते थे, अब भारतीय खिलाड़ी 40 खेलों में 300 से अधिक खेलों में हिस्सा लेने जाते हैं। एशियाड से पहले भारत ने टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन किया। भारत 20वीं सदी की शुरुआत यानी 1900 ईस्वी से ओलंपिक में हिस्सा लेता रहा है और उसने टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक अपने नाम किए, यह भारतीय खिलाड़ियों का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था।

भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक खेलों में पूरे चार दशक बाद कोई पदक जीता और 41 साल के बाद पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं नीरज चोपड़ा पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने ओलंपिक की एथलेटिक्स स्पर्धा में अपने देश भारत को पदक दिलवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खेलों पर विशेष ध्यान है और भारत ने अभी ही से अगले ओलंपिक की तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय खेल प्राधिकरण की तरफ से 21 खेलों के लिए 398 कोच की तैनाती की गई है। इनमें कई पूर्व अंतरराष्ट्रीय एथलीट हैं, कई अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं, जो अपने-अपने क्षेत्र के विजेता हैं। उनमें से कई विश्व चैंपियनशिप हैं या ओलंपिक विजेता हैं या उसमें हिस्सा लिया है।

इस बार के एशियाड को मिलाकर यह 7वीं बार है, जब भारत ने 50 से अधिक पदक जीते हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी जीते हुए खिलाड़ियों से बात करने के अलावा जो हारे हुए खिलाड़ी हैं, उनसे खासतौर पर बात करते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं। सरकार खेलों को रोजगार से जोड़ रही है और खेलो इंडिया अभियान के तहत तमाम मंत्री और नेता छोटे-छोटे कस्बों, शहरों और जगहों पर भी खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। गांवों और कस्बों में खेल के बुनियादी ढांचे के उपलब्ध होने से प्रतिभाओं की बहुत जल्द पहचान हो रही है और उन जगहों से भी खिलाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। जिस एथलेटिक्स में कभी हमारा कोई नामलेवा नहीं था, वहीं अब हम स्वर्ण-रजत जीत रहे हैं। 2024 और 2028 के ओलंपिक को लेकर भी अब तैयारियां पूरे तरीके से चल रही हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि ओलंपिक में भी भारत अपना तिरंगा इसी तरह ऊंचा लहराएगा।

● आशीष नेमा

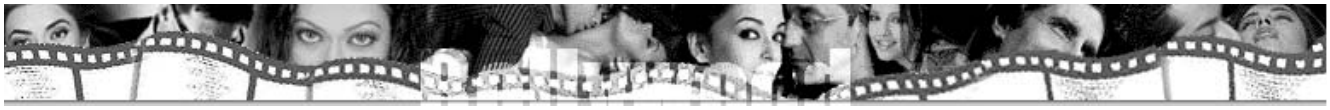

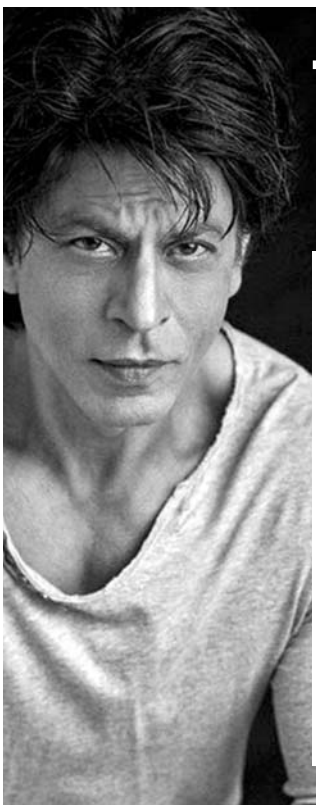

सड़क पर सोया, स्कूल से भी निकाला गया, अब है 6000 करोड़ की संपत्ति का मालिक

शाहरुख खान को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का बादशाह कहा जाता है। एक फिल्मफेयर के साथ इंटरव्यू में शाहरुख खान ने अपने उन दिनों को याद किया जब फीस का भुगतान न कर पाने के कारण उन्हें स्कूल से लगभग निकाल दिया गया था।

स्कूल की घटना को याद कर अभिनेता ने कहा था, मुझे पैसे के बारे में बात करने से नफरत है। मुझे इससे नफरत है। मैंने एक साम्राज्य बनाया है लेकिन मैं पैसे के बारे में बात नहीं कर सकता। मेरे लोगों ने मुझे बताया कि अगर मैंने पैसे मांगे होते तो यह साम्राज्य 10 गुना बड़ा होता। लेकिन मुझे पता है, अगर मैंने पूछा होता, तो यह 10 गुना छोटा होता। यह अहंकारी लग सकता है लेकिन राजा नहीं पूछते। भले ही मीडिया मुझे किंग कहे, मैं इस पर विश्वास करता हूं और इसीलिए मैं नहीं पूछता। दरिद्र राजा भी कभी नहीं पूछेगा। यदि लोग उससे कुछ मांगें तो वो अपना मांस और खून दे देगा। मैं एक गरीब परिवार से हूं। शाहरुख ने कहा, मैं सभी यंग एक्ट्रेसेस से कहता हूं कि प्लीज एक घर खरीदें। मुझे खुशी होती है जब वे आती हैं और मुझे बताती हैं कि उन्होंने एक घर खरीदा है। मन्नत के लिए लोग मुझे हमेशा याद रखेंगे। यह मेरी अन्य उपलब्धियों को कमतर करता है लेकिन यह ठीक है। आपके घर के अलावा, आपको जो कुछ भी मिलता है, वो वैल्यू एडिशन है। जैसा कि वे कहते हैं, यदि आप चांदी की थाली में खाएंगे तो आप पैसे नहीं खाएंगे और भोजन का स्वाद भी बेहतर नहीं होगा। मैं एक जैसा खाना खाता हूं, एक जैसे कपड़े पहनता हूं। मेरे पास चार जोड़ी जीन्स हैं। लोग मेरे बारे में कितना भी अलग सोचें, मैं बिल्कुल वैसा ही हूं जैसा 20 साल पहले था।

हेमा मालिनी ने जब संजीव कुमार को करवाया बाहर, शत्रुघ्न सिन्हा ने मारी बाजी, फिल्म ने कर डाली थी 5 गुना कमाई

बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया था। उन दिनों इंडस्ट्री में हेमा मालिनी का रुतबा कुछ ऐसा था कि उनके साथ फिल्म बनाने के लिए मेकर्स उनकी हर शर्त झट से मान जाते थे। ऐसे में हेमा जिसे चाहें उसे फिल्म से बाहर निकलवा देतीं थीं और जिसे चाहे उसे फिल्म में कास्ट करवा देती थीं।

ऐसा ही एक किस्सा साल 1974 में आई फिल्म दोस्त का है। इस फिल्म में धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा लीड रोल में नजर आए थे और दोनों ही एक्टर्स ने अपने अभिनय से खूब वाहवाही लूटी थी। अब शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस किरदार से शत्रुघ्न सिन्हा ने दर्शकों को अपने अभिनय का कायल बना लिया था, उस किरदार के लिए वह कभी भी मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे। पहले फिल्म में संजीव कुमार को कास्ट किया था, लेकिन हेमा के कहने पर एक्टर को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखाया गया।

दरअसल, उन दिनों पूरी इंडस्ट्री में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के अफेयर के किस्से चर्चित थे। वहीं संजीव कुमार ने ड्रीम गर्ल को शादी के लिए प्रपोज किया था जिसे एक्ट्रेस ने ठुकरा दिया था। यही कारण था कि हेमा मालिनी संजीव कुमार और धर्मेंद्र संग एक ही फिल्म में काम नहीं करना चाहती थीं।

शर्मिला टैगोर ने बिना हीरो के शूट किया गाना, 50 हफ्ते सिनेमाघर से नहीं उतरी फिल्म, साबित हुई कल्ट क्लासिक

साल 1969 में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की ब्लॉकबस्टर फिल्म आराधना रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। राजेश खन्ना के करियर के लिए तो ये फिल्म मील का पत्थर साबित हुई थी। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना ने एक से बढ़कर एक कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं।

फिल्म आराधना में राजेश खन्ना के अपोजिट नजर आ चुकीं शर्मिला टैगोर ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा करते हुए कहा था कि फिल्म के गाने सपनों की रानी इस फिल्म का हिट गाना था। लेकिन इस इस गाने की शूटिंग उन्हें अकेले ही करनी पड़ी थी। क्योंकि काका और सुजित कुमार दार्जीलिंग फिल्म की शूटिंग के लिए अकेले गए थे और एक्ट्रेस ने इस गाने के हिस्से के सीन स्टूडियो में ही शूट किए थे। उनका कहना है कि उन्होंने उस वक्त बहुत बड़ा समझौता किया था। अगर आज के दौर में ऐसा होता तो उन पर मुकदमा कर सकती थी। आराधना राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के करियर की बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री भी काफी पसंद की गई थी। इस फिल्म के बाद दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया था। एक वक्त ऐसा भी आया था जब इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म को बनाने से इनकार कर दिया था।

गधा विवाद में नहीं पड़ता

गधा कभी भी किसी बात को स्टेटस सिंबल नहीं बनाता। उसे आप किसी भी दिशा में धकेल दो, वह उसी तरफ चल देगा और कभी यह नहीं कहेगा कि उसे दक्षिण दिशा में मत मोड़ों क्योंकि दक्षिण पंथी विचारधारा उसे रास नहीं आती। गधे के ऊपर आप किसी भी विचारधारा का बैनर लटका दो, गधा कभी नाक भौं नहीं सिकोड़ेगा।

कई बार मुझे भाई लोगों की बात पर बहुत गुस्सा आता है। जब भी उनकी खोपड़ी घूमती है, किसी को भी गधा करार दे देते हैं। जैसे गधा, गधा न होकर दुनिया की सबसे मूर्ख शख्सियत हो। अरे भई, गधे की भी अपनी इमेज होती है, उसकी भी कोई बिरादरी होती है जहां उसने मुंह दिखाना होता है। उसके भी अपने इमोशन्स होते हैं। अब क्या हुआ जो गधा सबके सामने हंसता नहीं है, रोता नहीं है, मुस्कराता नहीं है, ईर्ष्याता नहीं है, घिघियाता नहीं है और न ही आंखे तरेर कर देखता है। अपनी भावनाओं पर काबू रखने में गधे का क्या कोई सानी है? नहीं न। तो फिर गधे को इतना जलील क्यों किया जाता है कि हर ऐरे-गैरे नत्थू-खैरे की तुलना उससे कर दी जाती है।

भाई लोग मेरी इस साफगोई का भले ही बुरा मानें लेकिन भाई मैं तो गधे के लिए अपने दिल में सॉफ्ट-कॉर्नर रखता हूं। उसकी इज्जत करता हूं। गधे को मैंने बहुत करीब से देखा है, जाना है। गधा एक ऐसा प्राणी है जिसका इस समाज को अनुसरण करना चाहिए, उसके पदचिन्हों पर चलना चाहिए। अब देखो न, गधा कभी बयान नहीं बदलता। अपने स्टैंड पर कायम रहता है। आस्थाएं भी नहीं बदलता। जिसके साथ खड़ा हो गया, दिलोजान से उसके साथ चलेगा। धांधलियों की शिकायत करने भी नहीं जाता। खोखले वायदे भी नहीं करता। नारे भी नहीं लगाता। उस पर सवार होकर कोई कितना भी क्यों न चीख-चिल्ला ले, गधे पर कोई असर नहीं पड़ता। उसकी सहनशक्ति गजब की है। क्या हम में से कोई इतनी सहनशक्ति का मालिक है?

आप गधे पर कोई भी निर्णय थोप दो। गधा कभी रियेक्ट नहीं करेगा। कोई ऐसा-वैसा इशारा भी नहीं करेगा जैसा ग्रैग चैपल ने कोलकाता में किया। गधा चुपचाप अपना गुस्सा पी जाएगा लेकिन विवाद खड़ा नहीं करेगा। वैसे भी विवाद खड़ा करके चर्चा में बने रहना गधे की आदतों में शुमार नहीं है। अगर विवाद ही खड़ा करना होता तो गधा भी तमिल अभिनेत्री खुशबू के उस बयान में अपनी हां मिला देता जो उसने शादी पूर्व सुरक्षित यौन संबंधों के हक में दिया था और सानिया मिर्जा की तरह अगले दिन अपने बयान से पलट जाता। कह देता कि मीडिया वालों ने बात को जरा तोड़-मरोड़ दिया।

गधा कभी भी किसी बात को स्टेटस सिंबल नहीं बनाता। उसे आप किसी भी दिशा में धकेल दो, वह उसी तरफ चल देगा और कभी यह नहीं कहेगा कि उसे दक्षिण दिशा में मत मोड़ों क्योंकि दक्षिण पंथी विचारधारा उसे रास नहीं आती। गधे के ऊपर आप किसी भी विचारधारा का बैनर लटका दो, गधा कभी नाक भौं नहीं सिकोड़ेगा। गधे के ऊपर आप किसी को भी बिठा दो, गधा कभी खुद को जलील महसूस नहीं करेगा। गधा उसी अलमस्त अंदाज में चलेगा जो अंदाज उसे पूर्वजों से विरासत में मिला है।

गधे की एक और खूबी यह भी है कि उसे दुनिया के किसी भी मसले से कोई लेना-देना नहीं है और न ही वह किसी मसले में अपनी टांग अड़ाता है। वह अमेरिका की तरह किन्हीं दो मुल्कों के पचड़े में नहीं पड़ता। न किसी की पीठ थपथपाता है और न किसी को धमकाता है। भारतीय क्रिकेट टीम की कमान किसको सौंपी गई है और किस प्रांत के खिलाड़ी को बाहर बिठाया गया है, गधे को इससे भी कोई लेना-देना नहीं है। गधा तो कभी यह राय भी जाहिर नहीं करता कि फलां खिलाड़ी लंबे अरसे से आऊट आफ फार्म चल रहा है, उसे टीम में क्यों ढोया जा रहा है? अगर मुल्क की टीम लगातार जीत रही हो तो गधा खुशी से बल्लियां नहीं उछालता और अगर टीम लगातार पिट रही हो तो गधा मैदान में पहुंचकर न तो मैच में विघ्न डालता है, न खाली बोतलें फेंकता है और न ही हाय-हाय के नारे लगाता है। गधा तो यह शिकायत भी नहीं करता कि अंपायर ने किसी खिलाड़ी को गलत आऊट दे दिया है, लिहाजा अंपायर को बाहर भेजा जाए और नया अंपायर लगाया जाए। कौन-सी टीम मैच जीतेगी और कौन खिलाड़ी सैंचुरी मारेगा, गधा इस बात पर कभी सट्टा भी नहीं लगाता।

गधा न तो धर्मांध है और न ही सांप्रादायिक। वह किसी मजहब विशेष का राग भी नहीं अलापता। मंदिर-मस्जिद के झगड़े में भी नहीं पड़ता। वह क्षेत्रवाद का हिमायती भी नहीं है। उसके लिए सारी धरा की घास बराबर है। गधे की इच्छाओं का संसार भी बहुत बड़ा नहीं है। उसे न तो मोबाईल चाहिए, न टेलीविजन, न गाड़ी-बंगला, न गनमैन और न ही किसी क्लब की मैंबरशिप। गधा पैग भी नहीं लगाता। उसे तो दो जून का चारा मिल जाए तो उसी में खुश रहता है। गधे में आपको और क्या-क्या खासियत चाहिए? गधा कभी-कभार दुलत्ती तो मारता है लेकिन किसी को गोली तो नहीं मारता, बम नहीं फोड़ता, बारूदी सुरंगें नहीं बिछाता, डकैती नहीं डालता, रिश्वत नहीं लेता, बूथ कैप्चरिंग नहीं करता, घोटाले नहीं करता, रात के अंधेरे में कोई ऐसे-वैसे काम भी नहीं करता। फिर गधे को इतना प्रताड़ित क्यों किया जाता है?

गधे पर मैंने कोई फोकट में रिसर्च नहीं की। कितने ही गधों की संगत करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि गधा अनुकरणीय तो है ही, प्रात: स्मरणीय भी है। गधे के अपने आदर्श हैं, अपनी फिलॉसाफी है, जिंदगी के अपने कुछ मापदंड हैं, सिद्धांत हैं। गधे को इज्जत देकर, उसका अनुसरण कर हम एक सभ्य समाज की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। हमारे इस कदम का गधा कतई बुरा नहीं मानेगा। जब तक गधे को महज गधा ही आंका जाएगा, तब तक न तो समाज का भला होने वाला है, न देश का, न दुनिया का और न भाई लोगों का।

● **गुरमीत बेदी**

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

BA200 LED TECHNOLOGY

BioSystems

The Highest Flexibility

Address : M-179, Gautam Nagar,
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

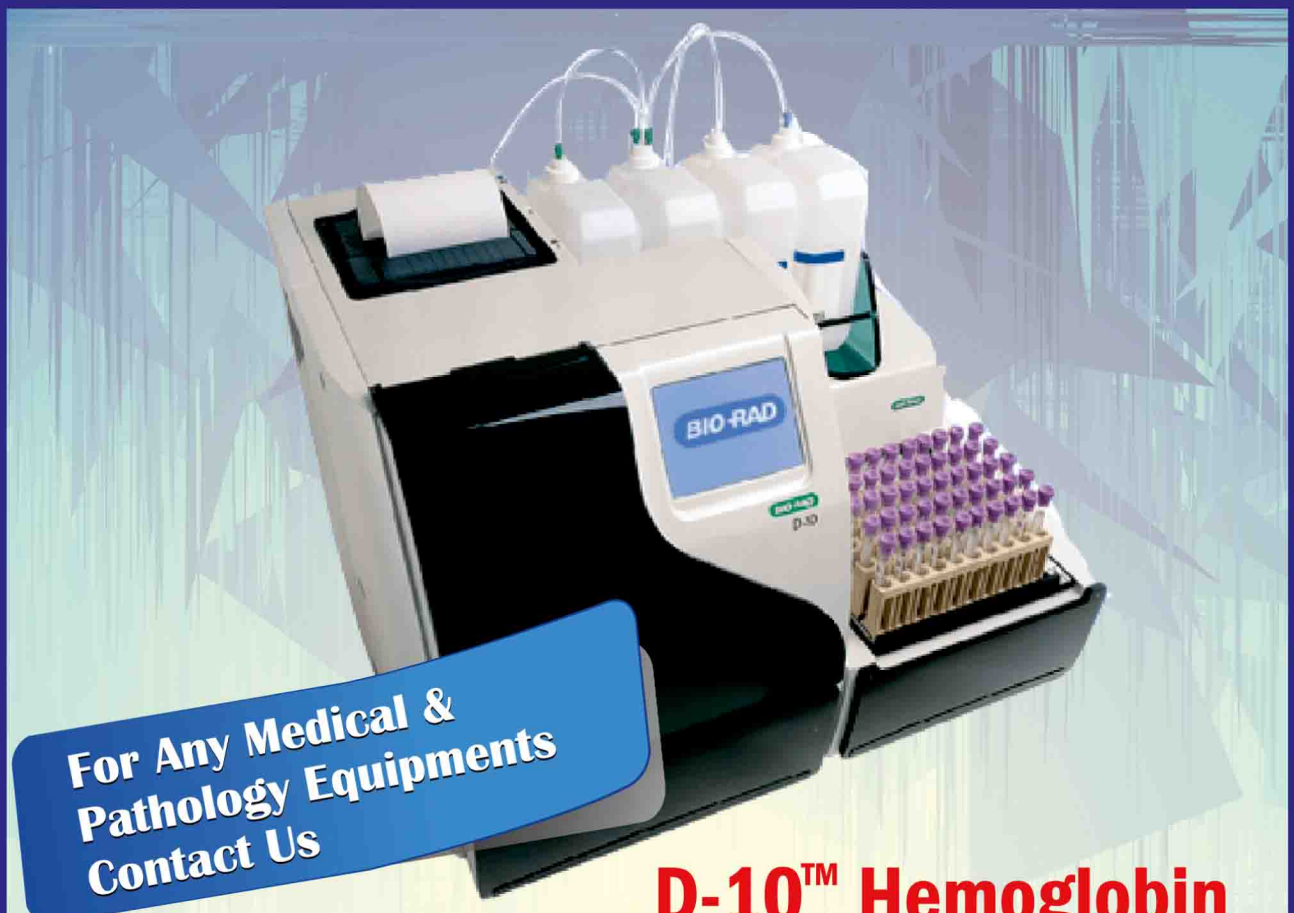

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687